वर्ष 12 • अंक 275 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

सोमवार 6 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

# बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 4

'अन्य' आयात के लिए लाइसेंसिंग पर विचार

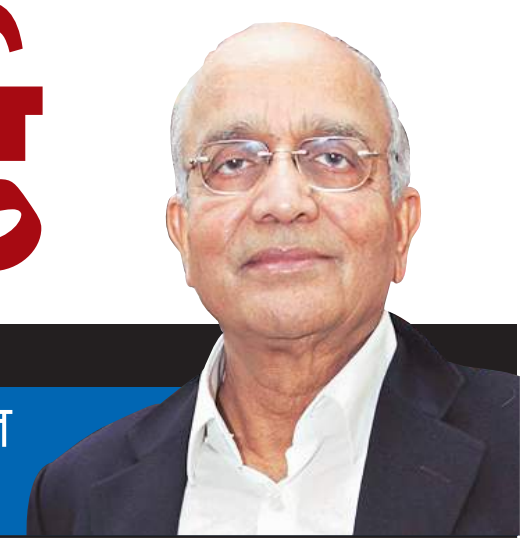

आर सी भार्गव ▶▶ पृष्ठ 2

लोगों में खरीदने की ताकत रही तभी बढ़ेगी कार बिक्री

## एक नज़र

### ज्यादा खर्च वालों के लिए नया आईटीआर

आय कर विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए दो आईटीआर फॉर्म आईटीआर-1-सहज और आईटीआर-4-सहज अधिसूचित किए हैं। बड़ी तादाद में उन लोगों को अनिवार्य रूप से रिटर्न फाइल करना होगा जिन्हें पहले ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी। साथ ही विभाग ने नकद जमा, विदेश यात्रा और बिजली पर होने वाले खर्च से संबंधित विवरणों का खुलासा भी अनिवार्य बनाया है। आईटीआर-1 सहज वेतन, एक मकान, ब्याज आय और पारिवारिक पेंशन आय आदि से कुल 50 लाख रुपये तक की सालाना आय कमाने वाले लोगों के लिए है। इस फॉर्म के लिए पासपोर्ट विवरण जरूरी होगा। पृष्ठ 4

### सुरक्षित पनाहगाहों में कई न्यासों पर जांच की आंच

भारत और स्विट्जरलैंड के कर अधिकारियों ने ऐसे न्यासों की पहचान की है, जो कर चोरी के लिए सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले देशों में स्थित निकायों का जाल बुनकर स्विस बैंकों में अवैध धन छिपाकर रखते हैं। ऐसे निकायों को स्विट्जरलैंड के कर प्राधिकरणों ने नोटिस जारी किए हैं। स्विट्जरलैंड के कर अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की बैंक जानकारियां भारत के कर अधिकारियों के साथ साझा कर रहे हैं, जो कर चोरी कर यहां से बाहर भाग गए। स्विट्जरलैंड के राजपत्र के अनुसार ऐसे कई व्यक्तियों के मैन आइलैंड्स स्थित न्यासों और कंपनियों को कहा गया है कि अगर वे भारत के साथ बैंक जानकारियां साझा करने के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो अपना प्रतिनिधि नामित करें।

### गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को भी देना होगा लेखा-जोखा

गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को भी सरकार के पास तिमाही या छमाही वित्तीय लेखा जोखा जमा कराना पड़ सकता है। सरकार इसके लिए कंपनी कानून में प्रावधान कर सकती है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। देश में 11 लाख से अधिक गैर-सूचीबद्ध कंपनियां परिचालन कर रही हैं। यह प्रस्ताव इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि कई बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को भी वित्तीय संकट से जूझना पड़ा है। फिलहाल इन कंपनियों को तिमाही अथवा छमाही आधार पर वित्तीय लेखा-जोखा सौंपने की जरूरत नहीं होती है।

### सुजलॉन के लिए एस्क्रो खाते की बैंकरों की योजना

कर्ज से लदी सुजलॉन एनर्जी के लिए लेनदारों ने एक समाधान योजना को अंतिम रूप दिया है। लेनदारों को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया माह के आखिर तक पूरी हो जाएगी, जो समाधान की समयसीमा भी है। सूत्रों ने कहा कि एक बैंक को छोड़कर सभी लेनदार कर्ज के 50 फीसदी से ज्यादा हिस्से को नए कर्ज में तब्दील करने के लिए तैयार हैं जबकि बाकी लेनदार बट्टे खाते में डाल देंगे। पृष्ठ 2

### आज का सवाल

क्या अमेरिकी-ईरान तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ाएगा मुश्किलें

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

**पिछले सवाल का नतीजा**

| क्या अमेरिकी हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ेगा तनाव | |
|---|---|
| हां | 77.78% |
| नहीं | 22.22% |

# न्यासियों की व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है जब्त

## वित्त विधेयक 2020 में सरकार कर सकती है इसका प्रावधान

**श्रीमी चौधरी**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

अगर कोई परोपकारी संस्था कर छूट या संस्थाओं के पंजीकरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके न्यासियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आम बजट में इसका प्रावधान किया जा सकता है।

सरकार के एक सूत्र ने कहा कि इसके लिए आय कर कानून में एक नया प्रावधान जोड़ा जा सकता है। इसके तहत अगर कोई पंजीकृत परोपकारी संस्था नियमों का उल्लंघन करती है तो अधिकारियों को उसके न्यासियों की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को जब्त करने का अधिकार दिया जा सकता है। टाटा ट्रस्ट्स का मामला सामने आने के बाद इस पर विचार किया जा रहा है।

अभी इस तरह के उल्लंघन के मामले में जिम्मेदारी ट्रस्ट पर ही होती है और न्यासियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नया प्रावधान वित्त विधेयक 2020 का हिस्सा हो सकता है। सूत्र ने कहा, 'सार्वजनिक ट्रस्ट काले धन को सफेद करने का सबसे आसान जरिया बन गए हैं क्योंकि उनके कामकाज पर बराबर नजर नहीं रखी जाती है।' उन्होंने कहा कि चूंकि इन ट्रस्टों को सही लोगों से चंदा मिलता है, इसलिए उनके प्रबंधकों से सवाल जवाब होना चाहिए और ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए।

सरकार साथ परोपकारी और गैर लाभकारी संस्थाओं के विदेशी चंदे की राशि भी सीमित करने पर विचार कर रही है। इसके तहत ये संस्थाएं अपनी कुल आय की 5 से 10 फीसदी राशि ही विदेशी चंदे के रूप में दे सकती हैं। अभी उनके लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है और अगर उनकी गतिविधियां आय कर कानून की धारा 11 (1) के तहत आती हैं तो वे कर छूट का दावा कर सकती हैं। हालांकि, कुछ परोपकारी ट्रस्ट इस श्रेणी में शामिल नहीं होने के बावजूद विदेशी चंदे पर छूट का दावा कर रही हैं।

साथ ही सरकार ने कर छूट का लाभ उठा रही परोपकारी संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर समान मौके देने के लिए राय मांगी है। एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें अपना निवेश निकालने के लिए तीन साल का समय दिया जा सकता है। अभी आय कर कानून में 1952, 1973 और 1982 में या इससे पहले किए गए निवेश के तौर तरीकों के लिए अलग-अलग तारीखों का प्रावधान है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि कई ऐसे ट्रस्ट हैं जिनके पास 1973 से पहले किया गया निवेश है। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे साबित हो कि यह निवेश ट्रस्टों की आय से 1973 में किया गया या उससे पहले। यह भी देखा गया है कि इन ट्रस्टों के कोष का इस्तेमाल उनमें बहुलांश हिस्सेदारी के जरिये अपने कारोबारी समूह की कंपनियों पर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है, न कि किसी परोपकारी उद्देश्य के लिए। रकम निवेश के लिए विभिन्न न्यासों को अलग-अलग रूपों एवं विधियों से रियायत उपलब्ध है, इसलिए उनके साथ होने वाले व्यवहार में भी भिन्नता होती है।

कर विशेषज्ञों के अनुसार इससे समीक्षा करना मुश्किल हो जाता है। इन बातों के मद्देनजर नियम समान किए जाने से सभी न्यासों को समान लाभ मिलेंगे। हाल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2019 की अपनी रिपोर्ट में कर प्रावधानों के तहत अनियमितताएं एवं रियायत के तरीकों की चर्चा की गई है। इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शुरू में रियातयत का दावा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि ट्रस्ट की प्रस्तावित गतिविधियां उन अंतरराष्ट्रीय पर उन परोपकारों को बढ़ावा नहीं दे रही है, जिनमें भारत की दिलचस्पी है।

### ... न्यासों पर अंकुश!

- नियमों के उल्लंघन की जिम्मेदारी न्यासियों पर
- टाटा के मामले के मद्देनजर सरकार उठा सकती है कदम
- आय कर कानून में किया जा सकता है प्रावधान
- आम बजट में आ सकता है नया प्रावधान

# टाटा समूह के चेयरमैन पद में दिलचस्पी नहीं

**बीएस संवाददाता**
मुंबई, 5 जनवरी

**टाटा** समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने आज कहा कि वह टाटा संस के अल्पांश शेयरधारक के रूप में शापूरजी पलौंजी समूह के अधिकारों को बचाने के लिए सभी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जिनमें बोर्ड में सीट का अधिकार भी शामिल है। लेकिन उनकी टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में बंबई हाउस में वापसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

शापूरजी पलौंजी समूह की टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में 18.5 फीसदी हिस्सेदारी है। मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। तभी से दोनों पक्षों में टकराव चल रहा है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने पिछले महीने मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन के रूप में बहाल करने का आदेश दिया था। मिस्त्री ने रविवार को कहा, 'पिछले तीन वर्षों के दौरान टाटा संस के नेतृत्व ने अपने आचरण और बयानों से अल्पांश शेयरधारकों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है। समूह के प्रबंधन को आत्ममंथन करना चाहिए और भविष्य के कामों में उनका यह आचरण दिखना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि वह एनसीएलएटी के आदेश के मुताबिक टीसीएस, टाटा टेलीसर्विसेज और टाटा इंडस्ट्रीज का निदेशक बनने के इच्छुक नहीं हैं। मिस्त्री ने कहा कि उनकी नजर टाटा संस के शीर्ष पद पर नहीं है लेकिन वह चाहते हैं कि कंपनी कॉरपोरेट प्रशासन और पारदर्शिता के उच्च मानकों का पालन करे।

मिस्त्री ने कहा कि रतन टाटा और एनसीएलएटी के आदेश पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों के हवाले से मीडिया में आई खबरों में कॉरपोरेट लोकतंत्र की व्याख्या एक ऐसे क्रूर बहुसंख्यकवाद के रूप में की गई है जिसमें अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं है। इस कानूनी कार्यवाही में सवाल यह है कि क्या बहुलांश शेयरधारक द्वारा अल्पांश शेयरधारकों का उत्पीडन न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

उन्होंने कहा कि भारत सहित पूरी दुनिया में कंपनी कानून अल्पांश शेयरधारकों के हितों की रक्षा और कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत करने के लिए विकसित हुए हैं। कंपनी कानून, 2013 ने बहुलांश शेयरधारकों के दमनकारी आचरण से अल्पांश शेयरधारकों को दी गई वैधानिक सुरक्षा को ज्यादा मजबूत किया है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि कॉरपोरेट लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

मिस्त्री ने कहा, 'टाटा समूह के संस्थापकों ने मजबूत नैतिक मूल्यों की नींव रखी थी जो सभी शेयरधारकों का ध्यान रखती थी। टाटा समूह और शापूरजी पलौंजी समूह के रिश्ते कई दशक पुराने हैं। टाटा के पुराने नेतृत्व ने सभी शेयरधारकों के हितों के लिए अल्पांश शेयरधारकों के साथ मिलकर काम किया था।' ■ संबंधित खबर पृष्ठ 2

### साइरस ने कहा...

- अल्पांश शेयरधारकों के हितों के संरक्षण की लड़ाई
- कॉरपोरेट प्रशासन और पारदर्शिता के उच्च मानकों का पालन करे टाटा संस
- टीसीएस, टाटा टेली और टाटा इंडस्ट्रीज का निदेशक बनने में दिलचस्पी नहीं
- मिस्त्री अक्टूबर 2016 में चेयरमैन पद से हुए थे बर्खास्त

# अमेरिका-ईरान से बाजार होंगे परेशान

**जश कृपलानी, अनूप राय और ऐश्ली कुटिन्हो**
मुंबई, 5 जनवरी

**अमेरिका** और ईरान में तनाव बढ़ने के बाद बाजार पशोपेश में नजर आ रहा है। ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर की हत्या के बाद वैश्विक स्तर पर उथल पुथल मची है और तनाव गहराने पर तेल कीमतें सरपट ऊपर भाग सकती हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं।

डॉयचे बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) कौशिक दास कहते हैं,'भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है और इसकी कीमतों में उतार-चढ़ावों का सीधा असर होगा। भू-राजनीतिक हालत बिगड़ने से रुपया गिरेगा और बॉन्ड पर प्राप्तियां भी बढ़ जाएंगी।' उन्होंने कहा कि एक बात तो तय है कि आने समय में अनिश्चितता चरम पर रहेगी।

ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में मौत के बाद शुक्रवार को कच्चा तेल 3.5 प्रतिशत उछलकर 68.96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। मुद्रा विनिमय बाजार पर नजर रखने वाले जानकारों के अनुसार आने वाले कारोबारी सत्रों में रुपया भी कमजोर पड़ सकता है। उनके अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) मुद्रा जोखिम से बचने के लिए भारी पैमाने पर बिकवाली कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा सलाहकार कंपनी आईएफए ग्लोबल में प्रबंध निदेशक अभिषेक गोयनका कहते हैं,'रुपये में अनिश्चितता ऐसे समय में एफपीआई का जायका खराब करेगी जब भारतीय बाजार को विदेशी निवेशकों की भागीदारी की दरकार है, खास बॉन्ड बाजार इनकी जरूरत महसूस कर रहा है। रुपया 72.75 के स्तर पर मध्यम अवधि में डॉलर-रुपया विनिमय दर के लिए प्रतिरोध के तौर पर काम करेगा।' जहां तक शेयर बाजारों की बात है तो एफपीआई के पीछे हटने की स्थिति में बड़े पैमाने पर बिकवाली दिख सकती है। ■ शेष पृष्ठ 12

■ खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच विदेशी निवेशक कर सकते हैं भारी बिकवाली

### बयानबाजी तेज

अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव के बीच रविवार को जुबानी हमले तेल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा आक्रामक कदम उठाने की स्थिति में अमेरिका उसके 52 ठिकानों पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ ईरानी सेना के प्रमुख ने कहा कि अमेरिका में युद्ध लड़ने का साहस नहीं है। इस बीच इराक के सांसद अमेरिकी सेना को अपने देश से बाहर करने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। इस विवाद का साया खाड़ी देशों के बाजारों पर भी देखा गया। ■ पृष्ठ 12

# 'आप' घोषणापत्र में कारोबारी सुझाव

**बीएस संवाददाता**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

**आम** आदमी पार्टी (आप) कारोबारियों के सुझावों को अपने घोषणापत्र में शामिल करेगी। इसके लिए पार्टी ने 'फंड रेजिंग डिनर' कार्यक्रम में कारोबारियों से सुझाव मांगे हैं। आप व्यापारी शाखा (ट्रेड विंग) की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कारोबारियों से 1.5 करोड़ रुपये चंदा इकट्ठा हुआ।

आप ट्रेड विंग की दिल्ली इकाई के महासचिव विष्णु भार्गव ने बताया कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के लिए चंदा जुटाने के लिए विंग और कारोबारियों ने शनिवार देर रात तक फंड रेजिंग डिनर पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, सुशील गुप्ता, पंकज गुप्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सिसोदिया ने पिछले पांच वर्षों में कारोबारियों के हित में किए कार्य गिनाए गए और आगे कारोबारियों की समस्याओं को सुलझाने का भरोसा दिया गया।

सिसोदिया ने कारोबारियों से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बनने वाले घोषणापत्र में अपने सुझाव देने की अपील की और कहा कि कारोबारियों के इन सुझावों को घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा। भार्गव ने कहा कि विंग जल्द ही कारोबारियों से सुझाव लेकर पार्टी को सौंपेगी। कारोबारियों के सुझावों में फायर एनओसी का सरलीकरण, लंबित वैट मामलों के निपटारे के लिए वैट एमनेस्टी स्कीम, फैक्टरी लाइसेंस का खात्मा, सीलिंग, जीएसटी संबंधी समस्याओं समाधान आदि कारोबारी मुद्दे शामिल होंगे। भार्गव ने कहा कि फंड रेजिंग डिनर कार्यक्रम में कारोबारियों से 1.5 करोड़ रुपये जुटाए गए। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो आप ट्रेड विंग ऐसे और कार्यक्रमों का आयोजन किए जाएंगे।

- कारोबारियों के साथ फंड रेजिंग कार्यक्रम में सिसोदिया ने मांगे सुझाव
- आप ने 'फंड रेजिंग डिनर' से कारोबारियों से जुटाया 1.5 करोड़ रुपये चंदा
- राजनाथ सिंह सोमवार को करेंगे कैट के राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का शुभारंभ

# रेल किराये में बढ़ोतरी के बाद अब छूट की तैयारी

**शाइन जैकब**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

**रेलवे** ने नए साल से यात्री किराया बढ़ा दिया था और अब वह सभी श्रेणी की ट्रेनों में यात्रियों को खाली सीटों के आधार पर छूट देने की योजना बना रहा है। इनमें मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेनें शामिल हैं। यह छूट उन ट्रेनों में उपलब्ध होगी जहां बड़ी संख्या में सीटें खाली होंगी।

इसे कम मांग वाली अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ाकर राजस्व में बढ़ोतरी की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इसके तहत ऐसे मार्गों में किराये में छूट दी जाएगी जहां सड़कों के कारण रेलवे को कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां ज्यादा स्टेशनों पर ठहराव के कारण ट्रेन को गंतव्य तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम श्रेणी आधारित छूट के मॉडल पर काम कर रहे हैं। यह उन सभी ट्रेनों पर लागू होगा जिनमें सीटें खाली जा रही हैं।'

रेल मंत्रालय के मुताबिक 2018-19 में शताब्दी एक्सप्रेस सहित विभिन्न ट्रेनों में प्रस्थान से गंतव्य तक भरी सीटों का औसत 70 से 100 फीसदी के बीच था। यह पहला मौका नहीं है जब रेलवे यात्रियों को लुभाने के लिए छूट दे रहा है। पहले से ही सभी तरह की ट्रेनों में पहला चार्ट तैयार होने के बाद खाली बची सीटों पर 10 फीसदी छूट की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा जिन ट्रेनों में श्रेणीवार भरी सीटें की संख्या 60 फीसदी से कम है, उनमें मांग आधारित किराये में छूट दी जा रही है।

2019-20 में कमाई के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही भारतीय रेल के लिए यात्री श्रेणी से ज्यादा राजस्व बेहद अहम है। रेलवे बोर्ड किराये को व्यावहारिक बनाने के लिए कई उपाय करने की योजना बना रहा है और किरायों में हाल में की गई बढ़ोतरी इसका हिस्सा है। रेलवे ने 1 जनवरी से विभिन्न श्रेणियों में यात्री किराये में एक पैसे से लेकर चार पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी। उपनगरीय और मासिक टिकटों को इस बढ़ोतरी से दूर रखा गया था।

अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान रेलवे की कमाई में 12.28 फीसदी यानी 16,391 करोड़ रुपये की गिरावट आई। रेलवे ने 133482.68 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य रखा था लेकिन उसे 117091.44 करोड़ रुपये मिले। दिलचस्प बात है कि पिछले वित्त वर्ष भी इस दौरान रेलवे की कमाई 117655.01 करोड़ रुपये रही थी। रेलवे के ऊंचे परिचालन अनुपात के कारण किराये में बढ़ोतरी रेलवे की वित्तीय स्थिति के लिए जरूरी थी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव ने पिछले सप्ताह मीडिया से कहा, 'इस तरह के संकट से संगठन मजबूत होगा।' उद्योग के सूत्रों के मुताबिक किराये में बढ़ोतरी मामूली है क्योंकि इससे रेलवे को केवल 2,300 करोड़ रुपये का फायदा होगा।

दिलचस्प है कि श्रेणी आधारित छूट पर माथापच्ची करना नीति निर्माताओं के लिए भी मुश्किल काम होगा क्योंकि रेलवे में मांग में एकरूपता नहीं है। यह कमजोर और ज्यादा मांग की अवधि, कम लाभकारी मार्गों, दूरी और ट्रेनों के समय पर निर्भर करता है।

अभी इस तरह की छूट राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और हमसफर ट्रेनों में दी जा रही है जहां भरी सीटों की संख्या 60 फीसदी से कम है। यह छूट ट्रेन के छूटने की तारीख से चार दिन पहले दी जाती है। इस मॉडल में मांग आधारित किराये के तहत 70 फीसदी तक सीटें भरी होने पर अंतिम किराये का 20 फीसदी छूट दी जाती है जबकि 70 से 80 फीसदी सीटें भरी होने पर 10 फीसदी छूट दी जाती है। 80 फीसदी से अधिक सीटें भरी होने पर कोई छूट नहीं मिलती है। मांग आधारित किराया शुरू करने के बाद यात्रियों ने हवाई यात्रा का रुख करना शुरू कर दिया था। इससे कई ट्रेनों में आधी से अधिक सीटें खाली जा रही थी। इस स्थिति से बचने के लिए रेलवे ने छूट की पहल की थी।

- सभी ट्रेनों में खाली सीटों के आधार पर मिलेगी छूट
- यात्री किराये से राजस्व बढ़ाने की कवायद
- कमाई का लक्ष्य पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है रेलवे

## संक्षेप में

### सुपरटेक ने सरकारी कोष से मांगे 1,500 करोड़ रु.

रियल्टी कंपनी सुपरटेक ने रविवार को कहा कि उसने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 12 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिये बनाए गये कोष से 1,500 करोड़ रुपये मुहैया कराने की मांग की है। कंपनी ने कहा कि इन परियोजनाओं में 20 हजार फ्लैट हैं। ये निर्माण के अंतिम चरण में हैं और इन्हें पूरा करके घर खरीदारों को सौंपने के लिये अंतिम समय में जरूरी वित्तपोषण की जरूरत है। सुपरटेक लिमिटेड के चेयरमैन आर.के.अरोड़ा ने यह जानकारी दी। *भाषा*

### भारतीय कंपनियों का विदेशी कर्ज बढ़ा

भारतीय कंपनियों का विदेशी कर्ज नवंबर 2019 में सालाना आधार पर 6.5 फीसदी बढ़कर 2.12 अरब डॉलर पर पहुंच गई। नवंबर 2018 में यह कर्ज 1.99 अरब डॉलर रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में घरेलू कंपनियों ने 2,11,53,22,022 डॉलर का कर्ज बाह्य वाणिज्यिक ऋण के स्वत: मंजूरी मार्ग से जुटाये। मंजूरी मार्ग से कोई पूंजी नहीं जुटाई गई। बाकी 9,86,681 डॉलर का कर्ज रुपये वाले बॉन्ड (आरडीबी) जारी कर जुटाए गए। *भाषा*

### एफपीआई ने निकाले 2,418 करोड़ रुपये

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने नए साल की शुरुआत में जमकर मुनाफा काटा है। एफपीआई ने जनवरी के पहले तीन कारोबारी सत्रों में ही भारतीय पूंजी बाजार से 2,418 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। डिपॉजिटरी के अनुसार एक से तीन जनवरी के दौरान एफपीआई ने शेयरों से 524.91 करोड़ रुपये और ऋण या बॉन्ड बाजार से 1,893.66 करोड़ रुपये की निकासी की। *भाषा*

बीएस बातचीत

# लोगों में खरीदने की ताकत रही तभी बढ़ेगी कार बिक्री : भार्गव

भारतीय वाहन उद्योग के साथ **आर सी भार्गव** करीब चार दशक से जुड़े हुए हैं। उनकी नजर में भी साल 2019 भारतीय वाहन उद्योग के लिए सबसे खराब रहा है। भार्गव ने कहा कि बिक्री में गिरावट की मुख्य वजह कार की कीमतों में इजाफे का सरकारी रवैया है। **अरिंदम मजूमदार** को दिए साक्षात्कार में मारुति के चेयरमैन भार्गव ने कहा कि राजस्व में कमी की भरपाई के लिए कारों पर कर में इजाफे का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर पड़ेगा। मुख्य अंश...

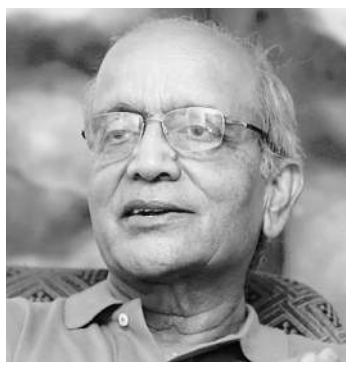

**क्या साल 2019 वाहन उद्योग के लिए सबसे खराब वर्ष रहा?**

बिक्री में गिरावट के लिहाज से साल 2019 संभवत: सबसे खराब रहा। कई मायनों में यह साल काफी असामान्य था। बीएस-4 से बीएस-6 की ओर जिस तरह से बढ़ा जा रहा है, वह पहले कभी नहीं हुआ। बीएस-4 का पंजीकरण 31 मार्च के बाद नहीं करने की शर्त पहले के किसी भी संक्रमण काल में नहीं रही है। इस समयसीमा ने सभी विनिर्माताओं को मुश्किल में डाल दिया है कि कैसे उत्पादन व बिक्री नियंत्रित की जाए ताकि साल के आखिर में कोई स्टॉक न बचे। इस समयसीमा ने उत्पादन व बिक्री के प्रबंधन के लिहाज से विनिर्माताओं के लिए काफी अनिश्चितताएं पैदा की हैं। कई ग्राहकों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि साल के आखिर में बीएस-4 वाहनों की घबराहट में बिकवाली होगी। मुझे लगता है कि रातोंरात बदलाव के इस तरीके से मुश्किल पैदा होती है। दूसरा, सुरक्षा व उत्सर्जन के उच्च मानकों के कारण वाहन की कीमत भी बढ़ी है। तीसरा, राजस्व में कमी की भरपाई के लिए नौ राज्यों ने कर बढ़ा दिए। सभी नीति निर्माता अभी भी सोचते हैं कि अगर आप कर बढ़ाना चाहते हैं तो शराब, सिगरेट और कार पर कर बढ़ा दीजिए। इससे वाहन चलाने की लागत बढ़ी है। इसके साथ ही बैंक अपने नुकसान को लेकर चिंतित हैं और उधारी मानक को सख्त बनाया है, जिससे काफी ग्राहक कर्ज नहीं ले पा रहे। आप किसी एक साल हुए काफी बदलाव देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वाहन निर्माताओं के लिए यह साल कैसे मुश्किल भरा रहा।

**ओला व उबर के चलते वाहन खरीदने की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है। भारतीय के पास खरीदने की ताकत नहीं है?**

ओला व उबर से युवाओं के बीच बिक्री पर वास्तव में असर पड़ा। इनके जीने का ढंग पिछली पीढ़ी से काफी अलग है। ऐसे लोगों की पहली प्राथमिकता कार खरीदने की नहीं है। वे ज्यादा पार्टी करते हैं, पर्यटन करते हैं और छुट्टियां मनाते हैं।

**क्या यह वर्ग इतना बड़ा है कि बिक्री पर असर डाल सके?**

अभी बहुत असर नहीं पड़ा है, लेकिन निश्चित तौर असर दिखना शुरू हो गया है। कंपनियों को उनके मनोविज्ञान को समझना होगा। बड़े शहरों में यह ज्यादा है। दिल्ली व मुंबई अब कंपनियों के लिए बिक्री केंद्र नहीं रह गए हैं।

**अब साल 2020 कैसा रहेगा?**

कार की अफोर्डेबिलिटी से बिक्री तय होगी। पिछले दशक में उद्योग की रफ्तार करीब 8 फीसदी थी। लेकिन मौजूदा लागत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उद्योग की रफ्तार 8 फीसदी भी रहेगी। मैं एंट्री लेवल कार और उसे खरीदने के लिए कर्ज लेने वाले ग्राहक की बात कर रहा हूं। साल 2019 की तरह अगर कार खरीदने की लागत 20 फीसदी बढ़ती है तो उस कार को खरीदने के लिए ग्राहक रकम कहां से लाएंगे।

**वाहन उद्योग में सुस्ती का सीधा असर जीडीपी और 5 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था की योजना पर पड़ेगा?**

देश के कुल विनिर्माण में कार की हिस्सेदारी 16 फीसदी है। इस उद्योग में सुस्ती से विनिर्माण की रफ्तार पर असर होगा। यह अन्य सहयोगी उद्योग को भी झटका देगा। हम इसके संकेत देख रहे हैं। इसलिए सरकार को अहसास होना चाहिए कि कार पर कर बढ़ाने से राजस्व नहीं बढ़ेगा। जीएसटी बढ़ने से विनिर्माण और नीचे जाएगा। क्योंकि खरीद की ताकत नहीं बढ़ रही है। हमें देखना होगा कि अप्रैल के बाद हालात कैसे रहते हैं। यह लागत का मामला है। डीजल व पेट्रोल कीमत एक समान होने के कारण डीजल कार इस्तेमाल करने का फायदा कम हो गया है।

**इलेक्ट्रिक वाहन पर मारुति की रफ्तार धीमी क्यों है? आपके प्रतिस्पर्धी आगे निकल गए हैं और वाहन पेश किया है?**

हमारी एकमात्र चिंता अफोर्डेबिलिटी और तकनीक की उपलब्धता है। बुनियादी ढांचा व बैटरी कहां है? कौन हमारी इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा। अगर मैं इसे बनाता हूं तो किसी न किसी को इसे खरीदना होगा।

**आपकी जैसी बड़ी कंपनी बैटरी प्लांट लगा सकती है?**

मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर आप हमसे सड़क बनाने को कहेंगे। यह मेरा काम नहीं है।

**लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन का दौर निश्चित तौर पर आएगा। क्या ऐसा नहीं है?**

इसके लिए बैटरी तकनीक व लागत में स्थिरता जरूरी होगी। अगर बैटरी की लागत घटकर 70 डॉलर आती है तो यह पूरे कारोबार को बदल देगी। तब शायद कोई बैटरी प्लांट लगा सकता है। भारत के लिए अभी यह काफी महंगी कार है।

# अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं रतन टाटा

**देव चटर्जी**
मुंबई, 5 जनवरी

**टाटा समूह** के दिग्गज रतन टाटा अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वह अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने के मामले में उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

टाटा की याचिका सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने होगी, जो इस पर सुनवाई की तारीख और पीठ पर फैसला लेंगे।

यह पहला मौका नहीं है जब टाटा कॉरपोरेट संघर्ष का सामना कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि टाटा के पद संभालने के ठीक बाद उन्होंने बहुत सारे क्षत्रपों को हटा दिया था जो पूर्व चेयरमैन जेआरडी टाटा के करीबी थे और उनकी जगह अपने लोगों को स्थापित किया था। टाटा ने तब टाटा स्टील के चेयरमैन रहे रूसी मोदी, इंडियन होटल्स के चेयरमैन अजित केलकर और टाटा केमिकल्स के दरबारी सेठ को 1990 के दशक में हटाया था।

टाटा को जेआरडी टाटा के एक अन्य करीबी नुस्ली वाडिया का समर्थन मिला। लेकिन टाटा और मिस्त्री की लड़ाई में वाडिया ने मिस्त्री के पक्ष में खड़ा होने का फैसला लिया। एक आंतरिक सूत्र ने कहा, जब मामला बोर्ड के सामने रखा गया था तब स्वतंत्र निदेशक के तौर पर वाडिया न सिर्फ टाटा स्टील की तरफ से कोरस स्टील के अधिग्रहण के खिलाफ थे बल्कि दूरसंचार क्षेत्र में निवेश के खिलाफ भी थे। टाटा नाखुश थे, लेकिन टाटा स्टील के बोर्ड में मामला आगे नहीं बढ़ाया और अन्य स्रोत से रकम का इंतजाम किया। टाटा की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मशहूर लड़ाई सिंगुर में टाटा मोटर्स के संयंत्र को लेकर हुई थी, जिसने बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा दिया।

साल 2012 में कार्यकारी चेयरमैन से रिटायर होने वाले टाटा ने अच्छे दिनों में दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन पर हमला बोला था, जो टाटा के दूरसंचार उद्यम को अहम मंजूरी देने के खिलाफ थे।

टाटा ने कई लड़ाई जीती है और कुछ गंवाई भी है लेकिन मिस्त्री संग लड़ाई सुर्खियां बन रही है क्योंकि मिस्त्री ने टाटा के कई फैसलों को रेखांकित किया है जो विनाशकारी हुए। लेकिन जानकारों ने कहा कि टाटा को वैश्विक ब्रांड बनाने और कोरस स्टील व जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियों के अधिग्रहण का श्रेय टाटा को दिया जाना चाहिए, जिसने टाटा समूह का कारोबार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा दिया।

**अदालत में संघर्ष**

- टाटा संस पर नियंत्रण है दांव पर
- टाटा संस की परिसंपत्तियां 6 लाख करोड़ रुपये का अनुमान
- टाटा चाहते हैं कि टाटा संस का नियंत्रण ट्रस्टों के पास रहे

# सुजलॉन के लिए होगा एस्क्रो खाता

## लेनदारों ने समाधान योजना को दिया अंतिम रूप। पवन ऊर्जा क्षेत्र में बोली की व्यवस्था पर तुलसी तांती ने प्रधानमंत्री कार्यालय से जताई चिंता

**श्रेया जय**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

देश की अग्रणी विंड टर्बाइन निर्माता और अभी कर्ज से लदी सुजलॉन एनर्जी के लिए लेनदारों ने एक समाधान योजना को अंतिम रूप दिया है। लेनदारों को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया माह के आखिर तक पूरी हो जाएगी, जो समाधान के लिए समयसीमा भी है।

सूत्रों ने कहा कि एक बैंक को छोड़कर सभी लेनदार कुल कर्ज के 50 फीसदी से ज्यादा हिस्से को नए कर्ज में तब्दील करने के लिए तैयार हैं जबकि बाकी कर्ज को लेनदार बट्टे खाते में डाल देंगे।

भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इस कंपनी के अहम लेनदार हैं। समझा जाता है कि इनमें से पीएनबी ने समाधान योजना का प्रतिरोध किया है।

योजना के तहत कंपनी के लिए एक एस्क्रो खाता बनाने का है ताकि कंपनी की लंबित परियोजना पूरी करने में मदद मिल सके। एक अधिकारी ने कहा, लेनदारों को रिटर्न मिलेगा और अगर कोई मुनाफा मार्जिन होता है तो वह कंपनी के खाते में जाएगी। एस्क्रो खाते से खर्च होने वाली सालाना रकम 800 से 1,200 करोड़ रुपये के दायरे में होगी।

लगता है कि लेनदारों ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया छोड़ने का फैसला लिया है और वे सुजलॉन के स्थायी कर्ज पर काम करेंगे। सुजलॉन पर अभी 7,000 करोड़ रुपये का कर्ज है और वह प्रवर्तक की हिस्सेदारी बिक्री के जरिए नए निवेशक पर विचार कर रही है। हालांकि अभी कोई सौदा नहीं हो पाया है।

जून 2019 की तिमाही में सुजलॉन का शुद्ध घाटा 337 करोड़ रुपये था जबकि राजस्व 833 करोड़ रुपये। जून 2019 में कंपनी का एकीकृत शुद्ध सावधि कर्ज (एफसीसीबी समेत) 7,751 करोड़ रुपये और कार्यशील पूंजी का कर्ज 4,000 करोड़ रुपये था।

समझा जाता है कि सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक तुलसी तांती ने केंद्र सरकार से कहा है कि पवन ऊर्जा क्षेत्र में बोली की प्रक्रिया शुरू करने से सुजलॉन समेत अन्य कंपनियों की वित्तीय हालत खस्ता हुई है।

एक अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कई बार हुई बैठक के दौरान तांती ने बोली प्रक्रिया पर चिंता जताई थी और परियोजनाओं के अभाव पर भी, जिसने इस क्षेत्र की बढ़त की रफ्तार धीमी की है।

सुजलॉन एनर्जी ने कर्ज पुनर्गठन और पीएमओ के साथ तांती की बैठक पर विस्तार से जानकारी देने से मना कर दिया।

भारत सरकार ने साल 2017 में पवन ऊर्जा परियोजना देने के लिए 25 साल पुरानी व्यवस्था समाप्त कर प्रतिस्पर्धी बोली का आगाज किया। उस अवधि में नई क्षमता जोड़ने का काम 650 मेगावॉट के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। लेकिन टैरिफ भी मौजूदा 2.5 रुपये प्रति मेगावॉट से आधी रह गई। पुरानी व्यवस्था में बिजली नियामक टैरिफ पर फैसला लेता था। भारत में मौजूदा वित्त वर्ष के लक्ष्य के मुकाबले आधी यानी 1,650 करोड़ रुपये की पवन ऊर्जा परियोजना ही स्थापित हो पाई है। साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष में कोई नई परियोनजा की पेशकश नहीं की गई है।

**सुजलॉन के समाधान की तैयारी**

- एक बैंक को छोड़कर सभी लेनदार कुल कर्ज के 50 फीसदी से ज्यादा हिस्से को नए कर्ज में तब्दील करने के लिए तैयार हैं जबकि बाकी कर्ज को लेनदार बट्टे खाते में डाल देंगे
- भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इस कंपनी के अहम लेनदार हैं। समझा जाता है कि इनमें से पीएनबी ने समाधान योजना का प्रतिरोध किया है

# हाइनकेन बढ़ा सकती है यूबीएल में हिस्सेदारी

**देवाशिष महापात्र**
बेंगलूरु, 5 जनवरी

डच कंपनी हाइनकेन भारत की यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (यूबीएल) में हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। हाइनकेन बियर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 46 फीसदी से बढ़ाकर 51 फीसदी कर नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है।

सूत्रों ने कहा कि बुधवार को मुंबई में पीएमएलए अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई वाले 15 बैंकों के कंसोर्टियम को शराब कारोबारी विजय माल्या की चल संपत्ति के इस्तेमाल की इजाजज दे दी। हाइनकेन इन बैंकों से संपर्क कर गिरवी शेयर खरीदना चाह रही है, जिसे लेनदार अपना कर्ज वसूलने के लिए बेचने की योजना बना रहे हैं।

एक सूत्र ने कहा, यूबीएल में हिस्सेदारी बढ़ाने के मामले में हाइनकेन हड़बड़ी में नहीं है क्योंकि वह पहले से ही कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक है। हालांकि अगर गिरवी शेयर बाजार में आते हैं तो कंपनी निश्चित तौर पर इसे खरीदना चाहेगी ताकि नियंत्रक हिस्सेदारी पा सके। कंपनी बैंकों से भी संपर्क कर सकती है, जैसा कि उसने पहले भी किया है।

इस बारे में जानकारी के लिए यूबीएल को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला।

सितंबर तिमाही के आखिर में हाइनकेन की यूबीएल में हिस्सेदारी विभिन्न सहायक फर्मों के जरिये करीब 46 फीसदी थी।

# इमामी सीमेंट के लिए जल्द शुरू होगी बोली

**अभिषेक रक्षित**
कोलकाता, 5 जनवरी

**इमामी सीमेंट** के अधिग्रहण के लिए बोली इस साल जनवरी के मध्य से शुरू हो सकती है। आदित्य बिड़ला समूह की अल्ट्राटेक सीमेंट 6,500-7,000 करोड़ रुपये की नकदी की पेशकश के साथ इस दौड़ में सबसे आगे है। इमामी समूह ने कर्ज घटाने के लिए अपनी सीमेंट परिसंपत्ति के मुद्रीकरण का फैसला लिया है और मौजूदा वित्त वर्ष के आखिर तक समूह के स्तर पर कर्जमुक्त बनने का लक्ष्य तय किया है। शुरू में हालांकि श्री सीमेंट, डालमिया भारत सीमेंट, नूवोको और अन्य प्राइवेट इक्विटी निवेशकों ने रुचि दिखाई थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट अपनी तरफ से बोली लगा सकती हैं।

इमामी समूह की इकाई इमामी सीमेंट ने आर्पवुड कैपिटल को इस सौदे के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। सूत्र ने कहा, बोली की प्रक्रिया जनवरी के मध्य से शुरू हो सकती है। सूत्र ने कहा, इमामी ने शुरू में 80 लाख टन सालाना क्षमता वाली सीमेंट परिसंपत्ति के लिए 8,500-9,000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन की इच्छा जताई थी, लेकिन इस बात की संभावना है कि समूह अंतत: इस सौदे का निपटान 7,000-7,500 करोड़ रुपये में कर सकती है।

सूत्र ने कहा कि यह मूल्यांकन इमामी सीमेंट की स्थापित क्षमता के लिए 110 डॉलर प्रति टन पर आधारित है और कंपनी की पहुंच को देखते हुए इसमें 10 फीसदी प्रीमियम जुड़ा हुआ है। यह प्रभावी तौर पर करीब 7,000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन में परिवर्तित होता है। इस बोली में सभी परिसंपत्तियां व खनन पट्टा शामिल होगा। इस मसले पर इमामी सीमेंट ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। इमामी सीमेंट के पास छत्तीसगढ़ के रिसडा में 25 लाख टन सालाना क्षमता वाला एकीकृत विनिर्माण संयंत्र है जबकि पानागढ़, पश्चिम बंगाल में 25 लाख टन सालाना क्षमता का संयंत्र है। इसके अलावा ओडिशा के जाजपुर की इकाई अभी चालू नहीं हुई है।

बिहार के भभुआ में भी 18 लाख टन क्षमता वाले संयंत्र में 12 लाख टन क्षमता और जोड़ी जानी है। जाजपुर इकाई में उत्पादन का ट्रायल दिसंबर 2018 में चालू हो गया है। खरीदार के सूत्रों ने कहा कि पानागढ़ संयंत्र की स्थापित क्षमता 25 लाख टन सालाना है, लेकिन इमामी सीमेंट के पास सिर्फ 20 लाख टन उत्पादन की मंजूरी है। इन परिसंपत्तियों के अलावा कंपनी के पास छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में खनन पट्टा भी है।

# एसबीआई काड्र्स का आईपीओ इसी महीने

**ऐश्ली कुटिन्हो**
मुंबई, 5 जनवरी

**भारतीय स्टेट** बैंक की क्रेडिट कार्ड इकाई एसबीआई काड्र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज को अगर नियामक की मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी इसी महीने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम बाजार में उतार देगी।

बाजार नियामक सेबी के पास पेशकश दस्तावेज का मसौदा नवंबर में जमा कराने वाली कंपनी को जल्द मंजूरी मिल सकती है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। कंपनी शेयर बिक्री के जरिए 9,000-9,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर कर चल रही है, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपये के नए शेयर होंगे। इस इश्यू में मौजूदा शेयरधारकों एसबीआई और सीए रोवर का करीब 13.1 करोड़ शेयर का ओएफएस होगा, जो इस आईपीओ में क्रमश: 5 फीसदी और 10 फीसदी हिस्सेदारी का विनिवेश करेंगे।

एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने कहा, सेबी का ऑब्जर्वेशन अगले कुछ दिनों में मिलने की उम्मीद है। विदेश में रोडशो हो चुके हैं और हमने निवेशकों की भारी मांग देखने को मिली है। हमारा इरादा इसी महीने आईपीओ उतारने का है।

इस कंपनी में एसबीआई की हिस्सेदारी 74 फीसदी है जबकि बाकी सीए रोवर के पास है, जिसका नियंत्रण कार्लाइल समूह करता है। दिसंबर 2017 से पहले एसबीआई के पास 60 फीसदी हिस्सेदारी थी जबकि बाकी 40 फीसदी हिस्सेदारी जीई कैपिटल के पास थी। दिसंबर 2017 में जीई कैपिटल इस कंपनी से पूरी तरह निकल गई। इसके बाद एसबीआई ने हिस्सेदारी बढ़ाकर 74 फीसदी कर ली जबकि सीए रोवर ने बाकी 26 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली।

बैंकर ने कहा, यह इकलौता कार्ड बिजनेस है जो सूचीबद्ध होने जा रहा है और इसमें उम्दा रिटर्न सृजित करने की क्षमता है। बाजार में विस्तार की काफी गुंजाइश है और हम इस कारोबार में खासी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। एसबीआई के समर्थन के साथ इसके लिए बिना सेवा वाले इलाकों में बढ़त की काफी मौका है।

ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल कंपनी की ताकत के तौर पर इसकी मजबूत मूल कंपनी और वितरण नेटवर्क को मानती है, साथ ही को-ब्रांडेड पार्टनरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता व असुरक्षित पोर्टफोलियो को कमजोरी मानती है। ब्रोकरेज ने एक नोट में कहा है, इस क्षेत्र में बैंक काफी प्रतिस्पर्धी हो गई है। अगर यह बेहतर नहीं रहा तो कंपनी के मार्जिन व बढ़त दोनों पर दबाव डालेगा।

भारत में एचडीएफसी बैंक के बाद दूसरी सबसे बड़ी कार्ड कंपनी एसबीआई काड्र्स की बाजार हिस्सेदारी कार्ड संख्या के लिहाज से सितंबर 2019 के आखिर में 18 फीसदी थी जबकि क्रेडिट कार्ड लेनदेन आदि में वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में 17-18 फीसदी थी। इन सभी मानकों में ज्यादातर में एसबीआई ने बाजार हिस्सेदारी विभिन्न वर्षों में बढ़ाई है।

पिछले तीन वित्त वर्ष में कंपनी के कुल कार्ड खर्च में सालाना 54.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी अपना राजस्व शुल्क आधारित आय मसलन इंटरचेंज शुल्क, देर से भुगतान पर शुल्क और सालाना शुल्क आदि से अर्जित करती है। गैर-ब्याज आय की हिस्सेदारी राजस्व में पिछले तीन वित्त वर्ष में बढ़ी है और यह 2016-17 के 43.6 फीसदी के मुकाबले 2018-19 में 48.9 फीसदी पर पहुंच गई। वित्त वर्ष 2019 में एसबीआई काड्र्स का शुद्ध लाभ 862 करोड़ रुपये रहा जबकि राजस्व करीब 7,000 करोड़ रुपये।

एसबीआई काड्र्स आईपीओ का कामकाज कोटक महिंद्रा कैपिटल, ऐक्सिस कैपिटल, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, एचएसबीसी, नोमूरा और एसबीआई कैपिटल संभाल रही है।

**भारत में कार्ड कंपनियां**

दूसरी सबसे बड़ी कार्ड कंपनी है एसबीआई कार्ड

| बैंक | कार्ड की संख्या (लाख में) | वित्त वर्ष 2019 में बाजार हिस्सा (फीसदी) | सालाना चक्रवृद्धि बढ़त (फीसदी) |
|---|---|---|---|
| एचडीएफसी बैंक | 125 | 27 | 19 |
| एसबीआई कार्ड | 83 | 18 | 24 |
| आईसीआईसीआई बैंक | 66 | 14 | 16 |
| ऐक्सिस बैंक | 60 | 13 | 34 |
| सिटीबैंक | 27 | 6 | 2 |

स्रोत : डीआरएचपी - एसबीआई काड्र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज

# दामों में सुधार के बाद धातु क्षेत्र में नजर आ रही आस

**राजेश भयानी, ईशिता आयान दत्त और टीई नरसिम्हन**
मुंबई/कोलकाता/चेन्नई, 5 जनवरी

एसऐंडपी बीएसई का सूचकांक धातु खंड में सुधार के संकेत दे रहा है। बढ़ते मार्जिन से बेंचमार्क सेंसेक्स बेहतर प्रदर्शन कर रहा है जिससे सूचकांक में पिछले तीन महीनों के दौरान 22.4 प्रतिशत की उछाल आई है। निचले स्तर पर जाने के बाद इस अवधि में इस्पात कंपनियां दाम बढ़ाती रही हैं। मूल धातु की कंपनियों को मांग में सुधार और ऑर्डर बुक में इजाफा होने की भी उम्मीद है। पिछले एक महीने में लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में 4.8 प्रतिशत की तजी आई है, हालांकि लौह अयस्क और इस्पात जैसी अन्य धातुओं के दामों में 3.5 से 5.8 प्रतिशत तक की तेजी है।

## जस्ता : आपूर्ति में कमी की वजह से तेजी

अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2019 के दौरान जस्ते की मांग में बढ़त नजर आई है। पहले 10 महीने में रिफाइंड जस्ते के उपयोग में हल्की-सी बढ़त हुई और यह 0.3 प्रतिशत बढ़कर 1.133 करोड़ टन हो गया।

हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्याधिकारी सुनील दुग्गल ने कहा कि मांग बढ़ने के कारण बाजार में आपूर्ति कम होने वाली है। जस्ते का मौजूदा स्टॉक (वैश्विक) काफी गंभीर स्तर पर होने की वजह से अनिश्चितता की स्थिति है।

उन्होंने कहा कि दामों का स्तर ऐतिहासिक रूप से 3,000 डॉलर प्रति टन के शीर्ष स्तर पर था। अगर दामों का मौजूदा स्तर (प्रति टन 2,300 डॉलर) लंबे समय तक बना रहता है, तो इससे खदान बंद हो सकती है क्योंकि 2,000 डॉलर के आस-पास का स्तर छोटे खनिकों के लिए दबावपूर्ण वाली स्थिति है जिससे आपूर्ति को नुकसान होगा तथा यह बाजार को और मुश्किल में डाल देगा।

फिलहाल एलएमई पर जस्ते का भाव 2,300 डॉलर प्रति टन के स्तर पर चल रहा है। भारत में जैसा कि अपेक्षित बुनियादी ढांचे पर जोर दिए जाने के कारण गैल्वनाइज्ड उत्पादों का उपयोग बढ़ रहा है, इसलिए जस्ते की मांग बढ़ेगी। लगभग 50 फीसदी जस्ते का इस्तेमाल गैल्वनाइजेशन के लिए किया जाता है जिसका उपयोग इस्पात में जंग और क्षरण से निपटने के लिए किया जाता है।

इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयंत रॉय ने कहा कि निर्माण में कुछ सकारात्मक परिदृश्य के कारण जस्ते की मांग के लिहाज से वित्त वर्ष 21 सकारात्मक वृद्धि के साथ समाप्त होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 20 की पहली छमाही के दौरान जस्ते की मांग वृद्धि में गिरावट नजर आई थी।

## एल्युमीनियम : दामों में ज्यादा इजाफे की उम्मीद नहीं

इक्रा के अनुसार भारत में प्रमुख रूप से वाहन बिक्री और उत्पादन में मंदी के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 20 की पहली छमाही के दौरान देश में एल्युमीनियम की मांग वृद्धि में करीब 2.5 प्रतिशत की नरमी रही है। वित्त वर्ष 19 में वृद्धि दर छह प्रतिशत थी।

एल्युमीनियम की करीब 30 से 40 प्रतिशत मांग में वितरण और पारेषण का योगदान रहता है तथा शेष भाग में पैकेजिंग, निर्माण और वाहन क्षेत्र का योगदान होता है। बाल्को के चेयरमैन एसके रूंगटा ने कहा कि नवंबर-दिसंबर में दाम प्रति टन 1,700 डॉलर के स्तर पर थे। दाम इससे कम नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर कुछ स्मेल्टर बंद हो जाएंगे और कुल मिलाकर मांग-आपूर्ति का संतुलन स्थापित हो जाएगा। इससे दाम बढ़ेंगे, हालांकि कोई बहुत ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद नहीं है।

## तांबा और सीसा : ऑर्डरों में सुधार का इंतजार

अप्रैल 2019 के बाद एलएमई पर तांबे के दामों में तीव्र गिरावट आई है और नवंबर 2019 के आखिर तक दामों पर दबाव रहा है। हालांकि इसके बाद से दाम उस स्तर से बढ़कर प्रति टन 6,153 डॉलर तक हो गए। हिंदुस्तान कॉपर के अधिकारियों के अनुसार एलएमई पर तांबे के दामों में सुधार का रुख जारी रहेगा। ऐसे कई कारण है जिन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार के आंशिक समाधान के प्रभाव से एलएमई पर तांबे की कीमतों को बढ़ने में मदद मिल पाई है। पूरा समाधान होने के मामले में काफी इजाफा होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि चीन और भारत में बुनियादी ढांचे के खर्च में बढ़ोतरी के साथ-साथ भंडारण गृह में तांबे के स्टॉक में गिरावट और वर्ष 2020 में कमी के अनुमान से तांबे के दामों में इजाफे का रुख रहने के आसार रहेंगे।

भारत में मूल धातु के उत्पादकों और प्रमुख उपभोक्ताओं का विश्लेषण करने वाली मुंबई स्थित रेगसस कंस्लटिंग के निदेशक संदीप डागा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक आंकड़े स्थिर हो रहे हैं। कई तिमाहियों की तीव्र औद्योगिक मंदी के बाद ऐसा हो रहा है। हालांकि इस धारणा में तेजी आ सकती है, लेकिन ऑर्डर बुक में अब तक ठोस बदलाव नहीं दिखा है। इनके धातु विश्लेषण द्वारा भारत के सीसा कारोबार के लिए किया गया मासिक विश्लेषण बताता है कि बैटरी क्षेत्र की मांग में कमी रही है। हाल के महीनों में सीसा उत्पादकों को बेहतर ऑर्डर बुक की वजह से फायदा तो मिला है, हालांकि यह फायदा शायद ज्यादा देर तक कायम न रह सके।

## इस्पात : बुनियादी ढांचे में तेजी के कारण मजबूती

इस्पात में जस्ते जैसे कारणों से ही सुधार हो रहा है। खुदरा क्षेत्र में मांग वृद्धि और सरकारी परियोजनाएं दामों का संचालन करने वाले प्रमुख कारण हैं। सितंबर में निचले स्तर तक जाने के बाद नवंबर से कंपनियां दाम बढ़ाती जा रही हैं। जेएसडब्ल्यू के संयुक्त प्रबंध निदेशक और समूह के मुख्य वित्त अधिकारी शेषगिरि राव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दामों में इजाफा शुरू होने के बाद तुरंत खरीद शुरू हो गई। इस तरह दामों में तेजी को वहन किया गया। उन्होंने कहा कि अगली तिमाही के लिए रफ्तार सकारात्मक है।

इस्पात की मांग में बुनियादी ढांचा, निर्माण और रियल एस्टेट का योगदान करीब 55 से 60 प्रतिशत तक रहता है जिनमें सुधार नजर आ रहा है। शेष करीब 40 प्रतिशत में वाहन, मशीनरी और पूंजीगत उत्पादों का योगदान रहता है। इस क्षेत्र के सुधार में देरी की संभावना जताई जा रही है।

पिछले दो सप्ताह के दौरान आईसीईएक्स जिंस एक्सचेंज पर लंबे इस्पात उत्पादों के लिए बोले गए दामों में (गाजियाबाद को छोड़कर) नौ प्रतिशत का इजाफा हुआ और भाव बढ़कर 32,000 रुपये प्रति टन हो गया है। इक्रा के रॉय के मुताबिक वित्त वर्ष 21 में इस्पात की मांग वृद्धि पांच से छह प्रतिशत रहने के आसार हैं।

## लौह अयस्क : दामों में और इजाफा होने के आसार

लौह अयस्क दिग्गज एनएमडीसी ने लौह अयस्क के दामों में प्रति टन करीब 200 रुपये का इजाफा किया है। सात महीने के बाद यह इसका पहला इजाफा है। लौह अयस्क टुकड़े के दाम फिलहाल 2,800 रुपये प्रति टन हैं, जबकि चूरे के दाम बढ़कर 2,560 रुपये प्रति टन हो चुके हैं। दामों में पिछली बार इजाफा मई 2019 में किया गया था जिसके बाद इसे दामों में कमी करनी पड़ी थी। अब दाम मई 2019 के स्तर पर हैं। इस्पात की बड़ी कंपनियों ने लौह अयस्क का स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जबकि छोटे इस्पात विनिर्माता बाजार में लौह अयस्क की कमी के पूर्वानुमान के कारण डरने लगे हैं। दिसंबर 2019 में एनएमडीसी की बिक्री वृद्धि दर सात प्रतिशत बढ़कर 30.4 लाख टन हो चुकी है। उद्योग के प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि अगले तीन महीने में दामों में 10 से 15 प्रतिशत तक का इजाफा होगा क्योंकि आयातित और घरेलू लौह अयस्क के बीच अंतर अब भी ज्यादा है।

# 'अन्य' आयात के लिए लाइसेंस की तैयारी

**शुभायन चक्रवर्ती**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

## गैर-जरूरी आयात पर नियंत्रण की कोशिश

- रसायनों, प्लास्टिक उत्पादों, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फुटवियर जैसे 'गैर-जरूरी आयात' पर प्रतिबंध की तैयारी
- शुल्क शब्दावली के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत हार्मोनाइज्ड सिस्टम पर अमल करता है
- इस प्रणाली का इस्तेमाल 10,000 से अधिक आयात श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है
- लेकिन 2433 श्रेणियों को 'अन्य' के तौर पर वर्गीकृत किया गया है
- सूत्रों का कहना है कि कई श्रेणियों में आयात 100 करोड़ रुपये तक का है

भारत के आयात क्षेत्र के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग मानक पेश किए जा सकते हैं। ये मानक ऐसे आयात को ध्यान में रखकर लाए जाने की संभावना है जिन्हें उचित तरीके से श्रेणीबद्ध नहीं किया गया हो और वह नीतिगत उपायों के पालन के संदर्भ में विफल रहा हो।

वाणिज्य विभाग ने इस कदम के जरिये खासकर चीन से लगभग 4 लाख करोड़ रुपये मूल्य के आयात को सीमित करने की योजना बनाई है। मौजूदा समय में, हजारों आयात श्रेणियों को आधिकारिक तौर पर व्यापार वर्गीकरण पुस्तिका में 'अन्य' के तौर पर पेश किया जाता है। इनमें से कई 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक के माल से संबंधित हैं। लेकिन इस बारे में पुख्ता आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लाइसेंसिंग व्यवस्था से भारत में घटिया उत्पादों के प्रवेश को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'लाइसेंसिंग की सख्त व्यवस्था इन उत्पादों के लिए सुझाई गई है, हालांकि इसके लिए उपयुक्त तकनीकी नियमन जरूरी हो सकता है।'

1277 अरब डॉलर मूल्य के या भारत के मौजूदा सालाना आयात के 26 प्रतिशत के बराबर 371 आयात पर प्रतिबंध का सुझाव दिया गया है। इस मामले पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अधिकारियों की 18 समूह बैठकें की जा चुकी हैं।

अंतर-मंत्रालयी समूह ने सुझाव दिया है कि रसायनों, प्लास्टिक उत्पादों, फर्नीचर, मशीनरी और कलपुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फुटवियर पर ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वाणिज्य विभाग ने वियतनाम, थाईलैंड और हाल में म्यांमार जैसे देशों के जरिये भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की घुसपैठ की पहचान की कोशिश तेज की है। डंपिंग शुल्कों से जूझने के बाद, चीन ने ऊंची दरों से बचने के प्रयास में मलेशिया के जरिये सौर उपकरण भेजने पर जोर दिया है।

इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस तरह के ज्यादातर आयात को 'गैर-जरूरी' श्रेणी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने वाणिज्य विभाग से सितंबर 2018 तक ऐसे उत्पादों की सूची प्रकाशित करने को कहा था, जब देश बड़े चालू खाते के घाटे की समस्या से जूझ रहा था। इस श्रेणी के तहत आने वाले माल के बारे में जांच-पड़ताल किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने संबद्ध खेपों का विवरण मुहैया कराने को कहा था।

राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड भारत के अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों के जरिये व्यावसाय पर डेटाबेस तैयार करता है।

भारत का कुल आयात 2018-19 में 514 अरब डॉलर था, जो पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है।

व्यवसाय से संबंधित उत्पादों के वर्गीकरण के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन ऐंड कोडिंग सिस्टम पर अमल करता है, जिसे हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) भी कहा जाता है।

इस प्रणाली में 10,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए अलग अलग स्तर शामिल हैं।

# ज्यादा खर्च करने वालों के लिए नए आईटीआर फॉर्म

**दिलाशा सेठ**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

- बैंक खाते में एक करोड़ से ज्यादा जमा या विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये या बिजली बिल पर एक लाख रुपये खर्च करने वालों के लिए आईटीआर-4-सुगम

**आयकर** विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए दो आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म अधिसूचित किए हैं जिससे बड़ी तादाद में उन लोगों को अनिवार्य रूप से रिटर्न फाइल करना होगा जिन्हें पहले ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी।

कर विभाग ने जनवरी में आईटीआर-1-सहज और आईटीआर-4-सहज को पेश किया है। साथ ही विभाग ने नकदी जमाओं, विदेश यात्रा और बिजली पर होने वाले खर्च से संबंधित विवरणों का खुलासा भी अनिवार्य बनाया है।

आईटीआर-1 सहज वेतन, एक मकान, ब्याज आय और पारिवारिक पेंशन आय आदि से कुल 50 लाख रुपये तक की सालाना आय कमाने वाले लोगों के लिए है। इस फॉर्म के लिए पासपोर्ट विवरण जरूरी होगा।

टैक्समैन में डीजीएम नवीन वाधवा ने कहा कि आईटीआर-4-सुगम उन लोगों के लिए है तो जिनकी आय तो सालाना 50 लाख रुपये तक है, और एक मकान भी है, लेकिन उनके बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से ज्यादा जमा है या उन्होंने विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये या बिजली बिल चुकाने पर एक लाख रुपये का खर्च किया है।

यह फॉर्म एचयूएफ और उन कंपनियों के लिए भी लागू होगा जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक की है, एक मकान (एकल स्वामित्व) है, व्यवसाय और पेशे से आय हासिल होती है।

वाधवा ने कहा कि यदि व्यक्तिगत करदाता किसी आवासीय परिसंपत्ति में सामूहिक तौर पर मालिक हैं तो वे आईटीआर-1 या आईटीआर-4 नहीं भर सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित आय का आकलन 2020-21 में किया जाता है।

अभी तक लोगों को कुल आय न्यूनतम सीमा के पार होने पर ही टैक्स रिटर्न फाइल की जरूरत थी। बजट घोषणा के साथ, बड़ा खर्च करने की क्षमता रखने वाले लोग कर बचाने या रिटर्न फाइल से बचने में सक्षम नहीं होंगे।

वाधवा ने कहा, 'सामान्य तौर पर, आयकर विभाग संबद्ध आकलन वर्ष के अप्रैल के पहले सप्ताह में आईटीआर फॉर्म के बारे में जानकारी देता है। हालांकि इस व्यवस्था के विपरीत विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में ही आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्मों को अधिसूचित कर दिया है।'

# कृषि निर्यात नीति: आठ राज्यों ने कार्य योजना तैयार की

**एजेंसियां**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

**सरकार** ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक समेत आठ राज्यों ने कृषि निर्यात नीति (एईपी) के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस नीति का मकसद ऐसे निर्यात को दोगुना करना है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, 'निर्यात और किसानों की आय दोगुना किए जाने के लक्ष्य के साथ पिछले साल कृषि निर्यात नीति की घोषणा की गई थी। कई राज्यों ने इसके लिए नोडल एजेंसी और नोडल अधिकारी को नियुक्त किया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नगालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक ने राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है और अन्य राज्य इसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं।'

एईपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों की गहरी दिलचस्पी सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। अपेडा ने कार्य योजना की तैयारी के लिए पूरे वर्ष राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकें की थीं।

# बजट में पीएसयू बैंकों में पूंजी लगाने की घोषणा के आसार नहीं

**एजेंसियां**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

**आगामी** बजट में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पूंजी लगाने की घोषणा किए जाने की संभावना नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा बैंकों को फंसे कर्ज की वसूली तेज करने और बाजार से कोष जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

अधिकारियों का कहना है कि बैंक 2020-21 के दौरान अपनी कोष उगाही कोशिशों के तहत अपने गैर-प्रमुख व्यवसायों की बिक्री कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी-2 सरकार का दूसरा बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, बैंकों को इस कैलेंडर वर्ष के दौरान एनसीएलटी और गैर-एनसीएलटी मामलों, दोनों के समाधान से मजबूत रकम वसूली की उम्मीद है और साथ ही बाजार से पूंजी जुटाने की भी संभावना बरकरार है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 76.6 प्रतिशत की 7 वर्षीय ऊंचाई पर है।

सूत्रों का कहना है कि कुछ फंसे ऋणों में, बैंकों ने 100 प्रतिशत तक का प्रावधान किया है और इन खातों से वसूली मददगार साबित होगी।

अधिकारियों का कहना है कि कुछ बैंकों की शेयर कीमतें मजबूत हो रही हैं जिससे उन्हें सरकारी हिस्सेदारी घटाने का अच्छा अवसर मिला है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहायक इकाइयों एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज और यूटीआई म्युचुअल फंड में अपनी हिस्सेदारी घटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुका है। वह नैशनेल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में 50 लाख शेयर (1.01 प्रतिशत हस्सेदारी) बेचने की संभावना तलाश रहा है। पूंजी उगाही की कोशिश में इसी तरह के प्रयास सरकार के स्वामित्व वाले अन्य ऋणदाताओं द्वारा किए जा रहे हैं।

चार प्रमुख बैंकों में पीएनबी को 16,091 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 11,768 करोड़ रुपये, केनरा बैंक को 6,571 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक को 2,534 करोड़ रुपये की पूंजी मुहैया कराई गई।

विलय से जुड़े बैंकों इलाहाबाद बैंक को 2,153 करोड़ रुपये, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 1,666 करोड़ रुपये और आंध्रा बैंक को 200 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए थे।

जहां सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया जाएगा, वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय होगा। इसी तरह, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समेति किया जाएगा।

# बीएसएनएल ने बिक्री के लिए परिसंपत्तियों की पहचान की

**एजेंसियां**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

- सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया था

**सरकार** के स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) दूरसंचार कंपनियों की प्रमुख परिसंपत्ति बिक्री योजनाओं के तहत निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को 20,160 करोड़ रुपये मूल्य की 14 परिसंपत्तियों का विवरण सौंप दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि कौशल विकास मंत्रालय भूमि तलाश रहा है और दूरसंचार विभाग ने गाजियाबाद में बीएसएनएल का भूखंड मंत्रालय को सौंपने की पेशकश की है। इस भूमि की अनुमानित वैल्यू 2,000 करोड़ रुपये है। इस बारे में संपर्क किए जाने पर बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने कहा, 'निगम अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री के हरसंभव प्रयास कर रहा है और उसने दीपम के जरिये 20,000 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की 14 परिसंपत्तियों को चिह्नित किया है।'

पुरवार ने कहा कि यह भूमि मुंबई, तिरूवरंतपुरम, चेन्नई, गाजियाबाद और अन्य स्थानों समेत पूरे भारत में मौजूद है। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया था जिसमें नुकसान वाली दो कंपनियों का विलय, उनकी परिसंपत्तियों की बिक्री और कर्मचारियों को वीआरएस देना शामिल था। पिछले कुछ सप्ताहों में इन दोनों कंपनियों ने अपनी वीआरएस योजनाएं पेश की हैं और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के हजारों कर्मचारियों ने स्वेच्छिक सेवानिवृति का विकल्प चुना है। इस याजना से बीएसएनएल का पारिश्रमिक बिल 50 प्रतिशत तक और एमटीएनएल के लिए 75 प्रतिशत तक घटाने में मदद मिलेगी।

# ग्रामीण, कस्बाई कारोबार प्रबंधन के लिए इकाई बनाएगा एसबीआई

**अभिजीत लेले**
मुंबई, 5 जनवरी

वित्तीय समावेशन के तहत बैंकिंग सेवाओं की पेशकश के लिए देश भर में बैंक के पास करीब 58,000 बीसी और 22,010 शाखाएं हैं

**देश** में कस्बाई और ग्रामीण शाखाओं के बड़े नेटवर्क के प्रबंधन के लिए भारतीय स्टेट बैंक एक इकाई बनाने जा रहा है जिसके माध्यम से कृषि कर्ज, सूक्ष्म वित्त और वित्तीय समावेशन पर बल दिया जाएगा।

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, 'हम राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की खुदरा बैंकिंग खंड में बड़े बदलाव कर रहे हैं। बैंक ने प्रत्येक सर्कल में सूक्ष्म वित्त और वित्तीय समावेशन के लिए एक अलग नेटवर्क तैयार करने का निर्णय लिया है। नई इकाई का प्रमुख महाप्रबंधक होगा।'

इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की गतिविधियों और बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट्स (बीसी) चैनल पर दृष्टि को व्यापक करना है। कुमार ने कहा कि पहले इन गतिविधियों का प्रबंधन बिखरा हुआ था जो अब केंद्रित होगा। ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में करीब 35 फीसदी शाखाओं का प्रबंधन इस इकाई के जरिये किया जाएगा। बैंक ने चंडीगढ़ सर्कल में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। फिलहाल एसबीआई 17 सर्कलों के जरिये अपना राष्ट्रीय परिचालन करता है। प्रत्येक सर्कल का प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक होता है।

वरिष्ठ एसबीआई अधिकारियों ने कहा कि वित्तीय समावेशन (एफआई) गतिविधि के परिणाम स्वरूप मिले कारोबार ने शाखा नेटवर्कों पर दबाव बनाया है और नियमित ग्राहकों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अब वित्तीय समावेशन के माध्यम से आने वाले ग्राहकों की सेवा नई इकाई के जरिये की जाएगी।

वित्तीय समावेशन के तहत बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए बैंक के पास देश भर में करीब 58,000 बीसी और 22,010 शाखाएं हैं। एसबीआई ने 2019-20 में 1.73 लाख करोड़ रुपये की 39.75 करोड़ लेनदेन दर्ज किए इस लिहाज से प्रतिदिन करीब 15 लाख लेनदेन किए गए।

बैंक ने रणनीतियों पर काम किया है और बिना बैंक वाले लोगों के दरवाजे तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए तकनीक का लाभ उठाया है ताकि उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाया जा सके।

सर्कल खुदरा और डिजिटल बैंकिंग समूह के तहत काम करते हैं। यह एसबीआई का सबसे बड़ा कारोबारी खंड है। 31 मार्च, 2019 के मुताबिक इसमें उसके घरेलू जमाओं की हिस्सेदारी 97.05 फीसदी और घरेलू अग्रिमों की हिस्सेदारी 54.89 फीसदी है। समूह में आठ रणनीतिक कारोबारी इकाई है जो पूरे देश में सबसे बड़े शाखा नेटवर्क का संचालन करती हैं।

# पांच वर्षीय विजन में महिला कल्याण पर जोर देगी सरकार

**शुभायन चक्रवर्ती**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

सरकार महिला कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर दे रही जोर

**केंद्र** सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान महिलाओं के कल्याण, सतत विकास, और निवेश-केंद्रित आर्थिक वृद्धि के लिए प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इस सबंध में शनिवार को एक बैठक हुई थी जिसमें मंत्रियों ने क्षेत्र-केंद्रित योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सौंपी थीं।शुक्रवार से दो-दिवसीय बैठक में 10 क्षेत्र-केंद्रित मंत्रालय समूहों ने पिछले कार्यकाल के दौर शुरू की गई पहलों और विकास कार्यों के बारे में अपनी योजनाएं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के समक्ष पेश कीं।

मौजूदा समय में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में सुधार लाना ज्यादातर मंत्रियों का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है, लेकिन साथ ही सरकार इस कार्यकाल में महिलाओं के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना तलाश रही है।

सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) प्रत्येक क्षेत्रीय वर्ग के साथ विस्तार से चर्चा की है और जल्द ही मंत्रियों के निर्णायक विजन दस्तावेजों पर जानकारी मुहैया कराई जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि संसद में बजट पेश किए जाने से महज कुछ सप्ताह पहले इस तरह के बदलावों के बावजूद बजटीय आवंटन हरेक विभाग के अनुसार किया जाएगा।

प्रत्येक मंत्रालय की जरूरतों को व्यक्तिगत तौर पर सुनने के बजाय (जैसा कि शुरू में मानक रहा है) पीएमओ ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण की भावना पर जोर दिया है, जिसके लिए नीतियों में अधिक बदलाव की जरूरत है। व्यक्तिगत तौर पर सचिवों ने अपने क्षेत्रीय समूहों का नेतृत्व किया। समूह स्तर पर वाणिज्य, वित्त, एमएसएमई, श्रम एवं ग्रामीण विकास शामिल हैं।

वाणिज्य सचिव के नेतृत्व वाले वाणिज्य समूह में वाणिज्य विभाग, भारी उद्योग, वस्त्र और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआईआईटी) शामिल हैं।

वाणिज्य विभाग का कहना है कि निर्यातकों और एमएसएमई, खासकर नकदी संकट से जूझ रहे क्षेत्र के लिए कम दर पर ऋण उपलब्ध कराना जरूरी होगा। वैश्विक नियमों के अनुकूल योजनाओं के साथ साथ मजबूत निर्यात प्रोत्साहन व्यवस्था विभाग की योजनाओं में मुख्य रूप से शामिल है।

इसके अलावा निर्यात अवसर तलाशने के लिए प्रमुख भागीदार देशों के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं बरकरार रखे जाने का भी सुझाव दिया गया है, जिनमें अमेरिका और यूरोपीय संघ भी शामिल हैं। राजस्व में अहम योगदान देने वाले टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सामान और रत्न जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बड़ी गिरावट का मतलब है कि भारत का निर्यात नवंबर तक लगातार चार महीनों तक कमजोर रहा। साथ ही लगातार 6 महीनों से आयात में भी कमी आई है जो अर्थव्यवस्था में लगातार कमजोरी का संकेतक है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि डीपीआईआईटी ने स्थानीय स्तर पर व्यवसाय करने की प्रक्रिया को आसान बनाए जाने का भी लक्ष्य रखा है और कहा है कि वह इस संबंध में राज्यों और अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ भागीदारी करेगा। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

## बीएस सूडोकू 3631

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 2 | 3 | | 4 | | | |
| 5 | | 8 | | | | 4 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | | | 5 | | 9 | | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | | | | 9 |
| | | 6 | 9 | | 1 | 3 | | |
| 7 | | | | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| 2 | | 5 | | 3 | | | 4 | 1 |
| 1 | 8 | 9 | | | | 2 | | 6 |
| | | | 1 | | 2 | 5 | | 8 |

**कैसे खेलें?**
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

**बहुत आसान**
★☆☆☆☆

परिणाम संख्या 3630

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 |
| 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 |
| 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 |
| 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |

# जीएसटी परिषद की वोटिंग में दूसरों के भरोसे भाजपा

**इंदिवजल धस्माना**
नई दिल्ली, 5 जनवरी

पार्टी का 15 राज्यों पर नियंत्रण है जो किसी निर्णय की मंजूरी के लिए जरूरी 75 प्रतिशत मतदान की तुलना में कम है

**वस्तु** एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में निर्णय के संबंध में यदि मतदान हुआ तो भाजपा के लिए बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (अन्नाद्रमु) जैसी पार्टियों को राजी करने की चुनौती होगी।

18 दिसंबर को हुई बैठक में लॉटरी पर जीएसटी दरों के निर्धारण के लिए परिषद में मतदान का सहारा लिए जाने के बाद अब परिषद में मतदान असंभव नहीं दिख रहा है। इस बैठक में ज्यादतर मत राज्य और निजी लॉटरियों दोनों पर 28 प्रतिशत की एक समान कर दर के पक्ष में पड़े थे।

परिषद ने इससे पहले इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए वोटिंग का सहारा कभी नहीं लिया था। दरअसल, जीएसटी कानून के तहत वोटिंग के लिए प्रावधान को इस बैठक से पहले शैक्षिक दिलचस्पी वाले विषय के तौर पर देखा गया था। खेतान ऐंड कंपनी में पार्टनर अभिषेक रस्तोगी ने कहा, 'एब कार वोटिंग के विकल्प का इस्तेमाल किए जाने से राज्यों को भुगतान की कम दर जैसे विवादास्पद मुद्दों के लिए भी वोटिंग का सहारा लिए जाने की संभावना बढ़ गई है।'डेलॉयट इंडिया में पार्टनर एम एस मणि ने कहा कि यदि परिषद की बैठक में निर्णय सभी राज्यों की सहमति के साथ लिए जाएं तो बेहतर होगा, जैसा कि पिछले समय में देखने को मिला है।

किसी निर्णय को मंजूरी दिलाने के लिए, कम से कम 75 प्रतिशत वोटिंग जरूरी है। सामान्य स्थिति में, जब राज्य और केंद्र किसी मुद्दे पर वोटिंग करते हैं, केंद्र सरकार निर्णय को रोक सकती है। वैकल्पिक तौर पर, यदि 12 राज्य एकजुट होते हैं तो वे भी किसी निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।

केंद्र को निर्णय लेने के लिए 19 राज्यों के समर्थन की जरूरत है। शेष शक्तियां केंद्र के पास होने से इसका एक-तिहाई मतों का योगदान है और राज्य शेष भागीदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

30 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को देखते हुए प्रत्येक राज्य (आकार कोई भी हो) का 2.22 प्रतिशत वोटिंग अधिकार है। इसका मतलब है कि अपनी आबादी के आंकडों में बड़े अंतर के बावजूद उत्तर प्रदेश और गोवा वोटिंग ताकत के समान प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार 29 राज्यों में है, जिनमें एक (जम्मू-कश्मीर) में राष्ट्रपति शासन के अधीन है। यदि वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, बीजद और अन्नाद्रमुक जैसी भाजपा की सहयोगी पार्टियों पर विचार करें तो भाजपा को जीएसटी में वोटिंग के मुद्दे पर 21 राज्यों का साथ मिल सकता है। इसका मतलब है कि उसे किसी निर्णय को मंजूरी देने के लिए इन पार्टियों का समर्थन हासिल करने की जरूरत होगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 275

# विश्वसनीय हो बजट

**उभरती** आर्थिक परिस्थितियां बजट की तैयारियों में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काम काफी मुश्किल बनाती जा रही हैं। महीने भर से भी कम समय में उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करना है। इसी दौरान वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बीपीसीएल, भारतीय कंटेनर निगम और एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री को चालू वित्त वर्ष में पूरा कर पाने की संभावना कम है। सरकार को बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से 56,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी। ऐसे में रणनीतिक बिक्री पूरी नहीं होने पर इस वर्ष का विनिवेश लक्ष्य काफी दूर रह जाएगा जिससे सरकारी वित्त पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

लेकिन विनिवेश ही इकलौती समस्या नहीं है। सरकार का कर राजस्व भी इस साल कम रहने के आसार हैं। वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में ही राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 115 फीसदी पहुंच चुका था। और कर प्रवाह सुस्त रहने से वित्त वर्ष के बाकी बचे महीनों में भी हालात में बहुत सुधार हो पाना मुश्किल होगा। मसलन, अग्रिम कॉर्पोरेट कर संग्रह दिसंबर तिमाही में ही 5.2 फीसदी गिर गया है। भले ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह दिसंबर में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा लेकिन यह अंतिम चार महीनों के लिए निर्धारित 1.1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से कम ही था। इस तरह राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसदी पर सीमित रखने के लिए सरकार को या तो अपने खर्चों में बड़ी कटौती करनी होगी या फिर भुगतान को टालना होगा। विश्लेषक यह मान रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि के अनुमान से कम रहने से सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर जाएगी। लिहाजा इस तरह के हालात में सभी हितधारकों की नजर आगामी बजट में कम-से-कम तीन बड़ी बातों पर रहेगी।

पहली, सरकार से अपेक्षा होगी कि वह अर्थव्यवस्था का ईमानदार आकलन पेश करने के साथ ही उसे दोबारा पटरी पर लाने की योजना भी रखे। इस समय अर्थव्यवस्था की अवास्तविक तस्वीर पेश करने से सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित होगी और आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए कड़े फैसले लिए जाने की संभावना भी कम होगी। दूसरी, बजट से यह साफ हो जाएगा कि सरकार किस हद तक राजकोषीय उपायों से अर्थव्यवस्था को संभालने की मंशा रखती है? उसे अपने विकल्प बहुत सोच-समझकर चुनने चाहिए। तीव्र सुस्ती को राजकोषीय घाटे के अनियंत्रित विस्तार का लाइसेंस नहीं माना जा सकता है। सरकार कम समय के लिए भी अपने वित्त को लेकर लापरवाह नहीं नजर आ सकती है। इसके अलावा बजट को वर्ष 2018-19 के बारे में वास्तविक राजस्व स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि गत जुलाई में पेश बजट के संशोधित अनुमान सही तस्वीर नहीं पेश कर पाए थे। अब वक्त आ गया है कि सरकार राजकोषीय समस्या को स्वीकार करे और अपने वित्त की पारदर्शी तस्वीर पेश करे। व्यय को लंबित रखना या अपनी देनदारियां सार्वजनिक इकाइयों पर डालना हमेशा नहीं चल सकता है।

तीसरी बात, सरकार से राजकोषीय मजबूती का एक विश्वसनीय रोडमैप पेश करने की अपेक्षा होगी। काफी हद तक यह अर्थव्यवस्था के भरोसेमंद आकलन पर निर्भर करेगा। मसलन, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यह मानकर चलती है कि वर्ष 2020-21 और 2024-25 के बीच वार्षिक नॉमिलन वृद्धि 12.2 फीसदी रहेगी। अगर मुद्रास्फीति को चार फीसदी भी मानें तो इसका यही अर्थ है कि खुद सरकार अर्थव्यवस्था के सही मायनों में आठ फीसदी से थोड़ा अधिक दर से बढ़ने की उम्मीद कर रही है। राजकोषीय स्थिति के बारे में ऐसी धारणाएं बाजार को कमजोर बनाएंगी और बजट अवास्तविक एवं कम विश्वसनीय हो जाएगा। सरकार ने सही परिप्रेक्ष्य तय करने का मौका गत जुलाई में गंवा दिया था और अब उसे एक और मौका नहीं गंवाना चाहिए।

अजय मोहंती

# केजरीवाल ने दिया दशक का सियासी स्टार्टअप

## भारतीय राजनीति में जाति, समुदाय, विचारधारा, वंश की बाधाएं लांघकर आम आदमी पार्टी पूरे भारत में पहचान वाली दिल्ली की पार्टी बन गई है

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

यह स्टार्टअप का दशक रहा है। सैकड़ों नए स्टार्ट अप आए हैं और दर्जन से ज्यादा स्टार्टअप कुछ ही समय में 'यूनिकॉर्न' (1 अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन) का रुतबा हासिल कर चुके हैं। लेकिन हम राजनीति की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे हिसाब से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) बीते दशक की राजनीतिक स्टार्टअप कहलाई जाएगी। इसकी कई वजहें हैं।

हमारी राजनति में कदम रखते ही स्थापित राजनीतिक पार्टियों और ठोस वोट बैंक तथा वंशावलियों वाली जाति-समुदाय-विचारधारा आधारित ताकतों के कारण कठिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जन संघ, स्वतंत्र पार्टी और जनता पार्टी से लेकर तेलुगू देशम, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम को भी अपनी विचारधारा, नेतृत्व, वोट बैंक या जातीय/सामुदायिक भरोसा पहले से स्थापित ताकतों से ही लेने पड़े।

आप एकदम अलग है। छोटे मगर प्रमुख राज्य में भी खुद को स्थापित करना और देश भर में पहचान कायम करना बड़ी बात है। आधिकारिक रूप से आप की स्थापना 26 नवंबर, 2912 को हुई थी। लेकिन इसका बीज 2010 के अंत में ही बो दिया गया था। उस वक्त कुल्हाड़ी पर पैर मारने में जुटे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) या कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूरी तरह तैयार नहीं थी। पार्टी की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में आने से पहले कुछ वक्त के लिए संभावना की एक खिड़की खुली थी।

केजरीवाल उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान से चमक रहे थे और माना जा रहा था कि वह भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। ध्यान रहे कि उसी साल राजनीतिक से लेकर अफसरशाही, मीडिया और कंपनियों तक सभी भरोसा और सम्मान खो रही थीं। राडिया टेप खुलासे ने हालत बदतर कर दी। इससे 'सब चोर हैं' वाली धारणा पैदा हो गई। कोई भी स्थापित पार्टी या नेता इस आक्रोश से बच नहीं सका। हर किसी को चोर मानने के बाद भारत ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा था, जो चोर नहीं था। उस मोड़ पर केजरीवाल और उनकी फौज आई, जिसे अभी तक सत्ता नहीं मिली थी और इसीलिए जो अब तक भ्रष्ट नहीं हुई थी।

उनकी जीवनशैली एकदम सामान्य थी, वे सरल भाषा में बात करते थे और भरोसेमंद लगते थे। उन्होंने स्थापित राजनीतिक और अभिजात वर्ग (मनमोहन सिंह से लेकर मुकेश अंबानी तक) को फटकारने, निंदा करने और भारत के भरोसे के नाकाबिल बताने के अलावा कुछ नहीं किया। अन्ना हजारे ने उनकी ताकत और भी बढ़ा दी।

अन्ना को दो साल के भीतर इस्तेमाल कर फेंक दिया गया (उनका अनशन 2011 में हुआ था) और 2012 में आप का उदय हो गया। पिछले कई दशकों में यह पहली नई राजनीतिक पार्टी थी, जिसकी कोई राजनीतिक विरासत, वोट बैंक, वंश या विचारधारा नहीं थी। नई पार्टी न तो वामपंथी थी, न दक्षिणपंथी और न ही मध्यमार्गी। इसीलिए वह किसी भी पार्टी पर उसकी विचारधारा को लेकर हमला कर सकती थी या किसी के भी साथ आ सकती थी और बाद में उससे किनारा कर सकती थी। उसने दिल्ली में कांग्रेस से लेकर पंजाब में सिख चरमपंथियों तक के साथ ऐसा किया। विचारधारा और राजनीतिक निष्ठा के नाम पर सिफर, दोस्तों और दुश्मनों को इस्तेमाल कर फेंक देने की आदत, राष्ट्रवाद के मुलम्मे में लिपटे कल्याण (भारत माता की जय और भगत सिंह की तस्वीरें उनकी पार्टी की पहचान बन गईं) को इस्तेमाल करने का हुनर ही राजनीतिक उद्यमशीलता में केजरीवाल की महारत है। वह सियासत के बाजार में घुस रहे थे, लेकिन उनके हाथ में ऐसा सामान था, जिसे वह हर सामान से अलग बता रहे थे। यही असली उद्यमशीलता होती है।

किसी भी स्टार्टअप की तरह आप के सामने भी ऐसे मौके आए, जब लगा कि वह खत्म हो जाएगी और इनमें से कुछ आफत उसने खुद मोल ली थीं। 2019 के लोकसभा चुनावों में दुर्गति को ही ले लीजिए, जब दिल्ली के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में यह पार्टी कांग्रेस से भी पिछड़कर तीसरे नंबर पर रह गई थी। उस वक्त आप को खत्म बता दिया गया था, लेकिन यह पार्टी वापसी कर अब दिल्ली चुनावों में सबसे आगे लग रही है।

मगर स्टार्टअप की तरह आप के साथ भी मानव संसाधन (एचआर) की दिक्कतें लगी रही हैं। बल्कि उसकी हालत स्टार्टअप से भी बुरी है क्योंकि मंत्रियों समेत कई प्रमुख लोगों को भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर सहमति भरे मगर विवाहेतर यौन संबंधों की सीडी सामने आने पर पार्टी से निकालना पड़ा है। स्टार्टअप की ही तरह इसे भी कई सह-संस्थापक छोड़ गए हैं।

मुझे लगता है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण केजरीवाल के लिए वैसे ही थे, जैसे मार्क जुकरबर्ग के लिए विंकलववॉस बंधु हैं। आप के भीतर स्टार्टअप की एक और फितरत आ गई है, जो कभी-कभी स्टार्टअप को तबाह भी कर देती है और वह है एक ही नेता का सर्वशक्तिमान बन जाना।

मेरे कहे या लिखे पर ध्यान देने वाले जानते हैं कि आप की राजनीति पर मुझे अक्सर संशय रहता है। अन्ना आंदोलन के समय से ही आप के नेताओं से मेरी बहस होती रही है। उनकी विचारधारा ढूंढते हुए मैंने केजरीवाल की चर्चित किताब स्वराज पढ़ी। पर्चे के आकार की यह किताब मैंने बेंगलूरु से दिल्ली आते वक्त उतनी देर में ही खत्म कर दी, जितनी देर में हमारा विमान भोपाल के आसमान में पहुंच पाया था। इसमें ढाई सहस्राब्दियों में हुए किस्सों से मिले विचारों और आदर्शों का घालमेल है। मुख्य विचार प्राचीन काल के लोकतांत्रिक कहे जाने वाले वैशाली साम्राज्य से आया है।

यह विचार इतना बचकाना था कि मैंने उस पर 'अरविंद चित्र कथा' शीर्षक से लेख ही लिख डाला। मैंने लिखा था कि अगर वे देश और 'तंत्र' को इसी तरह बदलना चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस बात के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए कि सत्ता में आने के बाद धीरे-धीरे वे शांत हो गए। अब आप उन्हें किसी को गाली देते, मोर्चे निकालते या गुस्सा करते कम ही देखेंगे। वे कानून और संविधान का पालन करते हैं, शांति से काम करते हैं और उन्होंने अपना विचारधाराहीन तथा निचले तबके के कल्याण का खाका तैयार कर लिया है। आलोचकों को यह बदलाव तथा सफलता स्वीकार करनी होगी।

केजरीवाल की तुलना उन्हीं की उम्र के दूसरे नेता राहुल गांधी से कर लीजिए। मैं केवल यह देखूंगा कि मोदी के उभार के बाद से हमारी राजनीति में आई तीन बड़ी चुनौतियों - राष्ट्रवाद, धर्म और कल्याणकारी विचारधारा - पर दोनों की प्रतिक्रिया कैसी रही है। जब जेएनयू में संघर्ष चल रहा था तो राहुल वहां गए, लेकिन केजरीवाल बिल्कुल नहीं गए।

केजरीवाल ने चतुराई से खुद को 'टुकड़े-टुकड़े' वाले बवाल से दूर रखा। याद कीजिए कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद के गिरफ्तार होने पर उन्होंने क्या कहा। केजरीवाल ने कहा कि अगर पुलिस उनके नियंत्रण में होती तो 'टुकड़े-टुकड़े' के नारे लगाने वाले जेल में होते और बेगुनाह बाहर होते। केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की फौरन सराहना की तथा अनुच्छेद 370 के पक्ष में बोले। उन्होंने राष्ट्रवाद को मोदी के हाथ में नहीं जाने दिया और भगत सिंह तो हमेशा से सावरकर के मुकाबले ज्यादा ताकतवर शख्सियत हैं ही।

जब राहुल मंदिर-मंदिर भटक रहे थे तब केजरीवाल ने खामोशी के साथ अपनी हिंदू पहचान बरकरार रखी और धर्मनिरपेक्ष शुद्धता की वामपंथी बुद्धिजीवियों की मांग के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा भी शुरू कर दी। तीर्थ स्थलों में अजमेर शरीफ भी था, लेकिन ज्यादातर हिंदू और सिख तीर्थ स्थल थे। योजना के विज्ञापन में भी आदर्श बेटे श्रवण कुमार की तस्वीर थी, जिसने अपने बूढ़े माता-पिता को कंधे पर टांगकर 84 हिंदू तीर्थ घुमाए थे। लेकिन उसी वक्त हिंदू दक्षिणपंथियों के विरोध के बीच उन्होंने टीएम कृष्णा कंसर्ट भी आयोजित कराया। बाद में उन्होंने पटाखों के बजाय लेसर किरणों वाला दीवाली मेला भी किया।

हमें पता है कि दिल्ली का चुनाव जीतने पर भी ब्रांड केजरीवाल-आप को लंबा सफर तय करना होगा। लेकिन वह लचीली राजनीति वाली स्थापित पार्टी बन गई है। हम कभी उससे सहमत होंगे और अक्सर असहमत होंगे, लेकिन उसकी ताकत को मोदी भी अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि वह अपने कद से बड़े काम करती रहेगी। हमें पता है कि एक दशक में केवल एक राज्य में दबदबा कायम करना स्टार्टअप की भाषा में हल्की उपलब्धि कही जाएगी। लेकिन देश विशेषकर भारत की राजनीति में एक दशक बहुत छोटा वक्त है।

# लोगों की गतिविधियों पर तकनीक से निगरानी पर विवाद और चिंता

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

**नागरिकता** संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर देश में मचे घमासान ने सबका ध्यान 'फेस रिकग्निशन' तकनीक की तरफ खींचा है। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल कर लोगों की तस्वीरें ली हैं और उसके बाद फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भीड़ में लोगों की शिनाख्त करने के लिए किया है। इस पूरे मामले से लोगों की गतिविधियों पर निगरानी से संबंधित राज्य के लगभग असीमित अधिकार चिंता का सबब बन गए हैं।

भारत में जल्द ही सबसे बड़ा फेशियल रिकग्निशन सूचना भंडार (डेटाबेस) तैयार होने वाला है। जून में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने डेटाबेस तैयार करने में मदद के लिए सहयोग मांगा था। एनसीआरबी की निविदा के अनुसार, 'इस प्रणाली के तहत पुलिस को एक वास्तविक माहौल में त्वरित एवं सटीक फेस रिकग्निशन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।' एनसीआरबी का कहना है कि इससे लापता हुए लोगों की पहचान करने में मदद मिलेगी। एनसीआरबी के अनुसार फेस रिकग्निशन तकनीक आधार से नहीं जोड़ी जाएगी। आधार में तस्वीर सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारियां भी होती हैं।

एनसीआरबी ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को एक लिखित जवाब में कहा कि जब तक कोई अपराध नहीं होता है तब तक प्रणाली सार्वजनिक जगहों से सीसीटीवी फुटेज नहीं लेगी। डेटा एक केंद्रीकृत ऐप्लीकेशन में रखा जाएगा और केवल पुलिस की इस तक पहुंच होगी। इसमें कोई शक नहीं कि विरोध प्रदर्शन के बाद ऐसी तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। इस बात को लेकर सभी अटकलें लगाएंगे कि एनसीआरबी ऐसी सूचनाएं दूसरे डेटाबेस जैसे 'आधार' आदि से नहीं जोड़ने का अपना वादा पूरा करेगा या नहीं। डेटाबेस के अलावा सीसीटीवी सार्वजनिक जगहों और बंद जगहों पर निगरानी के लिए मुस्तैद हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि आम दिनों में भी आपकी छवि एवं गतिविधियां विभिन्न सीसीटीवी कैमरों में कैद की जा रही हैं और कई संगठन आपके आंकड़ों का भंडारण और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस यातायात उल्लंघन पर जुर्माना जगाने के लिए पहले से ही सीसीटीवी में कैद तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है।

किसी लोकतांत्रिक देश में महत्त्वाकांक्षी निगरानी कार्यक्रम को निर्धारित सीमा का अतिक्रमण माना जाएगा। इस प्रणाली में लोगों की बिना अनुमति से उनके निजी व्यक्तिगत डेटा लिए जाएंगे। भारत के प्रस्तावित निजी डेटा सुरक्षा विधेयक (पर्सनल डेटा प्रोटेक्शनन बिल) में इससे सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है। यह विधेयक संसद में पारित भी नहीं हुआ है। इस विधेयक में बिना अनुमति के सरकारी एजेंसियों एवं संगठनों को डेटा जुटाने एवं इनका इस्तेमाल करने की खुली छूट होगी। इस विधेयक के वास्तविक मसौदे में इस बात का जिक्र था कि सरकारी एजेंसियां आवश्यक होने पर ही लोगों की सहमति के बिना डेटा का संग्रह करेंगे। दिसंबर के शुरू में लोकसभा में जारी मसौदे से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। कुल मिलाकर इसका यह मतलब हुआ कि अगर यह विधेयक पारित हो गया तो सरकार की निगरानी से सुरक्षा के उपाय नाम मात्र के होंगे। डिजिटल तस्वीर ऐसी चीज है, जो लोगों की अनुमति के बिना आसानी से प्राप्त की जा सकती है। यूरोप में इसे निजी व्यक्तिगत डेटा (निजी पर्सनल डेटा) के तौर पर माना गया है और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन के प्रावधान 'राइट टू फॉरगेट' का इस्तेमाल कर ऐसे सूचनाएं हटाने के लिए कहा जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 के तहत ऐसा आग्रह किया जा सकता है या नहीं, हालांकि इस विधेयक में 'राइट टू फॉरगेट' का प्रावधान जरूर है।

फेस रिकग्निशन तकनीक कई तरह के होती हैं। उदाहरण के लिए वन ऑफ मैचिंग सिस्टम्स जैसे लैपटॉप या मोबाइल उपकरण किसी व्यक्ति का डिजिटल फोटो का भंडारण करता है और लॉग इन के समय यूजर के चेहरे से इसका मिलान करता है। वन वर्सस फ्यू सिस्टम किसी संगठन में कर्मचारियों का छोटा डेटाबेस तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती है। इन दोनों मामलों में लोगों की सहमति ली जाती है और यह सहमति वापस भी ले सकती है। कई ऐसे मामले भी होते हैं, जिनमें पुलिस किसी व्यक्ति की तस्वीर का मिलान एक बड़े डेटाबेस से करते हैं। इसी तरह, पुलिस भीड़ की फोटो लेती है और प्रत्येक चेहरे का मिलान बड़े डेटाबेस से करते हैं। इनमें किसी भी मामले में सहमति या जानकारी नहीं होती है।

आधुनिक फेशियल रिकग्निशन कार्यक्रमों से बच निकलना आसान भी नहीं है, लेकिन कुछ चूक होने की गुंजाइश तो रह ही जाती है। एयर फिल्टर मास्क आधुनिक फेस रिकग्शिन प्रणाली को उलझन में नहीं डाल सकता है। मेक-अप आदि से चेहरा छुपाया जा सकता है, लेकिन यह भी आसानी से पकड़ में आ जाएगा। स्कार्फ या इयररिंग्स या किसी व्यक्ति के वास्तविक चेहरे के इर्द-गिर्द पहनी गई कोई चीज और चेहरे की शक्ल की तरह लगने वाली छवि सॉफ्टवेयर को धोखे में डाल सकती है।

फेस रिकग्निशन तकनीक और निगरानी के लिए सरकार द्वारा इसका इस्तेमाल विवाद का विषय है। विभिन्न देशों में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें तकनीकी खामी है। उदाहरण के लिए तकनीक के धोखा खाने से निर्दोष व्यक्ति भी परेशानी में फंस सकते हैं। इन तकनीकों की सीमाएं या संभावनाएं जानने, समझने या इनके इस्तेमाल को समझने में न्यायालय एवं न्यायाधीश भी गच्चा खा सकते हैं। हालांकि भारत में बड़े पैमाने पर ऐसी निगरानी तकनीकों का इस्तेमाल होगा और डेटा सुरक्षा विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यह पूरी तरह कानूनी एवं व्यापक होगा।

## कानाफूसी

### अब बलि की बारी!

झारखंड में कई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं पर गाज गिर सकती है। पहला नंबर ओम माथुर का हो सकता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन चुनाव के बाद राज्य के मुख्यमंत्री तक को अपनी सीट गंवानी पड़ी। ऐसा लगता है कि रघुवर दास की हरेक राजनीतिक चाल को माथुर को स्वीकृति हासिल थी, जिनमें सरयू राय को तवज्जो नहीं देना भी शामिल था। राय ने पूर्व मुख्यमंत्री दास को भारी मतों से पटखनी दी है। ऐसी खबरें हैं कि दास ने माथुर से कहा था कि राय को 10,000 से अधिक वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा और दास को अपनी सीट 76,000 से अधिक मतों से गंवानी पड़ी। चुनाव नतीजे आने से पहले भाजपा ने 500 किलोग्राम लड्डू के ऑर्डर दिए थे, लेकिन उनका भोग कहां लगा यह किसी को मालूम नहीं है।

### नेताओं की नाराजगी!

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई वरिष्ठ नेता इन दिनों अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। दरअसल उनकी शिकायत है कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि पार्टी में आए नए लोग टेलीविजन कैमरों पर भाजपा के नए चेहरे बनते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हरेक व्यक्ति टीवी पर दिखना चाहता है, लेकिन यह मुनासिब नहीं है। भाजपा उन लोगों को आगे कर अधिक से अधिक लाभ हासिल करना चाहती है, जो अपनी पुरानी पार्टी की जमकर निंदा कर सकते है। भाजपा के कुछ नए प्रवक्ताओं में गौरव भाटिया (पहले समाजवादी पार्टी में), टॉम वडक्कन (कांग्रेस के पूर्व नेता और भाजपा में आने से पहले गांधी परिवार के वफादार) और बैजयंत जय पांडा (बीजू जनता दल के पूर्व नेता) इन दिनों टीवी पर बहस में भाग लेते देखे जा सकते हैं। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इन लोगों की जगह लेना चाहते हैं, लेकिन उनमें टीवी पर दिखने वाला पैनापन नहीं है। पांडा संभवत: एक अपवाद हो सकते हैं, जिन्होंने नोटबंदी, जीएसटी क्रियान्वयन और सुस्त अर्थव्यवस्था के बाद मोदी सरकार का तब बचाव किया था जब वह बीजद का हिस्सा थे। इस बारे में पूछने पर वह मजाकिया लहजे में कहा करते थे कि उनका नाम ही सारे सवालों का जवाब है। उनका नाम बीजेपी (बैजयंत जय पांडा) है।

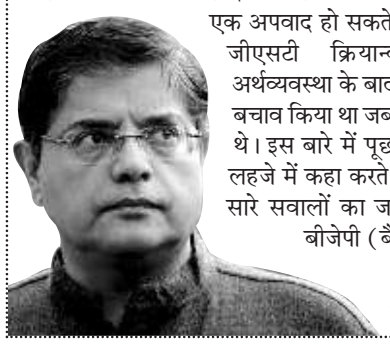

बैजयंत जय पांडा

## आपका पक्ष

### जलवायु परिवर्तन की समस्या बड़ी नहीं

जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरे देश के सामने एक चुनौती के रूप में बनकर उभर रही है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार अगर हमें अपनी धरती को बचाना है तो इसका तापमान 1.5 सेल्सियस कम करने की जरूरत है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब कुछ देश जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसका निराकरण तभी संभव है जब विश्व के सभी देश इस समस्या से निपटने के लिए एकजुट हो जाएं। हमें यह लगता है कि आज के दौर में मनुष्यों में इतना तर्कवाद बढ़ गया है कि हर चीज को भौतिक संसाधनों और उपभोग की वस्तु समझकर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या इतना तर्कवादी होना तथा अध्यात्म को महत्त्व नहीं देना देशहित में होगा। अगर हम प्राचीन युग को ही समझने का प्रयास करें तो ये बातें साफ जाहिर होती हैं कि उस युग में मनुष्य जिस चीज से डरते थे उसकी पूजा करते थे। लेकिन आज के दौर में हम इतने निडर हो गए हैं कि अध्यात्म को बिल्कुल महत्त्व नहीं दे रहे हैं। आज हम धरती को माता के स्थान पर सुख तथा मनुष्य की उपभोग की वस्तु मानने लगे हैं। अगर धरती को माता मानकर इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

*सुप्रिया कुमारी, पटना*

**जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होना चाहिए**

सच में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निजात पाना है तो बढ़ते आधुनिकीकरण के दौर में तर्कवाद के साथ-साथ अध्यात्म को स्थान दिया जाना चाहिए।

### मुफ्त नहीं, हर हाथ को मिले रोजगार

देश में किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) को वरदान बताते हुए समय-समय पर इसकी मांग उठती रही है। लेकिन आरक्षण और भ्रष्टाचार के कारण यूबीआई योजना का भी हर जातिवर्ग के बेरोजगारों को फायदा नहीं होगा। सरकार को इसे हरी झंडी देने से पहले इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कहीं यह देश के विकास की रफ्तार पर विपरीत असर नहीं डाल दे। देश में लोग काम से ज्यादा आराम को तवज्जो देते हैं, सरकार से मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं की उम्मीद रखते हैं, काम से जी चुराते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कमाई को नशे या दूसरे गलत कामों में खर्च करते हैं। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से बिना मेहनत किए आमदनी मिलने लगे तो यह नकारात्मक प्रभाव डालेगी। जो किसान अपनी फसल की पैदावार के लिए मजदूरों का सहारा लेते हैं अगर उन मजदूरों को सरकार की तरफ से आमदनी मिलनी शुरू हो जाएगी तो क्या मजदूर अपने काम के लिए ज्यादा समय देंगे। कुछ रिक्शेवाले जब एक दिन में अच्छी कमाई अगर कुछ घंटों में कमा लेते हैं तो वे अपना रिक्शा चलाना बंद कर आराम फरमाने लग जाते हैं। सरकार को चाहिए कि वह मुफ्त की आमदनी देने के बजाय देश के हर हाथ को रोजगार मुहैया कराए। मेहनत करने वालों की आमदनी बढ़ाए, महंगाई कम करने के उपाय करे। निजी क्षेत्र में रोजगार करने वालों पर ध्यान दे। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए गंभीरता दिखाए।

*राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

# धीमी पड़ती सुधार की रफ्तार, उम्मीद जगाए सरकार

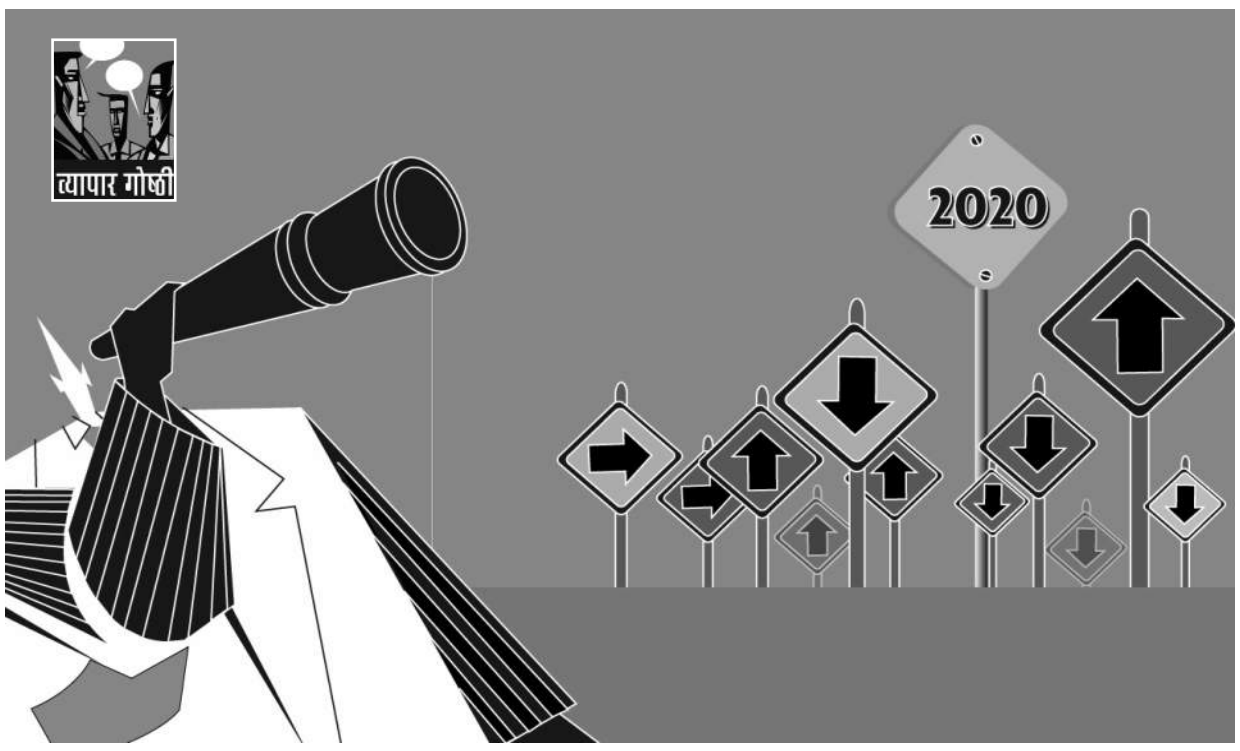


अजय मोहंती

## कई मोर्चों पर सुधार की उम्मीद

वैश्विक सुस्त सुस्त मांग से देश का निर्यात आंकड़ा वर्ष 2019 में ज्यादातर समय गिरावट में रहा। निर्यातकों के लिए तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी सुविधा, वस्तु निर्यात इंडिया स्कीम (एमईआईएस) की सरकारी पहल से उम्मीद है कि वर्ष 2020 में निर्यात सुधरेगा। वर्ष 2019 के दौरान उठाए गए सुधारात्मक कदमों की बदौलत नए साल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 40 से 50 फीसदी बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा जिन विदेशी कंपनियों के भारत में कारखाने हैं, उनके लिए ई-कॉमर्स मानदंड भी उदार बनाए गए हैं। नए साल में दालों का बफर स्टॉक बनाने में मदद मिलेगी।

**सुधीर कुमार सोमानी**
देवास, मध्य प्रदेश

## आर्थिक प्रयोग से दूरी बनाए सरकार

वर्ष 2019 निराशाजनक रहा। सरकार ने बीते वर्ष बहुत से बदलाव किए। उम्मीद यह है कि सरकार की ओर से किए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के निवेश का अनुकूल परिणाम सामने आए। साथ ही रियल एस्टेट में सक्रियता कारोबार को नए आयाम पर पहुंचा सकती है। महंगाई और आर्थिक सुस्ती की मार से उबरने के लिए तथा आर्थिक स्थिति को सामान्य स्तर पर लाने के लिए सरकार को अभी नए प्रयोगों से दूर रहना चाहिए। न केवल निवेशक अपितु हर तबका सबके लिए 2020 एक सौगात बन के आए। इसके लिए आर्थिक मोर्चे पर सबको सजग और आशावादी होना होगा।

**डॉ. रसिकेश 'नवजात'**
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

## चुनौतियों भरा होगा नया साल

नए साल से उम्मीदें रखकर आर्थिक और कारोबारी क्षेत्र में वृद्धि की ओर अग्रसर होकर आशातीत सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। विगत वर्ष व्यापार आर्थिक मंदी के कारण बेपटरी रहा। मंहगाई के निरंतर बढ़ते रहने से जनाक्रोश नए साल की दस्तक के साथ और बढ़ गया। बिना कटे ही प्याज ने जो आंसू निकाले वे अभी पोछे भी नहीं जा सके थे कि रसोई गैस, पेट्रोल व रेल किराये की वृद्धि ने जनवरी की भरी सर्दी में पसीने छुड़ा दिए। जिस साल का आगाज ही ऐसा है तो अंजाम खुदा जाने। ये सब आर्थिक व कारोबारी क्षेत्र के लिए वर्ष पर्यंत कष्ट देने वाली स्थिति बनाए रखेगा। सरकार को नए साल में आर्थिक मंदी, मंहगाई व बेरोजगारी से निपटने के प्रयास करने होंगे।

**प्रदीप माथुर**
अलवर, राजस्थान

## अर्थव्यवस्था के लिए आसान नहीं साल

कुछ घरेलू स्तर पर तो कुछ वैश्विक स्तर पर आए ठहराव और गतिरोध की वजह से वर्तमान में अर्थव्यवस्था के समक्ष तमाम तरह की चुनौतियां हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद संघर्ष कर रही है और अर्थव्यवस्था पिछले छह साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों उपभोग, निवेश और निर्यात में हालात चिंताजनक हैं। अब सुधार मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के बरतावों पर निर्भर है। अगले बजट में अगर व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती होती है तो मध्य वर्ग को राहत मिल सकती है। ब्रेक्जिट, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध जैसे हालात भी अर्थव्यवस्था पर असर डालेंगे। कुल मिलाकर आने वाला साल अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने जा रहा है।

**नृपेंद्र अभिषेक नृप**
छपरा, बिहार

## मंदी से उबरने की उम्मीद

नए साल के लिए इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब लगातार और निर्णायक तौर पर मंदी के खिलाफ कदम उठाती दिख रही है। मंदी का असर सभी जगह कम या ज्यादा महसूस हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि स्थिति इतनी भयावह भी नहीं है कि अर्थव्यवस्था पर भारी संकट मंडराने लगे। यह जरूर है कि जो उद्योग बंद हुए या जिनके रोजगार छिने, उनके लिए संकट खड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि मंदी के आधार को नया विस्तार मिले, इससे पहले ही सरकार पूरी तरह सक्रिय होती दिखाई दे रही है। मंदी का असर हमें अचानक ही दिखने लगता है लेकिन इससे निपटने के लिए उठाए गए कदम धीरे धीरे असर दिखाते हैं। यह सब के लिए धैर्य धारण करने का समय है।

**अजीत कुमार गौतम**
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

## उत्साहजनक स्थिति नदारद

नए साल में आर्थिक व कारोबारी उम्मीदों को लेकर कोई उत्साहजनक टिप्पणी करना निरर्थक होगा क्योंकि इनके लिए अपेक्षित कोशिशें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। सकल घरेलू उत्पाद के मोर्चे पर केंद्रीय वित्त मंत्री 6.5 फीसदी की उम्मीद कर रहीं हैं मगर उम्मीद से बात बनने वाली नहीं है। इस दिशा में वह कोई ठोस कदम उठाने की स्थिति में नहीं हैं। इस समय देश के कार्पोरेट क्षेत्र में दिशाहीनता और मात्र हवा में सपने लहराने की स्थिति है जिससे निवेशकों के सपने ध्वस्त हुए हैं और नियोजकों में असंतुष्टि का भाव चरम पर है। आर्थिक और कारोबारी उम्मीदें तभी फलीभूत होंगी जब इनके लिए सियासी पुट वाले आर्थिक निर्णय की प्रथा समाप्त कर वास्तविक आर्थिक कदम उठाए जाएंगे।

**राजा दुबे**
भोपाल, मध्य प्रदेश

## पटरी पर आ रही अर्थव्यवस्था

व्यापार के लिहाज से नया साल उम्मीदों से भरा होना चाहिए। जीएसटी की दरों को सरकार ने कम किया है जिस कारण से व्यवसाय को नई दिशा मिली है। सरकार के स्तर पर हर संभव बदलाव किए जा चुके हैं। अब इसके सकारात्मक परिणाम आने हैं। मोदी सरकार के बहुत से निर्णय त्वरित लाभ या हानि के तराजू पर नहीं बल्कि दूरदर्शी माना जाना चाहिए। भले ही नोटबंदी से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी पर इसकी वजह से बहुत से ऐसे धन का भंडाफोड़ हुआ जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा था। जीएसटी की दरें पहले असमान थी पर अब इसको विवेकपूर्ण माना जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व पटल पर हुए उठापटक की शिकार है वरना इन दिनों भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश है।

**डॉ राम हर्ष गुप्ता**
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

## खपत की चिंता रहेगी बरकरार

इस नव वर्ष में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की उम्मीद है। साल 2019 में आर्थिक सुस्ती के वजह से बाजार सुस्त पड़ चुके हैं। आर्थिक जानकारों की मानें तो साल 2020 की पहली तिमाही रोजगार के लिहाज से बहुत उत्साहजनक नहीं रहने वाली है। वास्तव में भारत की जीडीपी वृद्धि कमजोर है और इस स्थिति में कंपनियां कोई भी नया निवेश करने से बचती हैं। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों उपभोग, निवेश और निर्यात में हालात चिंताजनक हैं। अब सुधार मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के बर्तावों पर निर्भर है क्योंकि वैश्विक मांग की गिरावट के चलते निर्यात मंदा पड़ चुका है और निवेश के विभिन्न स्तरों पर तमाम तरह की चुनौतियां हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल में भी अर्थव्यवस्था में खपत की चिंता बरकरार रहेगी। खुदरा महंगाई आमजन के लिए चिंताजनक हो सकती है।

**उद्देश्य**
पटना, बिहार

## गलतियों का न हो दोहराव

नया साल उम्मीदों का साल होता है। पिछले साल पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि आर्थिक सुस्ती और बाजार ने हमें निराश ही किया पर हम यह भी जानते हैं कि ये तो होता ही रहता है और सुधारात्मक कदम उठाने से हम बाजार को फिर से गुलजार कर सकते हैं। इस साल हमें ऑटो, रियल एस्टेट, मनोरंजन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को और मजबूत करना होगा ताकि विकास दर को सुधारा जा सके। शेयर बाजार के निवेशक अपने निवेश को लेकर सशंकित न रहें, इसके लिए एक सुरक्षा का माहौल बनना चाहिए ताकि सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशक भी अपनी पूंजी को सुरक्षा के माहौल में विनियोग कर सके। नए साल में पिछले साल की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए।

**डॉ आंजनेय गुप्ता**
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

## नए साल से ढेर सारी उम्मीदें

गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों से जनता और कारोबारी जैसे तैसे उबर रहे थे कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की चपेट में भारत भी आ गया जिसका व्यापक प्रभाव रियल एस्टेट और वाहन उद्योग पर पड़ा और इन दोनों क्षेत्रों में फीकापन रहा। सरकार ने रियल एस्टेट को 25 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया ताकि निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाएं पूरी हो सकें। पीएसयू बैंकों में भी सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये डाले जिससे बैंक रियल एस्टेट और उद्योगों को कर्ज दे सकें। महंगाई को नियंत्रित करने के साथ ही विभिन्न वर्गों को करों में मिल रही छूट को बरकरार रखना चाहिए। आयकर दर का युक्तियुक्तकरण होना चाहिए।

**अनिल कोथुलकर**
इंदौर, मध्य प्रदेश

## सुधारात्मक रहेगा साल

देश की अर्थव्यवस्था अवस्फीति की स्थिति के साथ नव वर्ष में प्रवेश कर रही है और कुछ क्षेत्रों में महंगाई का दबाव भी बना हुआ है। 1 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को इस स्थिति से निपटना होगा। वैसे वर्ष 2020 में मंदी का प्रकोप कम होने की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि यह मंदी संरचनात्मक स्वभाव की नहीं है। वैसे भी अर्थव्यवस्था के मूल तत्व कमजोर नहीं है और हमारे पास करीब 4 अरब डॉलर का सुरक्षित विदेशी मुद्रा कोष है। नए वर्ष में भी खपत की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नए वर्ष में सरकार और आरबीआई द्वारा पिछले वर्ष उठाए गए कुछ कदमों के सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद की जा सकती है। वैश्विक स्तर पर व्याप्त मंदी के दौर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावहीन करने हेतु राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति में तालमेल जरूरी होगा।

**डॉ. एम एस सिद्दीकी**
फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

## कारोबार के मोर्चे पर मिलेगी सफलता

सरकार को नए वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में वृद्धि दर 6 से 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। सरकार मोटे तौर पर यह भी मान कर चल रही है कि देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में 4 फीसदी तक बदलाव हो सकता है। अभी देश की अर्थव्यवस्था सुस्त है और सरकार इससे निपटने के उपाय खोज रही है। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं और इस वर्ष मांग में तेजी रहेगी। साथ ही साथ इस वर्ष रियल्टी क्षेत्र में निवेश 5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इसमें विदेशी कंपनियों का योगदान अधिक रहेगा। वर्ष 2020 में जीएसटी संग्रह बढ़ने के साथ ही वाहन व मोबाइल क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन भी पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

**हरमोहन नीमा**
इंदौर, मध्य प्रदेश

## उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा

नव वर्ष अपेक्षाओं से अधिक समृद्धिशाली होगा। मोदी सरकार दूसरी पारी में पहली पारी की विवादास्पद आर्थिक विफलताओं की सुधारात्मक व्यवस्था कदम उठाएगी। इस दिशा में सुदृढ़ परिणाम हासिल करने के लिए आशातीत सकारात्मक प्रयास नजर आएंगे। फलत: आर्थिक विकास के साथ साथ अनेक ऐसी नीतियों को भी लागू किया जा सकता है, जो महंगाई कम करने में मददगार साबित हो। महंगाई पर नियंत्रण और विनिवेश की उदार नीतियों से विनिवेश बढ़ता है। इससे आर्थिक विकास में वृद्धि स्वभाविक है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक त्योहारों जैसे धनतेरस, दीवाली, शादी पर भी गत वर्ष की तुलना में कारोबार में आशातीत वृद्धि होगी। नया साल नई उम्मीदों का संचार करेगा। भारत की आत्मनिर्भरता तीव्र आर्थिक वृद्धि का सपना साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

**एम राज राकेश**
अलवर, राजस्थान

## जीएसटी पर सकारात्मक संकेत

आर्थिक सुस्ती के बीच साल 2020 के पहले दिन जीएसटी के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था को एक खुशखबरी मिली है। दिसंबर में जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा। त्योहारी सीजन और कानून का सख्त तरीके से पालन करने के चलते ऐसा हुआ। जीएसटी संग्रह धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में मददगार साबित होगा। लेकिन सरकार द्वारा किए गए कुछ बदलाव से उसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ सकता है। इन बदलावों से जनता को कहीं पर राहत मिलेगी तो कहीं पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

**कुमारी कबिता**
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

## बकौल विश्लेषक

### छोटे कारोबारियों को मिले राहत अर्थव्यवस्था सुधारने के हों उपाय

नए साल से कारोबार और आर्थिक मसलों पर बेहतरी की उम्मीद है क्योंकि बीता साल कारोबार के लिए बुरा रहा। आर्थिक सुस्ती से खासकर छोटे कारोबारियों को काफी परेशानी हुई। अब नए साल में सरकार को छोटे कारोबारियों को विशेष राहत देनी चाहिए। सरकार को अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार को छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सबसे पहले आम बजट में कॉरपोरेट क्षेत्र के उद्यमियों की तरह साझेदार फर्म के रूप में काम करने वाले कारोबारियों को भी कॉरपोरेट कर में कटौती करनी चाहिए। इन फर्म के साझेदारों के लिए वेतन के नियमों में बदलाव कर इसे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जीएसटी लागू होने के दो साल बाद भी कारोबारियों को इसके कुछ जटिल नियमों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को संपूर्ण जीएसटी व्यवस्था का सरलीकरण करना चाहिए। इसके तहत रिटर्न से लेकर सिस्टम की तकनीकी दिक्कतों को दूर कर तमाम अनुपालन सरलीकृत हों और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी न की जाए। आईटीसी दावे पर बंदिश को पहले से और सख्त कर दिया गया है, जिससे कार्यशील पूंजी अटकने के कारण अब बड़े कारोबारी छोटे कारोबारियों से माल खरीदना बंद कर सकते हैं। ऐसे में ये बंदिश हटनी चाहिए। साथ ही रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। सरकार को इस साल आयकर के लंबित एवं विवादित मामलों को निपटाने पर भी जोर देना चाहिए। छोटे कारोबारियों के लिए सहज और सस्ती दर पर कर्ज की व्यवस्था हो। खुदरा कारोबारियों को ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचने और उनके अन्य गलत क्रियाकलापों से परेशानी हो रही है। ऐसे में नए साल में सरकार से उम्मीद है कि वह ई-कॉमर्स के लिए नीति बनाकर खुदरा कारोबारियों के हितों की भी रक्षा करेगी। सरकार को इस वर्ष अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ाने के उपाय करने चाहिए जिससे जीडीपी में आ रही कमी को दूर कर इसे तेजी से बढ़ाया जा सके। बढ़ती महंगाई नियंत्रित करने के साथ उपभोक्ताओं की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएं जिससे उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति और कारोबारियों का कारोबार बढ़ेगा।

बातचीत: **रामवीर सिंह गुर्जर**

**हेमंत गुप्ता**
महासचिव, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल

### दिखेगा बेहतर आर्थिक परिदृश्य लेकिन चुनौतियां रहेंगी बरकरार

देश की आर्थिक स्थिति फिलहाल बेहतर स्थिति में नहीं है लेकिन साल 2020 की दूसरी छमाही से इसमें काफी सुधार देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके लिए वैश्विक तथा घरेलू, दोनों कारकों की अहम भूमिका होगी। घरेलू स्तर पर आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए अवसंरचनात्मक निवेश, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह में तेजी लाना, फंसे कर्ज की समस्या का उचित निदान करना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि 2020 की पहली छमाही से ऑटो क्षेत्र की सुस्ती दूर होगी लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के आने से दोपहिया वाहनों की बिक्री में आवश्यक वृद्धि की उम्मीद कम है। हालांकि आईटी क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 में डॉलर के संदर्भ में दो अंक के निर्यात को छूना मुश्किल होगा। आईटी निर्यात में 110 अरब डॉलर से अधिक के 'बेस इफेक्ट' के साथ वैश्विक जीडीपी की धीमी विकास दर आईटी निर्यात के विकास को बाधित करेंगी। सीमेंट तथा स्टील सहित बुनियादी ढांचे के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित निवेश से बढ़ावा मिल सकता है। व्यापार सौदों में आने वाली बाधाओं के समाधान से जस्ता, तांबा तथा एल्युमीनियम जैसी धातुओं के लिए दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और चीनी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ राज्य की चीनी कंपनियों के लिए 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। बैंक के फंसे कर्ज में काफी कमी आई है और सकल एनपीए मार्च 2018 के 11.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 9.1 प्रतिशत रह गया है। इस साल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सरकार का समर्थन, सरकारी बैंकों का विलय और रियल्टी क्षेत्र में मजबूती देखने को मिलेगी। हालांकि अमेरिकी नियामक द्वारा भारतीय कंपनियों के खिलाफ कड़ा रुख बनाए रखने से फार्मा क्षेत्र को उबरने में समय लगेगा। दूरसंचार क्षेत्र में भी अधिक तेजी आने की उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां बरकरार रहने के बावजूद वर्ष 2020 में साल 2019 के मुकाबले आर्थिक परिदृश्य बेहतर स्थिति में दिखाई देगा।

बातचीत: **वीरेश्वर तोमर**

**जी. चोकालिंगम**
संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक, इक्विनोमिक्स रिसर्च

## पुरस्कृत पत्र

### सरल नहीं है अपेक्षित परिणाम मिलना

नए वर्ष में कारोबार और आर्थिक गतिविधियों से अपेक्षित परिणाम मिलना इतना सरल नहीं है क्योंकि बृहद स्तर पर आर्थिक सुधार के परिणाम में काफी समय लगता है। बहरहाल पिछले साल की अपेक्षा कारोबारी वृद्धि जरूर दिखेगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो वर्ष 1991-92 के उदारीकरण के फायदे 21 वीं सदी में ज्यादा मिले। फिलहाल भारतीय कारोबार और अर्थव्यवस्था को नकारात्मक मानना भी उचित नहीं होगा क्योंकि भारत अभी भी विश्व की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की ओर अग्रसर है और कई सारे प्रयास कर रही है जैसे कमजोर बैंकों को बड़े बैंकों में विलय करके एनपीए को घटाने का प्रयास, एक्सिम बैंक का विस्तार, ढांचागत विकास के लिए विशेष निधि, कॉर्पोरेट करों में कमी, स्टार्टअप को ऐंजल टैक्स से छूट, किसान को छह हजार रुपये की सब्सिडी आदि।

1

**कृष्ण चंद्र त्रिपाठी**
उज्जैन, मध्य प्रदेश

पुरस्कार राशि
500 रुपये

## श्रेष्ठ पत्र

**दिव्या सेठी**
नोएडा, उत्तर प्रदेश

### इस साल मंदी से उबरने की आस

नए साल में शेयर बाजार नए शिखर पर पहुंच सकता है। आर्थिक सुधार जारी रहने की उम्मीद के बीच नजर मोदी सरकार की तरफ से की जाने वाली सुधार संबंधी गतिविधियों पर रहेगी। देश में आर्थिक सुधार का काफी दारोमदार निवेशकों की धारणा पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार को आम लोगों के साथ इनकी धारणा में भी बदलाव लाने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में हाल में काफी सुधार हुए हैं और अब कई क्षेत्र स्थिति के हिसाब से समायोजित करने में जुटे हैं। शेयर बाजार या जिंस बाजार के बारे में अनुमान लगाना हमेशा जोखिम भरा होता है। हम कह सकते हैं कि नया साल आर्थिक और कारोबारी दृष्टिकोण से सम्यक रहेगा और सरकार मंदी और मुद्रास्फीति से इस साल हमें उबार देगी।

**हरिओम हंसराज**
सारण, बिहार

### कारोबार के मोर्चे पर नरम ही रहेगा साल

साल 2019 में आर्थिक सुस्ती की वजह से ठंडे पड़े रोजगार बाजार के साल 2020 में भी नरम रहने की ही उम्मीद है। वेतन बढ़ने के मामले में भी स्थिति कुछ इसी तरह की रह सकती है। तकनीक की वजह से कारोबार में बदलाव आते रहेंगे और इस वजह से कंपनियां नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जगह मौजूदा कर्मियों की कुशलता बढ़ाने पर ध्यान दे सकती हैं। भारत की जीडीपी और अन्य आर्थिक संकेतक ठंडे हैं। इस वजह से घरेलू खपत और निवेश के आंकड़ों पर नजर रहेगी। अगर इनमें कुछ सुधार होता है तो रोजगार के मौके आकर्षक बन सकते हैं। साल 2020 की पहली तिमाही रोजगार के लिहाज से बहुत उत्साहजनक नहीं रहने वाली है। साल 2019 में वाहन, निर्माण और इंजीनियरिंग समेत तमाम क्षेत्र में कमजोरी देखी गई है।

**संजय डागा**
इंदौर, मध्य प्रदेश

### मील का पत्थर साबित होगा साल

साल 2019 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा लेकिन साल 2020 भारतीय बाजार के लिए अच्छा साल साबित हो सकता है। लोग भी नए साल को लेकर उत्साहित हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में इस वर्ष करीब सात लाख नौकरियां निकलने की उम्मीद है। इन नौकरियों को पैदा करने में स्टार्टअप कंपनियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेगी। साल 2020 रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए भी नई उम्मीद लेकर आया है। सरकार की ओर से 25,000 करोड़ रुपये का स्ट्रेस फंड और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले सुगम और सस्ते कर्ज से इस क्षेत्र में मांग बढ़ेगी। साथ ही सस्ते घरों की मांग भी निकलने से यह क्षेत्र नई उड़ान भरेगा। 2020 देश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा।

**राजेश कुमार चौहान**
जालंधर, पंजाब

### कुटीर कारोबार को बढ़ावा मिलेगा

वर्ष 2020 में मोदी सरकार की दूसरी पारी से आम लोगों को उम्मीद है कि वह महंगाई से राहत दिलाएगी और कारोबार जगत के अच्छे दिन लाने के लिए महत्त्वपूर्ण फैसले लेगी। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जहां सरकारों का दायित्व बनता है कि वो आम लोगों की खून पसीने की कमाई से वसूले गए विभिन्न करों का उपयोग देश के कारोबार में सुधार लाने के लिए भी करे। क्योंकि कारोबार में जरूरी नहीं कि हर समय लाभ ही हो। जब किसी कारोबारी को घाटा हो तो सरकार को उसकी आर्थिक मदद कठोर शर्तों के बिना करनी चाहिए और कारोबार जगत भी देय कर सरकारी खजाने में जमा करे। उम्मीद है कि वर्ष 2020 में मोदी सरकार कुटीर कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ऐतिहासिक फैसले भी जरूर लेगी।

## ... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम समसामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -
**अर्थव्यवस्था सुधारने को कर में हों क्या बदलाव?**

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
**फैक्स नंबर- 011-3720201**
**या फिर ई-मेल करें**
**goshthi@bsmail.in**

# अंतहीन नहीं होनी चाहिए ब्लैकलिस्टिंग

एम जे एंटनी

अमूमन, किसी कंपनी को निश्चित समय यानी कुछ साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है। लेकिन अगर किसी कंपनी अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंधित करना उसे ब्लैकलिस्ट करने से भी बदतर है और अवैध है। उच्चतम न्यायालय ने डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद में यह व्यवस्था दी। इस मामले में डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सहित 56 दवा कंपनियों ने 2015 में राज्य के अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति के लिए बोली लगाई थी। लेकिन डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उसके एक निदेशक पर सीबीआई की नजर थी। उस पर व्यक्तिगत फायदे के लिए फर्जी खाते बनाने का आरोप था। लेकिन कंपनी की दलील थी कि उस निदेशक ने 2012 में ही इस्तीफा दे दिया था और वह अब कंपनी ने नहीं जुड़ा था। उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह दलील भी दी कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए प्रतिबंध को सही ठहराया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं है क्योंकि अनिश्चितकालीन प्रतिबंध गैर कानूनी है और आदेश पारित करने से पहले कंपनी का पक्ष नहीं सुना गया।

## संशोधित मध्यस्थता कानून पर रेलवे का पेच

मध्यस्थता एवं सुलह कानून में संदेह को दूर करने के लिए 2015 में संशोधन किया गया था लेकिन इसके बावजूद मध्यस्थता की तटस्थता पर विवाद पैदा हुआ है। विवादित पक्षों के कुछ अधिकारियों के मध्यस्थ बनने पर प्रतिबंध लगाया गया दिया गया है। यहां तक कि वे विवाद में मध्यस्थ भी नामांकित नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता, रेलवे मंत्रालय ने कुछ मामलों में वैधानिक शर्तों में छूट देने के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में बदलाव किए हैं। केंद्रीय संगठन बनाम ईसीआई-एसपीआईसी-एसएमओ-एमसीएमएल (जेवी) वाद में रेलवे के एक ठेकेदार ने इसका विरोध किया था। रेलवे ने अपने कुछ अधिकारियों को मध्यस्थ नामांकित किया था लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए एक स्वतंत्र मध्यस्थ को नियुक्त किया। इसके खिलाफ रेलवे

अदालत से

ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और ठेकेदार को रेलवे द्वारा मुहैया कराए गए नामों में से मध्यस्थ चुनने को कहा। न्यायालय ने कहा कि समझौते में स्पष्ट रूप से संशोधित जीसीसी का उल्लेख किया गया था जिसमें रेलवे अधिकारियों को मध्यस्थ बनाने का प्रावधान है। इसलिए समझौते का पालन होना चाहिए।

## तर्कसंगत होने चाहिए अवॉर्ड

उच्चतम न्यायालय का कहना है कि मध्यस्थता पंचाटों के फैसले अस्पष्ट नहीं बल्कि पूरी तरह स्पष्ट होने चाहिए। अस्पष्ट फैसलों से संबंधित पक्षों के समय और संसाधनों की बरबादी होती है। न्यायालय ने डायना टेक्नोलॉजिज बनाम क्रॉम्प्टन ग्रीव्स वाद में अपने फैसले में यह बात कही। दोनों पक्षों बीच करीब 25 साल से चले आ रहे विवाद में क्रॉम्प्टन ग्रीव्स को विवाद खत्म करने के लिए दूसरे पक्ष को 30 लाख रुपये देने को कहा था। क्रॉम्प्टन ग्रीव्स ने डायना के साथ एक्वाकल्चर यूनिट बनाने का अनुबंध खत्म कर दिया था जिससे विवाद पैदा हुआ। पंचाट के फैसले को मद्रास उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से सही ठहराया लेकिन कहा कि इसमें कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। अपील पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ विस्तृत फैसला देने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन फैसला उचित, स्पष्ट और पर्याप्त होना चाहिए। अगर फैसलों में स्पष्टता नहीं होगी तो उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है।

## बतानी होगी दावा खारिज होने की वजह

अगर कोई साधारण बीमा कंपनी किसी दावे को खारिज करती है तो उसे बीमित व्यक्ति को इसकी वजह बतानी चाहिए। अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो बीमा कंपनी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के सामने कोई नई वजह नहीं बता सकती है। उच्चतम न्यायालय ने सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड बनाम नैशनल इंश्योरेंस कंपनी वाद में यह व्यवस्था दी। कंपनी को कुछ समय के लिए बीमार घोषित किया गया था और उसका माल गोदाम में पड़ा था। जब गोदाम को फिर से खोला गया तो पता चला कि आग के कारण कुछ माल नष्ट गया। अग्नि नीति के तहत कंपनी ने इसका मुआवजा मांगा। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावे को खारिज कर दिया कि आग किण्वन या प्राकृतिक ताप की वजह से लगी जो नीति के तहत नहीं आती है।

हालांकि देर से दावा करने का जिक्र नहीं किया गया था। जब कंपनी ने बीमा कंपनी को अदालत में घसीटा तो उसने एक नई दलील दी कि दावा 15 दिन की तय अवधि के बाद किया गया था। आयोग ने इसे मान लिया और दावे को खारिज कर दिया। अपील स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बीमा कंपनी दावा खारिज करने का अपना आधार नहीं बदल सकता है। अगर संबंधित पत्र में दावा करने में देरी को वजह नहीं बताया गया है तो वह राष्ट्रीय आयोग के समक्ष सुनवाई में इसका हवाला नहीं दे सकती है।

## आधिकारिक परिसमापक बनाम आरपी की भूमिका

अवनी प्रोजेक्ट्स बनाम आधिकारिक परिसमापक मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) द्वारा नियुक्त समाधान पेशेवर (आरपी) और कलकत्ता उच्च न्यायालय के कंपनी न्यायाधीश द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक की भूमिका को लेकर विवाद था। कुछ ऋणदाताओं ने कंपनी कानून की धारा 433-ई का हवाला देते हुए कंपनी न्यायाधीश में गुहार लगाई। न्यायाधीश ने एक परिसमापक नियुक्त कर दिया। इसके बाद ऋणदाताओं के एक समूह ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता का हवाला देते हुए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया। पंचाट ने एक समाधान पेशेवर नियुक्त कर दिया। न्यायाधीश और एनसीएलटी के आदेशों ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी जिसे उच्च न्यायालय ने विवेकपूर्ण तरीके से निपटाया। उसने व्यवस्था दी कि अदालत कंपनी के परिसमापन की याचिका पर सुनवाई कर सकती है लेकिन वह एनसीएलटी की समाधान योजना पर फैसला करने के बाद ही ऐसा कर सकती है। अगर समाधान योजना खारिज होती है तो कंपनी न्यायाधीश परिसमापन की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। परिसमापक को समाधान पेशेवर को हर तरह की मदद करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने साथ ही कहा कि एनसीएलटी को परिसमापक के लिए आदेश पारित करते समय ज्यादा सतर्क होना चाहिए था। एनसीएलटी ने परिसमापक को कंपनी का लेखाजोखा सौंपने और व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा था।

## जीएसटी कानून में संशोधन करे सरकार

गुजरात उच्च न्यायालय ने आयातकों और वितरकों पर लागू होने वाले एकीकृत जीएसटी के मामले में 16 दिशानिर्देश जारी किए हैं और सरकार को जीएसटी कानून के दो प्रावधानों में संशोधन करने को कहा है। डीलरों की शिकायत यह थी कि अधिकारी मनमाने ढंग से जीएसटी कानून की धारा 129 और 130 का उपयोग कर रहे हैं। पहली धारा वस्तुओं की जब्ती से संबंधित है जबकि दूसरी धारा अधिकारियों को उन वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार देती हैं जिन पर कर चोरी का शक होता है। सिनर्जी फर्टिकेम लिमिटेड बनाम राज्य वाद में स्पेन से सिरैमिक पेंट्स का आयात करने वाले आयातक की शिकायत थी कि आवाजाही के समय उसकी खेप को जब्त कर दिया गया था और उनका सामान जल्दी खराब होने वाला था। न्यायालय ने डीलरों को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि जीएसटी अधिकारियों को करदाताओं को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। जीएसटी अधिकारियों को कानून के विभिन्न प्रावधानों और नियमों को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हें लागू करने में किसी को कोई दिक्कत न हो। न्यायालय ने सरकार को इन दो प्रावधानों को संशोधित करके स्थिति स्पष्ट करने को कहा। न्यायालय ने साथ ही जीएसटी से जुड़े सभी विवादों के तुरंत समाधान के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विवाद समाधान समितियां बनाने का भी सुझाव दिया।

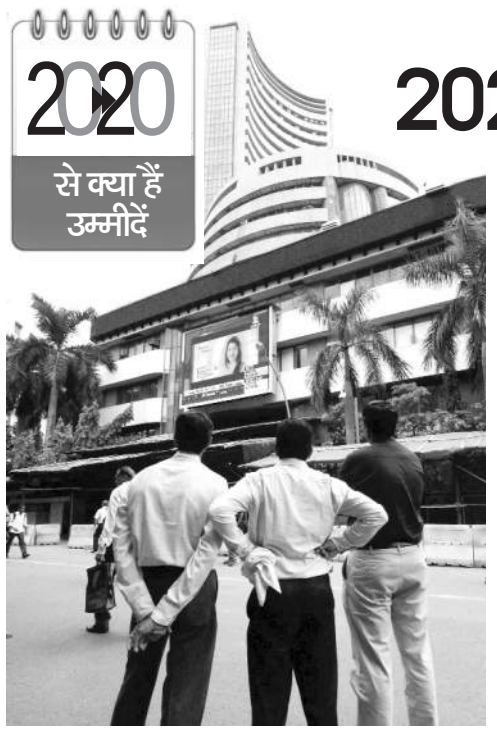


# 2020 में इन 10 शेयरों पर लगाएं दांव

**राम प्रसाद साहू और श्रीपाद ऑटे**

पिछले साल सेंसेक्स और निफ्टी करीब 12 फीसदी चढ़े हैं, लेकिन दोनों में तेजी मुख्य रूप से लार्ज कैप शेयरों की बदौलत आई है। मिड और स्मॉल कैप मुश्किल से 2018 का मूल्यांकन बरकरार रख पाए हैं। असल में 2019 में बीएसई मिडकैप सूचकांक 2018 की तुलना में करीब सात फीसदी लुढ़का है। आर्थिक मंदी और अनिश्चित माहौल की वजह से निवेशकों ने अच्छी और बड़ी कंपनियों में भरोसा दिखाया है। क्रेडिट सुइस जैसी ब्रोकरेज का मानना है कि कम से कम कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में बाजार सीमित दायरे में बना रहेगा। विश्लेषकों का कहना है कि व्यापक तेजी के लिए और नीतिगत पहलों की जरूरत है। उदाहरण के लिए मॉर्गन स्टैनली का तेजड़िया नजरिया कॉरपोरेट कर में कटौती से निवेश चक्र में मजबूती, सरकारी पूंजीगत व्यय में तेजी और निर्यात में बढ़ोतरी पर आधारित है। ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि सुधार धीरे-धीरे आएगा, जिसमें कैलेंडर वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में तेजी आएगी।

वृद्धि को बढ़ाने वाले कारकों में निम्न आधार के अलावा सामान्य मॉनसून और ब्याज दरों में कटौती का ग्राहकों पूरा फायदा मिलने का असर आदि शामिल हैं। आगामी समय में निवेश और खपत में बढ़ोतरी की उम्मीद है, इसलिए ज्यादातर शोध फर्मों का मानना है कि वित्तीय आंकड़ों में सुधार आएगा। वित्तीय आंकड़ों के अलावा हमने बहुत से क्षेत्रों के उन शेयरों को प्रमुखता से पेश किया है, जिनमें ऊंचा प्रतिफल देने की संभावना है और जिन्हें तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा कम से कम दो ब्रोकरेज ने इन शेयरों का सुझाव दिया है। इन शेयरों में 10 फीसदी या अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद है।

## भारती एयरटेल

| | |
|---|---|
| मौजूदा कीमत (रुपये) | 455.00 |
| लक्षित कीमत (रुपये) | 542.50 |
| बढ़त (%) | 19.0 |
| चालू पीई (गुना) | उपलब्ध नहीं |

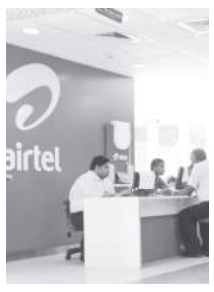

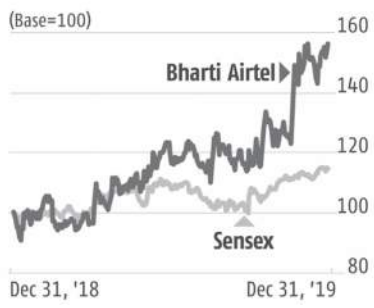


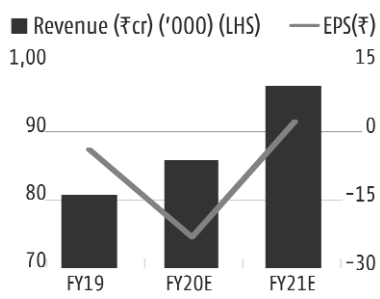


- शुल्क बढ़ोतरी और डेटा के अधिक इस्तेमाल से प्रति ग्राहक औसत राजस्व (एआरपीयू) में इजाफा होगा
- इस क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से एयरटेल को भी मिलेगी मदद
- अगर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के भुगतान में कोई राहत नहीं भी मिलती है तो कंपनी को अपनी पूंजी जुटाने की योजना और सुधरती नकदी आवक से इसे चुकाने में मदद मिलेगी
- नेटवर्क और सेवा पेशकशों को देखते हुए यह इस क्षेत्र में एकीकरण से फायदा उठाने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में है
- अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूदगी और दूरसंचार सेवाओं से इतर पेशकश भी लंबी अवधि में राजस्व में देंगी अहम योगदान

## अल्ट्राटेक सीमेंट

| | |
|---|---|
| मौजूदा कीमत (रुपये) | 4,217.95 |
| लक्षित कीमत (रुपये) | 4,762.93 |
| बढ़त (%) | 12.9 |
| चालू पीई (गुना) | 45.6 |

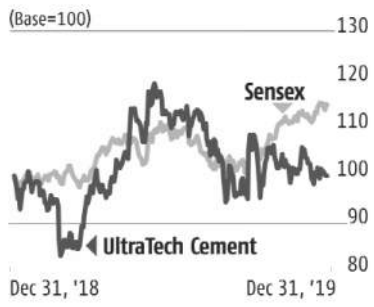


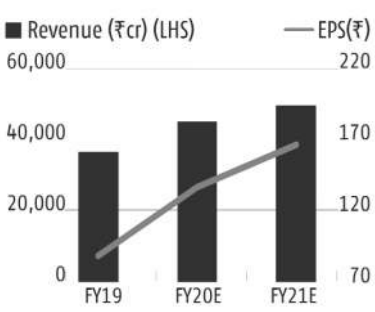


- करीब 23 फीसदी बाजार हिस्सेदारी और देश भर में मौजूदगी के चलते अल्ट्राटेक बाजार की अगुआ है
- वर्ष 2020 में बुनियादी ढांचे और किफायती आवासों पर सरकार का खर्च बढ़ने के आसार हैं, जिससे सीमेंट की मांग में इजाफा होगा और ज्यादातर क्षेत्रों में क्लिंकर की क्षमता के ज्यादा उपयोग से आमदनी में सुधार होगा
- सीमित पूंजीगत खर्च की जरूरत और मजबूत संभावित नकदी आवक से अल्ट्राटेक के प्रतिफल अनुपात में आएगा सुधार
- हाल में अधिग्रहीत सेंचुरी के सीमेंट संयंत्रों के लाभ में आने के आसार हैं, जिससे अल्ट्राटेक को अगले दो वर्षों में कुल आमदनी सुधारने में मदद मिलेगी
- हाल में शेयर में गिरावट आने से जोखिम-प्रतिफल अनुकूल नजर आ रहा है

## एचसीएल टेक्नोलॉजिज

| | |
|---|---|
| मौजूदा कीमत (रुपये) | 584.65 |
| लक्षित कीमत (रुपये) | 657.50 |
| बढ़त (%) | 12.4 |
| चालू पीई (गुना) | 15.5 |

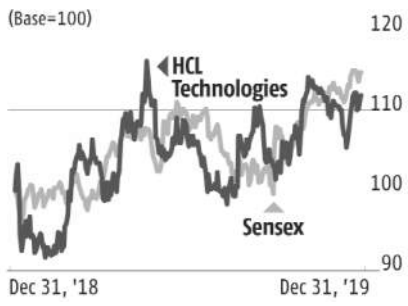


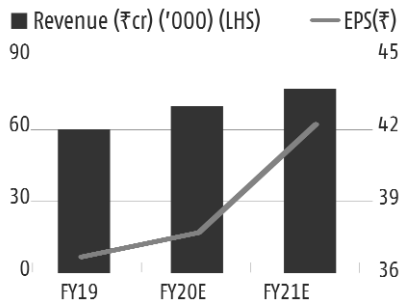


- इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और ब्लॉक चेन जैसी आधुनिक तकनीकों पर जोर से भविष्य में वृद्धि तेज होगी
- मौजदा ग्राहकों से ज्यादा से ज्यादा कमाई करने, साझेदारों के साथ गठजोड़ और स्वचालन के जरिये लागत को कम करने से वृद्धि के मौजूदा अवसरों में इजाफा होगा और मार्जिन में सुधार आएगा
- विलय एवं अधिग्रहण और बिक्री में बढ़ोतरी के जरिये वृद्धि में संतुलन और अधिग्रहणों से राजस्व को बढ़ाने पर ध्यान देना
- सौदे हासिल करने, मजबूत ऑर्डर बुक और सॉफ्टवेयर खंड (अधिग्रहीत आईबीएम के उत्पाद एवं कारोबार समेत) के योगदान से मिलेगी मदद

## लार्सन ऐंड टुब्रो

| | |
|---|---|
| मौजूदा कीमत (रुपये) | 1,335.15 |
| लक्षित कीमत (रुपये) | 1,636.83 |
| बढ़त (%) | 22.0 |
| चालू पीई (गुना) | 20.5 |

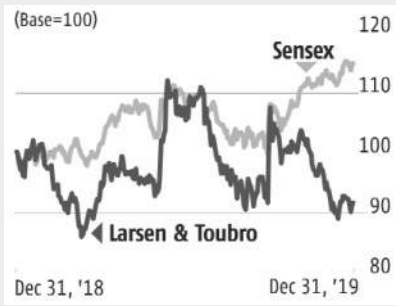


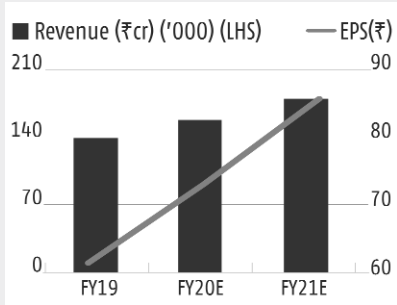


- कंपनी 16 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बनी हुई है अगुआ
- नए ऑर्डरों में बढ़ोतरी से इंजीनियरिंग क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी की ऑर्डर बुक सितंबर 2019 में तीन लाख करोड़ रुपये का स्तर पार कर गई
- दूसरी छमाही में अच्छे सौदे मिलने का अनुमान है, इसलिए एलऐंडटी वित्त वर्ष 2020 में ऑर्डरों की आवक में 10 से 12 फीसदी बढ़ोतरी के अपने ही अनुमान से आगे निकल सकती है
- सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डों और शहरी बुनियादी ढांचे पर सरकार के निवेश का कंपनी को मध्यम अवधि में फायदा मिलेगा
- गैर-प्रमुख और कम मार्जिन वाले कारोबारों से दूर होने से कंपनी के प्रतिफल का अनुपात सुधरने की संभावना

## पावर ग्रिड कॉर्प

| | |
|---|---|
| मौजूदा कीमत (रुपये) | 192.95 |
| लक्षित कीमत (रुपये) | 253.50 |
| बढ़त (%) | 31.3 |
| चालू पीई (गुना) | 8.0 |

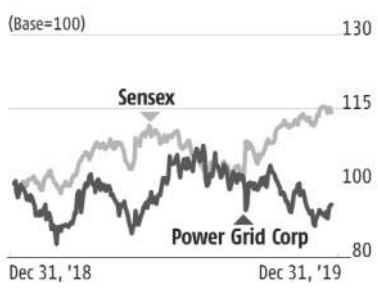


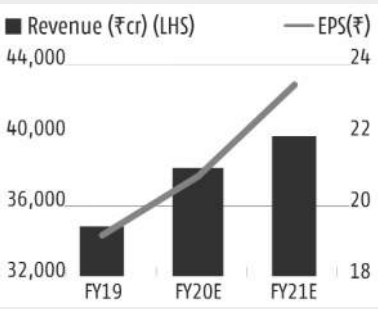


- पावर ग्रिड आक्रामक रूप से परियोजनाओं की शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली लगा रही है ताकि पूंजीगत व्यय में मंदी को मात दी जा सके। कंपनी अपनी ऑर्डर बुक को फिर से भर रही है
- कंपनी अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर धन जुटा रही है, जिससे उसे अपना मूल्य बढ़ाने और नई परियोजनाओं के लिए पूंजी मुहैया कराने में मिल रही है मदद
- सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता मौजूदा 130 गीगावॉट से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट करने की योजना बनाई है। यह कंपनी के लिए सकारात्मक है क्योंकि इस योजना के तहत पारेषण पर 5.5 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा
- इस समय पावर ग्रिड के शेयर की एक साल बाद की संभावित आमदनी के मुकाबले कीमत (पी/ई) महंगी नहीं है
- वृद्धि की संभावनाओं के अलावा 4.4 फीसदी लाभांश प्रतिफल देता है राहत

## भारतीय स्टेट बैंक

| | |
|---|---|
| मौजूदा कीमत (रुपये) | 333.75 |
| लक्षित कीमत (रुपये) | 395.02 |
| बढ़त (%) | 18.5 |
| चालू पीई (गुना) | 1.2 |

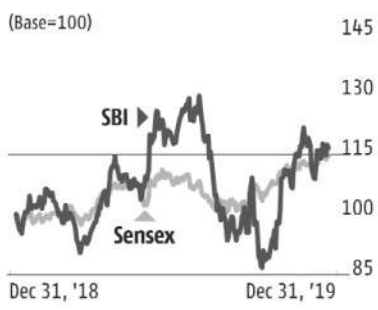


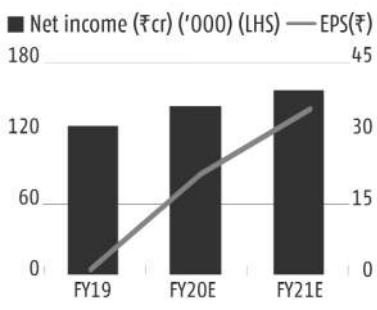


- व्यापक शाखा नेटवर्क कारोबारी अवसरों के लिहाज से अन्य बैंकों पर देता है बढ़त
- हाल में एस्सार स्टील समेत कई फंसे ऋणों के समाधान से प्रावधान की राशि वापस आएगी और आमदनी में इजाफा होगा
- पिछले साल फंसे ऋणों के लिए प्रावधान का असर देखना लेकिन सितंबर 2019 तक 63 फीसदी का अच्छा प्रावधान कवरेज अनुपात राहतभरा है
- अहम सहायक कंपनियां शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, जिन्हें बेचकर एसबीआई ने धन जुटाने की योजना बनाई है। इससे शेयरधारकों के शेयरों का मूल्यांकन बढ़ेगा
- इस समय शेयर वित्त वर्ष 21 की अनुमानित बुक वैल्यू के आकर्षक स्तर 1.2 गुना पर है, जबकि कुछ अन्य बड़े निजी बैंक 2-3 गुना पर पर बने हुए हैं।

## चोला इन्वेस्ट ऐंड फाइनैंस

| | |
|---|---|
| मौजूदा कीमत (रुपये) | 303.00 |
| लक्षित कीमत (रुपये) | 354.72 |
| बढ़त (%) | 17.0 |
| चालू पी/बीवी (गुना) | 3.8 |

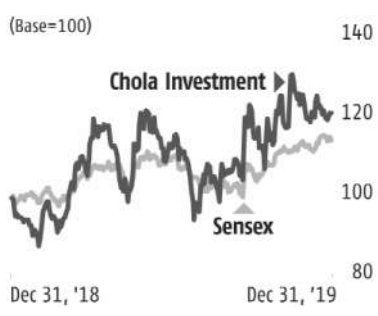


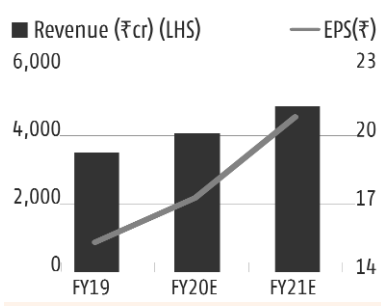


- यह विविधीकृत गैर-बैंकिंग ऋणदाता है, जिसका जोर तुलनात्मक रूप से सुरक्षित एवं लगातार बढ़ रहे वाहन ऋण और आवास इक्विटी खंड पर है
- नकदी की अच्छी उपलब्धता, पैरेंट कंपनी (मुरुगप्पा समूह) के समर्थन और ऋण देने में परंपरागत तरीके अपनाना क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए अच्छी रणनीति है
- डिजिटलीकरण पर जोर, गाडी बाजार (पुराने वाहनों के लिए ऑनलाइन बाजार) जैसे नए टूल शुरू करने से इसके वाहन ऋण कारोबार को मदद मिलेगी
- मददगार बैलैंस शीट और निश्चित ब्याज दर वाली परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा होने और फ्लोटिंग देनदारियों में प्रमुख हिस्सेदारी मार्जिन में तगड़ी बढ़ोतरी का संकेत है।
- फंसे ऋणों का अनुपात जून 2018 में 3.6 फीसदी था, जो सितंबर 2019 में 3.2 फीसदी पर आया

## डाबर इंडिया

| | |
|---|---|
| मौजूदा कीमत (रुपये) | 455.60 |
| लक्षित कीमत (रुपये) | 516.77 |
| बढ़त (%) | 13.4 |
| चालू पीई (गुना) | 56.1 |

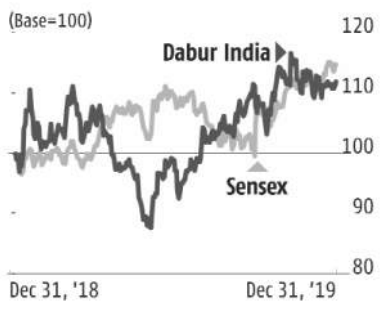


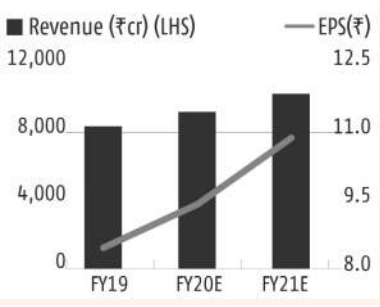


- ग्रामीण बाजार में स्थितियां सुधरने के अनुमान सकारात्मक हैं क्योंकि 45 फीसदी राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों से आता है
- आक्रामक प्रचार गतिविधियों और कारोबारी ऑफरों से मौजूदा कमजोर मांग के दौरान बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी
- ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने की रणनीति से डाबर को अपना ग्रामीण कारोबार शहरी बाजार से आगे ले जाने में मदद मिल रही है। अन्य कंपनियों के बाजार में शहरी बाजार का बड़ा हिस्सा है।
- नवोन्मेष और प्रीमियम उत्पाद विशेष रूप से प्राकृतिक उत्पादों के खंड में उत्पाद पेश करने से मार्जिन सुधरेगा
- शेयर में 13 फीसदी बढ़त की संभावना एफएमसीजी कंपनियों में सबसे बेहतर है

## ऐक्सिस बैंक

| | |
|---|---|
| मौजूदा कीमत (रुपये) | 742.90 |
| लक्षित कीमत (रुपये) | 851.67 |
| बढ़त (%) | 14.6 |
| चालू पी/बीवी (गुना) | 2.9 |

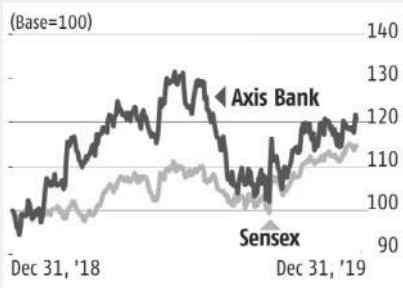


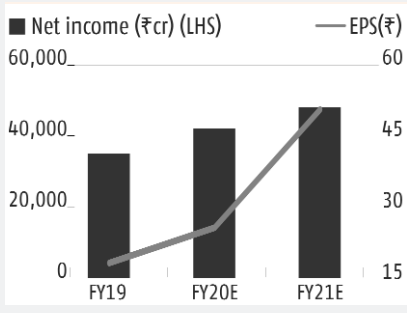


- एटीएम समेत शाखाओं के बड़े नेटवर्क ने बैंक को मजबूत खुदरा कारोबार खड़ा करने में मदद दी है। तकनीक की मदद से इसमें और सुधार आएगा।
- जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर ज्यादा प्रतिफल देने वाले ऋणों और लागत घटाने से लाभ में सुधार आएगा
- कुल परिसंपत्तियों में बीबी और इससे कम रेटिंग वाले ऋण घटकर सितंबर 2019 में 1.1 फीसदी पर आए, जो जून 2016 में 7.3 फीसदी थे
- परिसंपत्ति गुणवत्ता का परिदृश्य सुधरने से प्रतिफल अनुपात सुधरेगा और फंसे ऋणों के प्रावधान में कमी आने की संभावना है।
- सितंबर 2019 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.5 फीसदी और प्रावधान कवरेज अनुपात 79 फीसदी था, जो अच्छा नजर आ रहा है।

## हिंदुस्तान यूनिलीवर

| | |
|---|---|
| मौजूदा कीमत (रुपये) | 1,928.75 |
| लक्षित कीमत (रुपये) | 2,158.49 |
| बढ़त (%) | 11.9 |
| चालू पीई (गुना) | 68.8 |

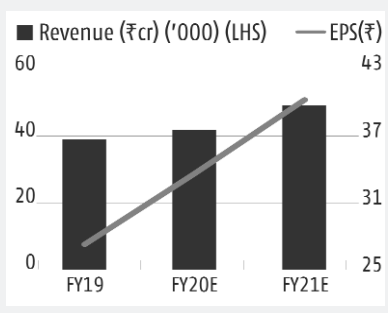


- रोजमर्रा का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके पास कई उत्पाद खंड हैं। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर के विलय से कंपनी के उत्पादों में बढ़ोतरी होगी
- ब्रांड की अच्छी साख से मौजूदा चुनौतीपूर्ण दौर में देखे जा रहे प्रीमियम उत्पादों के चलन का फायदा उठाने में मदद मिलेगी
- बाजार की जरूरत वाले उत्पादों को तेजी से अपनाने, प्राकृतिक उत्पादों के पोर्टफोलियो के कुशल क्रियान्वयन और आमदनी में तेजी लाने के लिए तकनीक पर जोर देना सकारात्मक है
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आने की संभावना है। इससे कंपनी की कुल आमदनी में इजाफा होगा क्योंकि एचयूएल के राजस्व में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा 40 फीसदी है
- कंपनी की बिक्री में वृद्धि सितंबर तिमाही में स्थिर रही। हालांकि कमजोर मांग के बावजूद तिमाही दर तिमाही आधार पर इसमें पांच फीसदी बढ़ोतरी रही

मौजूदा कीमत 3 जनवरी, 2020 को, लक्षित कीमत और बढ़त अगले 12 महीनों के लिए हैं। प्राइस टू अर्निंग (पी/ई) और प्राइस टू बुक वैल्यू (पी/बीवी) अनुपात सितंबर 2019 में समाप्त 12 महीनों के वित्तीय आंकड़ों पर आधारित हैं। एनआईआई शुद्ध ब्याज आमदनी है। ईपीएस प्रति शेयर आमदनी है। स्रोत : ब्रोकरेज, जिनमें ऐक्सिस सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, केआईएम ईएनजी सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज और क्रेडिट सुइस शामिल हैं।

बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़े

# चक्रवात से लड़ाई लड़ने वाला असाधारण योद्धा

## एलऐंडटी द्वारा विकसित की गई शुरुआती चेतावनी प्रणाली की मदद से ओडिशा सरकार को फणि चक्रवात के समय राहत-बचाव कार्यों में काफी मदद मिली

**जयजित दास**

जब पिछले साल अप्रैल महीने के दौरान भयंकर चक्रवात फणि ओडिशा के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा था तो उस समय राज्य प्रशासन इतिहास का सबसे बड़ा बचाव अभियान चला रहा था। अनुमान के मुताबिक पुरी और गंजम आदि राज्य के तटीय जिलों से करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया जिससे बड़े स्तर पर जान-माल की हानि को बचाया जा सका। इन सभी प्रयासों के पीछे एक अहम तकनीक का सहयोग था जिसे ओडिशा सरकार ने इंजीनियरिंग फर्म लॉर्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) के साथ मिलकर स्थापित की थी। दोनों ने समुद्र के तटीय इलाकों में पूर्व चेतावनी प्रणाली और मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित किया था।

ओडिशा में एलऐंडटी द्वारा लगाई गई पूर्व चेतावनी एवं प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) ने अक्टूबर 2018 में कार्य करना शुरू कर दिया था और राज्य की आपदा प्रबंधन इकाई के अधिकारी भुवनेश्वर स्थित राज्य आपात परिचालन केंद्र से संवेदनशील तटीय इलाकों में संदेश और अलर्ट भेज सकते थे। इसकी मदद से वे चक्रवात राहत केंद्र से भी संपर्क स्थापित कर सकते थे। सौर पैनल से चलने वाली और नवीन तकनीकों से लैस यह प्रणाली ऐसे समय में भी काम करती है जब तेज हवाओं के चलते मोबाइल सेवा बाधित हो जाती है और बिजली के खंभे गिर जाते हैं। एलऐंडटी की स्मार्ट वर्ल्ड ऐंड कम्युनिकेशन इकाई ने 'ईडब्ल्यूडीएस' को विकसित किया है। इस सिस्टम में डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर), उपग्रह आधारित मोबाइल डेटा वॉयस टर्मिनल, मास मेसेजिंग सिस्टम, अलर्ट टावर सायरन प्रणाली, और यूनिवर्सल कम्युनिकेशन इंटरफेस आदि कई नवीन तकनीक लगाई गई हैं। ये सभी मूल उपकरण निर्माताओं से खरीदे गए हैं। उदाहरण के लिए, अलर्ट टावर सायरन प्रणाली स्लोवाकिया स्थित इलेक्ट्रॉनिक सायरन कंपनी टेलीग्राफिया से ली गई है, जबकि मोटोरोला ने डीएमआर उपलब्ध कराया है। उपग्रह-आधारित मोबाइल डेटा वॉयस टर्मिनल डेनमार्क की कंपनी कोबहम से लिया गया तो वहीं स्थान विशेष पर आधारित अलर्ट सिस्टम नॉर्वे की यूएमएस से खरीदा गया था।

ओडिशा के तट पर उपकरण पहुंचने से पहले एलऐंडटी की एक टीम ने डीएमआर और जीएसएम नेटवर्क से जुड़ी सायरन प्रणाली लाने के लिए ओईएम की इकाई का दौरा किया। इसके इंटरफेस को इस तरह से बनाया गया है कि मामूली जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी इसे संचालित कर सकता है। यहां एक थर्ड पार्टी नेटवर्क निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है जिसके माध्यम से सभी उपकरणों की निगरानी और उनका दूर से प्रबंधन किया जा सके। एलऐंडटी के एक सूत्र ने कहा, 'हमने यह सुनिश्चित किया कि सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित था और कार्यान्वयन के समय आईटी अधिनियम के अनुसार सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम था।' ईडब्ल्यूडीएस को 22 तटीय ब्लॉक में स्थापित किया गया था और इसके जरिये राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र को छह जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों, 22 ब्लॉक आपातकालीन संचालन केंद्र, 14 फिश लैंडिंग सेंटर (एफएलसी) और 113 चक्रवात आश्रयों से जोड़ा गया।

### तकनीक से आपदा में बचाव

- **अप्रैल 2019 में भयंकर चक्रवात फणि ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से टकराया था**
- **उस समय सरकार ने तकनीक की मदद से सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाया**
- **राहत बचाव अभियान में पुरी और गंजम आदि राज्य के तटीय जिलों से करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था**
- **ओडिशा सरकार ने एलऐंडटी के साथ मिलकर उस को तकनीक स्थापित की थी**

एलऐंडटी के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक एसएन सुब्रमण्यन ने कहा, 'एलऐंडटी ने गंभीर प्राकृतिक आपदा के दौरान मानव जीवन को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए स्मार्ट तकनीक अनुप्रयोग का शानदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार (ओडिशा) के तंत्र को मजबूत करने के साथ हमारे एकीकृत अत्याधुनिक तकनीकी उपायों ने उन्हें संसाधन जुटाने, नागरिकों को सूचित करने, स्थिति की निगरानी करने और स्थितियों के लिए समय-समय पर प्रतिक्रिया संदेश प्रेषित करने के लिए उपयोगी उपकरणों से लैस किया है।'

ओडिशा की 480 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ 122 सायरन स्टेशन स्थापित किए गए थे। एसईओसी के अधिकारियों ने इन स्टेशनों की सीमा के भीतर रहने वालों को चक्रवात संबंधी अलर्ट तथा चेतावनी जारी करने के लिए नेटवर्क का उपयोग किया। आने वाले चक्रवात के बारे में लोगों को सावधान करने और जरूरी सुरक्षा उपायों के लिए उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और तेलुगू में मोबाइल टेक्स्ट मेसेज प्रसारित किए गए थे।

इस प्रणाली में अंतिम सिरे पर रिमोट टर्मिनल यूनिट के साथ अलर्ट सायरन प्रणाली लगी है जो चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र में लगाई गई है। रिमोट टर्मिनल यूनिट (आरटीयू) के स्पीकर हॉर्न को जगह विशेष की स्थिति के आधार पर 5 मीटर के खंभे या 30 मीटर के कोणीय टावर या कंक्रीट के टावर पर स्थापित किया जाता है। इन सूचनाओं को सायरन, पहले से रिकॉर्ड घोषणाएं या लाइव घोषणाओं के रूप में प्रसारित किया जाता है।

एसईओसी या बीईओसी द्वारा वीएचएफ नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क की मदद से भेजे गए संदेश को आरटीयू ग्रहण करता है और डीकोड करता है। सही चेतावनी संदेश मिलने पर आरटीयू पहले से निर्धारित अवधि के लिए तेज आवाज में संदेश प्रसारित करता है।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया, 'वर्ष 1999 में ओडिशा में एक खतरनाक चक्रवात आया था। उस दौरान हमारे पास इस तरह की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। इसके बाद वर्ष 2013 में जब फेलिन नामक चक्रवात में दक्षिणी तट को छुआ तो हमने बड़े पैमाने पर राहत कार्य को अंजाम दिया। लेकिन इस बार, हमने अलर्ट संदेश प्रेषित किए। फणि चक्रवात के समय प्रभावित होने वाले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए 18 करोड़ संदेश प्रसारित किए गए और हम जानते हैं कि ये कितने उपयोगी रहे।'

बचाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी अलर्ट भेजे जा रहे थे, जिससे यदि कोई व्यक्ति असुरक्षित जगह पर फंस गया हो तो उसे मदद उपलब्ध कराई जा सके। 3 मई को पुरी तट से टकराने के 15 मिनट पहले तक अलर्ट भेजे जा रहे थे। हालांकि इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी, सायरन स्टेशनों को स्थापित करना। कंपनी के एक सूत्र ने कहा, 'टावरों और अन्य सामग्रियों को साइट पर ले जाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। संबंधित स्थान की मिट्टी की स्थिति का अग्रिम अध्ययन किया जाना आवश्यक है क्योंकि 300 किमी/घंटे की तेज गति वाली हवा में टावर को बनाए रखने के लिए महबूत नींव की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, चक्रवात से बचाव के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों में रिमोट टर्मिनल यूनिटों को धूल तथा पानी से बचाने के लिए आईपी65 के अंदर रखा गया था।'

### डीएमआर से नवीनतम जानकारी

**एलऐंडटी** का दावा है कि आगामी चक्रवात की संभावना के दौरान मानव जीवन को बचाने के लिए ईडब्ल्यूडीएस फिलहाल उपलब्ध अहम तकनीकों में से एक है। ईडब्ल्यूडीएस में कई अहम प्रणालियां शामिल हैं जिसमें से एक है डीएमआर। डीएमआर की मदद से अधिकारी मौसम विभाग की नवीनतम जानकारी को जिला तथा ब्लॉक स्तर पर तैनात अधिकारियों तक भेज सकते हैं। डीएमआर प्रणाली ने समुद्र में मछुआरों के साथ संवाद करने के लिए समुद्र किनारे पर वीएचएफ रेडियो स्पेक्ट्रम प्रणाली को भी लगाया है जिससे वे सुरक्षित तट तक पहुंच सकें। उपग्रह-आधारित मोबाइल डेटा वॉयस टर्मिनल भी ईडब्ल्यूडीएस का एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटक है। इसका महत्त्व तेज गति वाले चक्रवाती तूफानों के समय बढ़ जाता है जब अक्सर मोबाइल नेटवर्क खराब हो जाते हैं। ये टर्मिनल ब्रिटिश फर्म इनमारसैट के स्वामित्व वाले एक उन्नत उपग्रह दूरसंचार नेटवर्क, इनमारसैट -4 के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को संदेश तथा ब्रॉडबैंड डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। भुवनेश्वर एसईओसी में तैनात राहत आयुक्त इन टर्मिनलों का अधिक उपयोग करते हैं क्योंकि फणि चक्रवात के समय नियमित दूरसंचार सेवाएं कम तथा अविश्वसनीय हो गई थीं। तेज चक्रवात के समय में भी इनमें से प्रत्येक टर्मिनल 11 मोबाइल से जुड़ सकता था और उन मोबाइल तक संदेश तथा इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा रहा था।

अंतिम छोर तक जुड़ने की योजना को सुनिश्चित करने वाली प्रणाली ईडब्ल्यूडीएस विश्व बैंक समर्थित राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम निवारक परियोजना के तहत खंड-ए के अंतर्गत अमल में लाई गई है। इसका उद्देश्य चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित समुदाय तक चेतावनी संदेश प्रसारित करके फुल-प्रूफ प्रणाली विकसित करना है। ओडिशा सरकार ने इसे लागू करने का बीड़ा उठाया है। इस प्रणाली को आंध्र प्रदेश में भी लगाया जा रहा है क्योंकि राज्य की सीमाएं भी चक्रवात से काफी प्रभावित होती हैं। ईडब्ल्यूडीएस प्रणाली को लगाने की लागत तथा बजट स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। हालांकि अभी भी राज्यों को लगता है कि इस प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। सरकारी अधिकारी ने कहा, 'अभी भी हमारी अपनी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अब 58 सैटेलाइट फोन से संबद्ध है लेकिन वे सभी केवल तब काम करते हैं जब उनमें अतिरिक्त एंटीना लगा होता है। हमें स्थायी एंटीना वाला उपकरण लाना चाहिए जिससे इनका हर समय काम करना सुनिश्चित किया जा सके।'

---

एल्गोरिद्म

## बातचीत संबंधी स्वचालित सेवा (सीएएस)

तकनीक तेजी से बदल रही है और इसके साथ ही लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। बातचीत संबंधित सेवाओं को स्वचालित करना तकनीक का एक ऐसा ही क्षेत्र है।

ग्राहक केंद्रित कंपनियां ऑटोमेशन, चैटबॉट, ई-मेल, स्पीच एनालिटिक्स और बायोमेट्रिक सुरक्षा आदि विभिन्न उपायों का एक साथ प्रयोग करके ग्राहक अनुभव को बेहतर और दक्ष बनाने पर काम कर रही हैं। खुदरा, उपभोक्ता सामान, दूरसंचार, पर्यटन एवं आतिथ्य और बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं जैसे उद्योग ग्राहकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वचलित तकनीकों का शुरुआती अवस्था में ही उपयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं।

कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी यूनिपोरे और सलाहकार एवं विश्लेषण फर्म ओपस रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार उद्योग अब कृत्रिम मेधा तकनीक की सहायता से ग्राहक सेवा संबंधी क्षेत्र में प्रोद्योगिकी का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए अगले चरण में कदम बढ़ाने को तैयार है। इसके लिए कॉम्प्रिहेन्सिव कन्वसेशनल्स सर्विस ऑटोमेशन के साथ एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

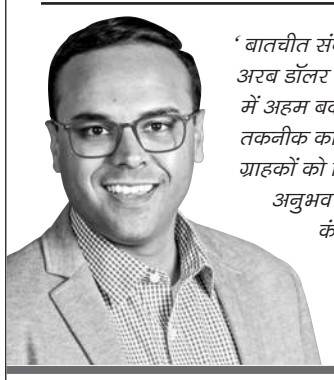

*'बातचीत संबंधी सेवा के ऑटोमेशन से 350 अरब डॉलर के वैश्विक कारोबार वाले उद्योग में अहम बदलाव आएगा। इसमें एआई तकनीक का अहम योगदान है जिससे ग्राहकों को रियल टाइम में बेहतरीन अनुभव मिल सकेगा। सीएसए के साथ कंपनियां कम लागत में बेहतर ग्राहक सेवाएं दे पाएंगी'*

उमेश सचदेव, सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी, यूनीफोरे

### क्या है सीएएस?

- उपभोक्ता उपायों की उभरती हुई एक श्रेणी, जिसके तहत कंपनियों द्वारा ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए एआई तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- इसे हासिल करने के लिए बहुत सी श्रेणियों का एक साथ समायोजन किया जाता है। जैसे, डेटा एनालिटिक्स, कन्वर्सेशनल्स एनालिटिक्स, वॉइस रोबोट, आईवीआर प्रणाली, सुरक्षा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) और ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं के इतिहास को एक साथ मिलाकर जांचना।
- यह स्वचालित मानव और मशीनी वार्तालाप, दोनों को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही, ग्राहकों तथा संबंधित केंद्र के एजेंट के बीच सार्थक बातचीत सुनिश्चित करता है।

### ग्राहक संबंधी सेवाओं में एआई का उपयोग

(आंकड़े प्रतिशत में)

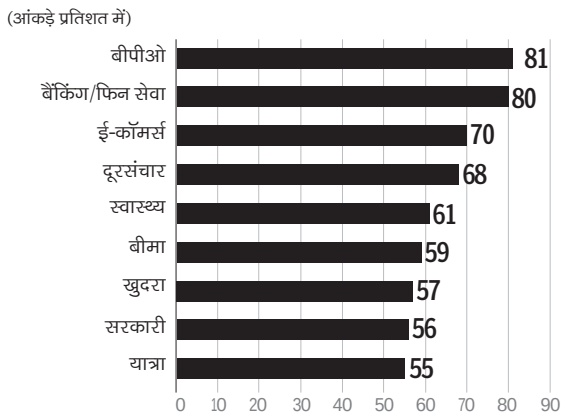


# उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और ब्रिटेन के 400 नीति निर्माताओं पर किए गए शोध पर आधारित

स्रोतः ओपस रिसर्च ग्लोबल सर्वे 2019

### खराब ग्राहक अनुभव के चलते हुई हानि

**अमेरिकी कंपनियों** ने खराब ग्राहक अनुभव के चलते पिछले एक वर्ष में गंवाई करीब 75 अरब डॉलर की राशि

**वर्ष 2016 में** इसके कारण करीब 62 अरब डॉलर का हुआ नुकसान

**इससे 350 अरब डॉलर** वाले ग्राहक सेवा कारोबार पर काफी दवाब बड़ा है। उद्योग फिलहाल बदलाव के दौर से गुजर रहा है

### समय की जरूरत

**ग्राहक सेवा**
ग्राहकों संबंधी अनुभवों को बेहतर करने के लिए इसका बेहतर होना नितांत आवश्यक

**आज के दौर में ग्राहक**
पहले की तुलना में काफी अधीर हो गए हैं। उनके पास बहुत से विकल्प मौजूद हैं।

**वे अपने समय की**
कीमत समझते हैं और बदले में कंपनी से भी उनके समय की कीमत समझने की उम्मीद करते हैं।

**वे इस बात से परेशान हैं**
कि स्वचालित प्रक्रिया अक्सर खराब रहती है और वहां काम करने वाले एजेंट सही तरीके से काम नहीं करते और उनकी बात को अनसुना करते रहते हैं।

---

# गूगल को भा रहे भारतीय स्टार्टअप के कारनामे

**पीरजादा अबरार**

**ऑप्टिक्स** एवं फोटोनिक्स क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय संस्था एसपीआईई के पिछले वर्ष हुए सालाना तकनीकी कार्यक्रम में चेन्नई स्थित स्टार्टअप एडिवो डायग्नोस्टिक्स की संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी गीतांजलि राधाकृष्णनन ने भी हिस्सा लिया था। अमेरिका में हुए इस कार्यक्रम में विश्व के हजारों लोगों ने भागीदारी की जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे।

तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एसएएसटीईए संस्थान से बायो-इंजीनियर की डिग्री हासिल करने वाली राधाकृष्णनन ने इस अवसर पर फोटोनिक्स पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया और उनकी कंपनी द्वारा विकसित की गई घाव में इन्फेक्शन से बचाव संबंधी उपकरण पेश किया। इस तकनीक से प्रभावित होकर गूगल ने उनसे संपर्क किया और भारत में गूगल लॉन्च पैड एक्सीलरेटर में शामिल होने के लिए कहा। एडिवो उन कई नई भारतीय कंपनियों में से एक है, जो कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित नवाचारों की मदद से भारत की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के उपाय विकसित कर रही हैं और उन्हें एक्सीलरेटर कार्यक्रम के तहत गूगल सलाह और समर्थन दे रही है। उदाहरण के लिए, कैंसर का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को हल करने के लिए 'भावनात्मक रूप से बुद्धिमान' रोबोट बनाए जा रहे हैं या बीमा धोखाधड़ी और दावों के प्रबंधन का पता लगाने के लिए नई तकनीक का उपयोग हो रहा है।

भारत में गूगल लॉन्च पैड एक्सीलरेटर के प्रोग्राम मैनेजर पॉल रवींद्रनाथ कहते हैं, 'हम भारत की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मानना है कि एआई और एमएल की सहायता से हम इनमें से कई चुनौतियों का समाधान कर सकेंगे।' वह कहते हैं, 'हम जिन स्टार्टअप को सहायता प्रदान कर रहे हैं उनमें से अधिकांश के कामकाज के केंद्र में एआई और एमएल तकनीक शामिल है।'

भारत में गूगल का तीन महीने का एक्सीलरेटर कार्यक्रम अपने उत्पादों को तेजी से बढ़ाने में मदद करने के लिए अपने लोगों, नेटवर्क और उन्नत प्रोद्योगिकियों के साथ उभरती नई परिस्थितियों से ये स्टार्टअप मेल खाते हैं। यह कार्यक्रम उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट और शीर्ष तकनीकी कंपनियों के सलाहकारों से भी जोड़ता है। एडिवो ने मशीन लर्निंग आधारित क्लाउड मॉडल पेश किया था जो इस नवोन्मेष की प्रायोगिक परियोजना के लिए आवश्यक है। हालांकि शुरुआत में यह उपकरण काफी बड़ा और भारी था लेकिन गूगल टीम की मदद से इसे आईफोन जैसे आकार तक लाने में मदद मिली। उपकरण का यूजर इंटरफेस बेहतर बनाया गया और ऐप का आकार भी कम किया गया। एडिवो का पोर्टेबल उपकरण 'इल्युमिनेट' उन्नत इमेज प्रोसेसिंग एवं मशीन लर्निंग एल्गोरिद्म का उपयोग करके मिनट के भीतर त्वचा में रोगजनक एवं संक्रमित ऊतकों की उपस्थिति का पता लगा सकता है। इससे चिकित्सकों को संक्रमण के प्रारंभिक चरण में सही उपचार करने में मदद मिलती है।

### गूगल की पसंद

| कंपनी | नवोन्मेष का क्षेत्र |
|---|---|
| एडिवो डायग्नोस्टिक्स | शीघ्र घाव इन्फेक्शन निदान उपकरण |
| वाइसा | मानसिक स्वास्थ्य के लिए एआई आधारित रोबोट |
| पर्सेप्टिविटी | बीमा में फर्जी दावों की पहचान |
| फाइनेंसपीयर | तकनीक की मदद से स्कूलों को वित्तीय मदद |
| स्मार्टकॉइन | आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को मदद |
| निरामयी | शुरुआती स्तर पर स्तन कैंसर की पहचान करना |

एडिवो में बिजनेस ऑपरेशंस के प्रमुख मुकुंद राममूर्ति कहते हैं, 'आजकल घाव का इलाज आसानी से हो सकता है लेकिन अभी भी घाव के ईलाज के लिए सही उपचार की पहचान करने में करीब 72 घंटे लग जाते हैं क्योंकि ऊतकों को प्रयोगशालाओं में ले जाना पड़ता है। हम इस समय को घटाकर कुछ मिनट तक सीमित कर रहे हैं और इसमें होने वाली मानव की गलतियों को भी हटा रहे हैं।'

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शुरुआती स्तर पर संक्रमण की पहचान कर ली जाए तो बाद में बीमारी के चलते शरीर का वह हिस्सा हटाने की संभावना 90 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। फिलहाल देश के कुछ अस्पतालों में एडिवो के उपकरण का प्रयोग हो रहा है और अब कंपनी अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में लॉन्च करने की योजना बना रही है।

तकनीक की मदद से मानसिक स्वास्थ्य विकारों का समाधान खोज रही कंपनियों को भी गूगल सहायता उपलब्ध करा रही है। एआई तकनीक आधारित मानसिक स्वास्थ्य के लिए चैट थेरेपी प्लेटफॉर्म 'वाइसा' ने 'भावनात्मक बुद्धिमता' आधारित रोबोट तैयार किया है जो वर्चुअल कोच की तरह काम करता है और उपयोगकर्ता की भावनाओं के हिसाब से व्यवहार करता है। यह व्यक्ति को अच्छा अनुभव कराने और मानसिक शांति के लिए कॉग्निटिव व्यवहारात्मक तकनीक (सीबीटी) जैसे, मेडीटेशन, सांस लेना, योगा, प्रेरणादायी साक्षात्कार और दूसरी सकारात्मक गतिविधियों का उपयोग करता है।

बेंगलूरु स्थित वाइसा को बनाने में मनोवैज्ञानिक, डिजाइनर एवं डेवलपरों की 15 सदस्यीय टीम और 5 लाख उपयोगकर्ताओं की एक वर्ष की मेहनत लगी है। इस दौरान उन्होंने समझा कि किस तरह एआई तकनीक युक्त रोबोट भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करता है। वाइसा के सह-संस्थापक रमाकान्त वेम्पती कहते हैं, 'भारत में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है और यहां की 1.2 अरब जनसंख्या के लिए 5,000 से भी कम प्रशिक्षित मनोचिकित्सक मौजूद हैं। यहां मांग-आपूर्ति के बीच भारी अंतर है।' विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वेम्पती कहते हैं कि विश्व में हर चार में से एक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मानसिक या मनोविकारों से प्रभावित होगा।

अपनी उच्च गुणवत्ता वाली एआई विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के साथ साथ गूगल वाइसा को ग्राहक अनुभव बेहतर करने, उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने और मंच से पैसे कमाने में भी मदद करती है। इस समय 30 से अधिक देश वाइसा का उपयोग कर रहे हैं।

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी गूगल नई कंपनियों को काफी मदद उपलब्ध करा रही है। गुरुग्राम स्थित पर्सेप्टिविटी डेटा सॉल्यूशंस बीमा और भुगतान संबंधी जानकारियों, फर्जी संदेश तथा गलत प्रबंधन के लिए एआई तकनीक पर आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया है। कंपनी मशीन लर्निंग की मदद से प्रत्येक दावे के लिए जोखिम स्कोर की गणना करती है। इससे गलत या दोहरे दावों की पहचान करने में मदद मिलती है और वास्तविक दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित होता है। कंपनी की कहना है कि इसने अभी तक 90 प्रतिशत सटीकता के साथ लाखों दावों का निपटान किया है और इससे फर्जी दावों की पहचान करने की लागत में 70 प्रतिशत तक की कमी आई है।

पर्सेप्टिविटी की शेरलॉक प्लेटफॉर्म 100 पेज के बीमा दावे को कुछ सेकंड के भीतर पढ़ सकता है और गलत या अस्पष्ट जानकारी की पहचान कर लेता है। यह गूगल के विजन एपीआई और टेंसरफ्लो मशीन लर्निंग क्षमता का उपयोग करता है और स्वास्थ्य बीमा संबंधी दावे को पूरी तरह स्वचलित बना रहा है।

पर्सेप्टिविटी के संस्थापक संदीप खुराना कहते हैं, 'आमतौर पर एक मरीज को बीमा दावा स्वीकृत होने और धनराशि मिलने के लिए लगभग 4-8 घंटे इंतजार करना पड़ता है, जो कई बार कुछ दिनों तक भी हो सकता है। हमारा एआई तंत्र इस समय को घटाकर कुछ मिनट कर देती है।'

गूगल एक्सीलरेटर के सलाहकार पर्सेप्टिविटि के मशीन लर्निंग मॉडल को बेहतर बनाने और इसका आकार कम करने में मदद कर रहे हैं। खुराना बताते हैं कि इन सलाहकारों में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के स्वामित्व वाली एआई तकनीक आधारित कंपनी डीपमाइंड की एक टीम भी शामिल है।

गूगल की सहायता प्राप्त एक अन्य कंपनी फायनेंसपीयर स्कूल की फीस संबंधी विशिष्ट समस्या का समाधान खोज रही है। मुंबई स्थित पीयर-टू-पीयर लेंडिंग कंपनी कर्ज लेने वालों को कर्जदाताओं से जोड़ती है और वह स्कूल की एक वर्ष की पूरी फीस का एक किश्त में भुगतान करके माता-पिता से 9-12 महीने की किश्त में राशि इकट्ठा करती है। कंपनी माता-पिता से किसी तरह का ब्याज नहीं लेती। फायनेंसपीयर एआई तकनीक आधारित एक सॉफ्टवेयर की मदद से जोखिम की पहचान करती है। इसी तरह, ऐप आधारित कर्ज देने वाला प्लेटफॉर्म स्मार्टकॉइन वित्तीय रूप से कमजोर लोगों के लिए काम कर रहा है। डेटा साइंस, एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके यह ग्राहकों को छोटे या मध्यम आकार के कर्ज देता है और भविष्य के लेनदेन के लिए क्रेडिट स्कोर विकसित करता है।

गूगल ने इस तरह की के कई उद्यमियों को सलाह एवं परामर्श देने के लिए अपने अमेरिका स्थित कार्यलय में बुलाया है। इनमें से ही एक निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी गीता मंजूनाथ हैं, जिन्होंने शुरुआती स्तर पर स्तन कैंसर की पहचान करने के लिए एआई तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया है।

फोटो-पीटीआई

# नए साल में लें निवेश का हाल ताकि बरकरार रहे आपका माल

संजय कुमार सिंह

साल 2020 आ गया है और हो सकता है कि सर्दियों के इस मौसम में आप अपनी पसंदीदा जगह की सैर कर रहे हों। यह भी हो सकता है कि सैर के खयालों को ताक पर रखकर आप अपने बरामदे में अंगीठी या अलाव के पास कंबल में पसरे हों और गर्म पकौड़ियों या अदरक वाली चाय का लुत्फ ले रहे हों। हाड़ कंपाती सर्दी में इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन इस सबके बीच आप एक जरूरी काम को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? वह जरूरी काम है अपनी वित्तीय स्थिति पर नजर डालना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से आपका निवेश एकदम दुरुस्त हो।

## पोर्टफोलियो में फेरबदल

जिन निवेशकों का निवेश पोर्टफोलियो श्रेणियों में बंटा होता है, वे जोखिम उठाने की अपनी क्षमता के मुताबिक एक खास प्रकार का संपत्ति आवंटन करते रहेंगे। उनका कुछ निवेश शेयरों में जाएगा, कुछ स्थिर आय योजनाओं में और कुछ सोने तथा अन्य निवेश श्रेणियों में होगा। आम तौर पर पिछले एक साल में किसी एक संपत्ति श्रेणी का प्रदर्शन बाकी सबसे अच्छा होने और दूसरी श्रेणी का प्रदर्शन कमतर होने के कारण निवेशकों का संपत्ति आवंटन गड़बड़ा जाता है। इसलिए उसे पटरी पर लाना जरूरी है। इसके लिए शानदार प्रदर्शन करने वाली संपत्ति श्रेणी में मुनाफावसूली करनी चाहिए और उसकी रकम कम प्रदर्शन वाली संपत्ति श्रेणियों में लगाकर पहले से निर्धारित संपत्ति आवंटन पर लौटना चाहिए।

निवेशकों को यह भी देखना चाहिए कि उप-संपत्ति श्रेणियों में उनका निवेश एकदम ठीक है या नहीं। उदाहरण के लिए इस साल लार्ज-कैप फंडों ने मिड और स्मॉल-कैप फंडों से बेहतर प्रदर्शन किया है। संभव है कि निवेशक के पोर्टफोलियो में लार्ज-कैप फंड कुछ ज्यादा ही हो गए हों। ऐसे में उसे संभलना जरूरी है।

पोर्टफोलियो में संतुलन को जोखिम कम करने के लिहाज से जरूरी बताते हुए आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड के सह-मुख्य निवेश अधिकारी महेश पाटिल कहते हैं, 'संपत्ति श्रेणियां हमेशा एक चक्र में चलती हैं। कोई भी संपत्ति श्रेणी एक निश्चित अवधि तक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसकी वजह से निवेशक के पोर्टफोलियो में उस संपत्ति श्रेणी की भरमार हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि मुनाफावसूली की जाए और संपत्ति को पहले से तय स्तर पर लाया जाए। ऐसा नहीं किया तो जब भी उस संपत्ति श्रेणी में गिरावट आएगी तो ढिलाई बरतने वाले निवेशक को नियमित बदलाव कर रहे निवेशक से अधिक चोट खानी पड़ेगी।' पाटिल उदाहरण भी देते हैं। 2013 से 2017 के बीच मिड और स्मॉल-कैप श्रेणियों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन 2018 की शुरुआत से ही उनमें गिरावट आने लगी। जिस निवेशक ने बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे मिड और स्मॉल-कैप में अपने आवंटन को दुरुस्त नहीं किया होगा, उसे 2018 से अच्छी खासी चपत खानी पड़ी होगी।

आजकल किसी वित्त वर्ष में शेयरों से होने वाला मुनाफा अगर 1 लाख रुपये के पार पहुंच जाता है तो उस पर 10 फीसदी की दर से दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर वसूला जाता है। निवेशक कर की रकम में कटौती के लिए कुछ तरीके आजमा सकते हैं। सबसे पहले, अगर पहले से तय किए गए स्तर के मुकाबले पोर्टफोलियो में अधिक फेरबदल नहीं हुआ है और निवेशक के पास फालतू रकम पड़ी है तो वह बेहतरीन प्रदर्शन वाली संपत्ति श्रेणी की बिकवाली के बजाय कमजोर प्रदर्शन वाली श्रेणी में और भी निवेश कर सकता है। दूसरा, 1 लाख रुपये की सीमा किसी एक व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए पति और पत्नी अपने-अपने पोर्टफोलियो से थोड़ी-थोड़ी बिकवाली कर इस बंदिश का फायदा उठा सकते हैं और परिवार का पोर्टफोलियो स्तर दुरुस्त रख सकते हैं। वित्तीय योजनाकार आगाह करते हैं कि निवेशकों को बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों से इतना प्रेम भी नहीं करना चाहिए कि उन्हें बेचने के लिए तैयार ही नहीं हों।

### लार्ज कैप फंड औसत रिटर्न

| श्रेणी | वाईटीडी | 3 साल | 5 साल |
|---|---|---|---|
| लार्ज कैप फंड्स | 12.02 | 12.92 | 8.83 |
| मल्टी कैप फंड्स | 8.99 | 11.64 | 8.72 |
| मिड कैप फंड्स | 1.6 | 8.25 | 8.16 |
| स्मॉल कैप फंड्स | -3.46 | 5.25 | 7.28 |

स्रोतः म्युचुअल फंड इंडिया डॉट कॉम

## लक्ष्य करीब हो तो इक्विटी छोड़ें

निवेशक की उम्र एक खास पड़ाव तक पहुंचने पर भी संपत्ति आवंटन में बदलाव किया जा सकता है। मान लीजिए कि निवेशक 55 साल का हो जाता है तो वह सेवानिवृत्ति तक अधिक सुरक्षित पोर्टफोलियो का सहारा लेना चाहता होगा। ऐसे निवेशक को इक्विटी संपत्ति बेचकर डेट में अधिक धन लगाना चाहिए। निवेशक किसी लक्ष्य के करीब पहुंचने पर भी अपने आवंटन में परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए कि उसकी संतान तीन साल बाद कॉलेज में जाएगी। उसे अपना निवेश इक्विटी से निकालकर डेट में लगाने का काम अभी से शुरू कर देना चाहिए ताकि शेयर बाजार में किसी तरह की गिरावट उसके लक्ष्य के आड़े नहीं आए। किसी भी संपत्ति से निकलने का समय और तरीका खासा अहम होता है। प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के मुख्य वित्तीय योजनाकार विशाल धवन कहते हैं, 'जिस तरह निवेशक फंड में निवेश की शुरुआत करते समय सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) का रास्ता चुनता है, उसी तरह उसे फंड से निकलने के लिए भी सिस्टेमैटिक विदड्रॉल प्लान या सिस्टेमैटिक ट्रांसफर प्लान की मदद लेनी चाहिए।' उनका मशविरा यह भी है कि निवेशकों को पूरी रकम एक ही बार में नहीं निकाल लेनी चाहिए क्योंकि अगले छह महीने में बाजार चढ़ा तो उन्हें माथा पीटना पड़ेगा। जिस तरह फंड में धीरे-धीरे प्रवेश किया जाता है, उसी तरह उससे धीरे-धीरे निकलना भी चाहिए। निकाली गई रकम अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म फंड (या निवेशक जोखिम लेने की कुव्वत रखे तो कम अवधि वाले फंड) में लगाई जा सकती है।

## कमजोर प्रदर्शन वालों को हटाएं

पोर्टफोलियो की सालाना समीक्षा के दौरान निवेशकों को कमजोर प्रदर्शन वाली संपत्तियों की पहचान कर उन्हें पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए। पाटिल कहते हैं, 'किसी भी फंड के प्रतिफल की तुलना उसके बेंचमार्क और उस श्रेणी के औसत से करें। चूंकि शेयर दीर्घकालिक संपत्तियों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए फैसला लेने से पहले यह जरूर देखें कि तीन साल या पांच साल की अवधि में फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है।'

चूंकि बेहतरीन से बेहतरीन फंड भी कमजोर प्रदर्शन कर सकता है, इसलिए निवेशक किसी भी फंड से निकलने का फैसला लेने से पहले 6 महीने से दो साल तक उसके प्रदर्शन पर बारीक नजर जरूर रखें। यदि फंड के प्रदर्शन में कमजोरी ऊंचे खर्च अनुपात (एक्सपेंस रेश्यो) के कारण है तो निवेशक को जल्द से जल्द पल्ला झाड़ लेना चाहिए। अगर फंड प्रबंधक का अब तक का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है तो निवेशक को उसे कुछ और वक्त देना चाहिए। यदि सक्रिय फंड मैनेजरों को बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो निवेशक को उनके फंडों के खर्च अनुपात की बारीक जांच करनी चाहिए।

## अवधि और क्रेडिट के जोखिम से बचें

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2019 में कई बार नीतिगत दरों में कटौती की। लेकिन दिसंबर में आखिरी मौद्रिक नीति समीक्षा में उसने अपनी मुट्ठी बांध ली क्योंकि खुदरा महंगाई का सूचकांक ऊपर चढ़ रहा था। खुदरा निवेशकों को स्थिर आय वाला अपना अधिकतर निवेश कम अवधि के डेट फंडों में रखना चाहिए ताकि अवधि से जुड़ा जोखिम कम से कम हो। धवन की सलाह है, 'निवेशकों को अपने डेट फंड पोर्टफोलियो की क्रेडिट गुणवत्ता खुद जांचनी चाहिए या किसी विशेषज्ञ के हाथ जंचवानी चाहिए।' निवेशक डायनमिक बॉन्ड फंडों में निवेश कम रखें तो बेहतर है।

## विदेश में निवेश समझदारी

जिन निवेशकों ने देसी शेयर बाजार में अच्छी खासी रकम लगा दी है, वे दूसरे देशों में निवेश पर भी विचार कर सकते हैं। पाटिल समझाते हैं, 'अनुभवी निवेशकों के लिए वैश्विक स्तर पर निवेश करना महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि इससे वे एक ही बाजार में निवेश के जोखिमों से बच जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों या फंडों में रकम लगाने से निवेशक मुद्रा के अवमूल्यन से होने वाले जोखिमों से भी बच जाते हैं।' भारत की मुद्रा यानी रुपया अक्सर डॉलर जैसी मुद्रा के मुकाबले गोता खाता रहता है यानी उसकी कीमत कम होती रहती है। अब कई परिवार ऐसे वित्तीय लक्ष्य तय करने लगे हैं, जिनमें डॉलर जैसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा खर्च करने की नौबत आती है, जैसे संतान को विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाना या विदेश यात्रा करना आदि। ऐसी सूरत में अंतरराष्ट्रीय फंडों में निवेश करना जरूरी हो जाता है। भारतीय निवेशक यदि वैश्विक स्तर पर निवेश करने की सोचें तो अमेरिका पर केंद्रित फंडों पर उन्हें सबसे पहले नजर डालनी चाहिए।

## स्वास्थ्य बीमा भी देखें

इस मोर्चे पर सबसे पहले यह देखें कि आपके पास पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा है या नहीं। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े खर्च तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और सुविधाएं महंगी होती जा रही हैं। इसीलिए बीमा पर नजर डालना जरूरी है। आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस के मुख्य कार्य अधिकारी मयंक बथवाल का कहना है, 'सुनिश्चित कीजिए कि आपका पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा हो ताकि परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने पर आपको कर्ज वगैरह नहीं लेना पड़े।'

बथ्वाल की सलाह यह है कि बुनियादी बीमा (सामान्य बीमा पॉलिसी, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर हुए सभी खर्च की रकम वापस मिल जाती है) के साथ ही गंभीर बीमारियों का बीमा भी हो ताकि गंभीर रोग होने पर उसका इलाज आराम से हो सके और परिवार को किसी तरह की वित्तीय दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़े। चार लोगों के परिवार के लिए फ्लोटर कवर में कम से कम 10-15 लाख रुपये का बीमा होना चाहिए। यदि माता-पिता को भी उसी बीमा पॉलिसी में शामिल किया जाता है तो यह रकम बढ़ाकर 20-25 लाख रुपये की जा सकती है। ध्यान रखिए कि आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कम से कम बीमारियों को बाहर रखा गया हो। आजकल कई बीमा पॉलिसियों में ओपीडी (बहिरंग रोगी विभाग) और वेलनेस के लाभ (इनमें स्वस्थ रहने यानी दावा नहीं करने पर ग्राहक को प्रीमियम में छूट दी जाती है) दिए जाने लगे हैं। कई बीमा कंपनियां स्वास्थ्य कोच भी मुहैया कराती हैं, जो ग्राहकों को मधुमेह, दमा, कलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों से निपटने में मदद करते हैं। यदि आपके मौजूदा स्वास्थ्य बीमा में ये फायदे नहीं मिल रहे हैं तो आपको दूसरी बीमा कंपनी से पॉलिसी लेने की कोशिश करनी चाहिए।

## जीवन बीमा भी टटोलें

आपकी जीवन बीमा की जरूरत पिछले एक साल में बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी। जब कोई व्यक्ति नया कर्ज लेता है या ज्यादा बोझ भरे लक्ष्य तय कर लेता है (जैसे बच्चों को देश के बजाय विदेश में पढ़ाना) तो उसके लिए जीवन बीमा की जरूरत बढ़ जाती है। जब व्यक्ति कर्ज चुका देता है या उसे विरासत में संपत्ति मिल जाती है तो उसकी जीवन बीमा की जरूरत कम हो जाती है।

यदि आपकी जरूरत बढ़ गई है तो आपको नई पॉलिसी लेनी पड़ सकती है। अगर जरूरत कम हो गई है तो आपको कोई पॉलिसी बंद भी करनी पड़ सकती है। आप टर्म बीमा पर भी ध्यान दे सकते हैं क्योंकि इसका खर्च लगातार कम हो रहा है। इसे खरीदें तो सभी बीमा कंपनियों के प्रीमियम की तुलना जरूर कर लें।

# नौकरी की शुरुआत में ये नुस्खे बांध लें गांठ तो रहेंगे आपके ठाठ

## खर्च में कमी बेशक नहीं करें मगर बचत करना जरूर शुरू कर दें

सर्वजित के सेन

### सबसे पहले बजट बनाएं फिर करें निवेश

- जब बचत आपकी आदत बन जाती है तो लघु बचत और दूसरी वित्तीय योजनाओं में निवेश शुरू कर दें
- शुरुआत के लिए म्युचुअल फंड का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या इक्विटी फंड में एसआईपी बेहतर रहेगा
- इनसे नियमित निवेश की आदत पड़ती है और अच्छी संपत्ति भी जमा हो जाती है
- जब आप कुछ महीने तक बजट तैयार करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमाई कितनी है और आप किस तरह खर्च कर रहे हैं
- अगर आपके माता-पिता आप पर निर्भर नहीं हैं तो नौकरी के शुरुआती सालों में जीवन बीमा आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा बेहद जरूरी है

**पहली** नौकरी का जश्न मनाने की कई वजह होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह होती है कि रुपये-पैसे के मामले में आप आजाद हो जाते हैं। नए कपड़े खरीदने हों या नया-नवेला गैजेट, आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। लेकिन कई बार इसकी वजह से आप बेवजह खर्च भी कर जाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि माता-पिता पहली नौकरी लगते ही अपने बच्चों को बचत के सबक देना शुरू कर दें।

उनसे पूछें कि वे क्या खरीदना चाहते हैं? नया-नवेला मोबाइल फोन या कार या घर? जो भी खरीदना चाहें, उसके लिए बचत और निवेश शुरू कर दें। सबसे पहले देखें कि उसके लिए कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी और उसी हिसाब से बचत शुरू कर दें। लैडर7 फाइनैंशियल एडवाइजर्स के संस्थापक सुरेश सदगोपन कहते हैं, 'अलग-अलग खर्चों या अल्पावधि और दीर्घावधि लक्ष्यों के लिए कितनी रकमी चाहिए। यह देखिए और उसी हिसाब से संपत्ति आवंटन शुरू कर दीजिए।'

सबसे पहले बचत करें और उसके बाद निवेश शुरू करें। टीबीएनजी कैपिटल एडवाजर्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्य अधिकारी तरुण बिरानी सलाह देते हैं, 'आप कितना भी कमाते हों, उसका एक हिस्सा जरूर बचाएं।' जब बचत आपकी आदत बन जाती है तो लघु बचत और दूसरी वित्तीय योजनाओं में निवेश शुरू कर दें। प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के मुख्य कार्य अधिकारी विशाल धवन कहते हैं, 'जैसे ही वेतन हाथ आए, 20-30 फीसदी हिस्सा निवेश कर दें। उसके बाद ही खर्च करना शुरू करें।'

निवेश के इतने ठिकाने मौजूद हैं कि युवाओं के लिए सही ठिकाना चुनना भी कम मुश्किल काम नहीं है। मगर शुरुआत के लिए म्युचुअल फंड का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) या इक्विटी फंड में एसआईपी बेहतर रहेगा क्योंकि इनसे नियमित निवेश की आदत पड़ती है और अच्छी संपत्ति भी जमा हो जाती है। बिरानी कहते हैं, 'नियमित एसआईपी से आपके भीतर वित्तीय अनुशासन आएगा, जो लंबी अवधि की वित्तीय योजना में सबसे अहम होता है।'

## बजट तैयार करें

बिरानी का मशविरा है, 'बजट बनाए बगैर रकम का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। व्यस्तता भरे जीवन में तो और भी मुश्किल।' जब आप कुछ महीने तक बजट तैयार करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमाई कितनी है और आप किस तरह खर्च कर रहे हैं। इस तरीके को बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल खर्च में से गैर जरूरी खर्च कौन से हैं। धवन कहते हैं, 'तयशुदा या जरूरी खर्च और गैर जरूरी खर्च को अलग कर लें। गैर जरूरी खर्चों पर उसी वक्त लगाम लगा लें वरना उन्हें जरूरत में बदलते देर नहीं लगेगी।'

## क्रेडिट कार्ड में सावधानी

क्रेडिट कार्ड भी किसी को आसानी से कर्ज के जाल में फंसा सकते हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सदगोपन समझाते हैं, 'कुछ भी खरीदना है तो पहले उसके लिए रकम बचाएं और बाद में खरीदें। कर्ज लेकर या क्रेडिट कार्ड की मदद से खरीदने के बजाय यह बेहतर तरीका है। कार्ड का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के लिए ही करना चाहिए। इस मामले में डेबिट कार्ड बेहतर होते हैं। पेटीएम, फोन पे जैसे कई वॉलेट भी होते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना आसान है और जिनसे आप पर कर्ज भी नहीं चढ़ता।'

## आपात स्थितियों के लिए रकम

आप कितनी भी बेहतर योजना बना लें, सब कुछ उसी के हिसाब से होना जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे अप्रत्याशित खर्च या आपात स्थितियां आ जाती हैं, जिनके बारे में आपने कोई योजना ही नहीं बनाई होती है। बिरानी कहते हैं, 'ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अलग से रकम रखना ही समझदारी है। इससे अप्रत्याशित वित्तीय परिस्थितियों से निपटने के लिए हम तैयार रहते हैं और आपात स्थिति आने पर दिमागी तनाव से भी बच जाते हैं।'

## स्वास्थ्य बीमा लें

अगर आपके माता-पिता आप पर निर्भर नहीं हैं तो नौकरी के शुरुआती सालों में जीवन बीमा आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा बेहद जरूरी है। जीवन बीमा बाद में ले लीजिए। सदगोपन कहते हैं, 'पहली नौकरी लगते ही सबसे पहले करीब 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए।' इससे सुनिश्चित होगा कि अचानक अस्पताल में भर्ती होने पर युवा व्यक्ति को अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़े और उसकी वित्तीय योजना चौपट नहीं हो जाए। हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको समूह स्वास्थ्य बीमा दे रही हो। फिर भी अलग से स्वास्थ्य बीमा लीजिए ताकि कंपनी छोड़ने पर आपको कोई परेशानी नहीं हो।

# अमेरिका-ईरान में बढ़ी तल्खी

## डॉनल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिका में लड़ने का 'साहस' नहीं है

**रॉयटर्स**

ईरान ने रविवार को डॉनल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए उन्हें 'सूट बूट वाला आतंकवादी' बताया। ईरान की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति की इस धमकी के बाद आई है कि अगर ईरान ने अपने सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए अमेरिकियों या अमेरिकी संपत्तियों पर हमला किया तो उसकी चिह्नित 52 जगहों को निशाना बनाया जाएगा।

दोनों देश एक-दूसरे को युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ओमान ने दोनों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका ने शुक्रवार को बगदाद हवाई अड्डे पर ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के काफिले पर ड्रोन से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। इससे दोनों देशों के बीच दुश्मनी चरम पर पहुंच गई है और पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध की आशंका पैदा हो गई है।

ईरान के सूचना एवं दूरसंचार मंत्री मोहम्मद जावेद अजारी-जहरोमी ने ट्वीट किया, 'आईएसआईएस, हिटलर, चंगेज खान! वे सभी संस्कृतियों से नफरत करते थे। ट्रंप सूट-बूट में एक आतंकवादी हैं। वह बहुत जल्द इतिहास सीख जाएंगे कि कोई भी महान ईरानी देश एवं संस्कृति को हरा नहीं सकता।'

ट्रंप ने कहा कि ईरान की 52 जगह अमेरिका के निशाने पर हैं, जिनमें से कुछ ईरान और उसकी संस्कृति के लिए अहम हैं। इन लक्ष्यों और खुद ईरान पर त्वरित और तगड़ा हमला होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये 52 लक्ष्य ईरान में 52 अमेरिकियों को बंधक बनाए जाने की घटना का प्रतीक हैं, जिन्हें 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के दौरान अमेरिकी दूतावास से पकड़ा गया था। ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर देश के सेना प्रमुख मेजर जनरल अब्दुलरहीम मौसावी ने कहा कि अमेरिका में ईरान से लड़ाई का साहस नहीं है।

यूरोपीय संघ (ईयू) ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव घटाने की अपील करते हुए रविवार को कहा कि ईरान के विदेश मंत्री को ब्रसेल्स आमंत्रित किया गया है।

इराक में बहुत से लोगों ने इराकी जमीं पर अमेरिका द्वारा सुलेमानी और इराक के गैर सैनिक संगठन के नेता अबु महदी अल मुहांदिस की हत्या और उनके देश को एक और युद्ध में धकेलने के लिए गुस्सा जाहिर किया। इराक के जनप्रतिनिधियों ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर यह प्रस्ताव पारित किया कि सरकार अमेरिका को इराक से अपनी सेनाएं हटाने के लिए कहे। इस बीच ईरान के साथ हुए बहुपक्षीय समझौते से अमेरिका के पीछे हटने और उस पर फिर से प्रतिबंध लगाने के जवाब में ईरान अब परमाणु समझौते से पीछे हटने से संबंधित अपने पांचवें कदम को रविवार रात तक अंतिम रूप देगा।

ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरआईबी के मुताबिक सुलेमानी के पार्थिव शरीर को ईरान लाए जाने के बाद उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए अहवाज और मशद में हजारों लोग उमड़े और सबने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। यहां लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ईरान के लोग सुलेमानी को 1980-88 के ईरान-इराक युद्ध और ईरान के पश्चिम एशिया अभियान की अगुआई करने वाले नायक के तौर पर देखते हैं।

ईरान के अहवाज शहर में काले कपड़े पहनकर हजारों ने मनाया ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के लिए मातम

- यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ओमान ने दोनों देशों से शांति की अपील की
- विदेशी मंत्री जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से की बातचीत
- ईरान ने ट्रंप के खिलाफ विरोध जताने के लिए स्विस राजदूत को बुलाया
- यूरोपीय संघ ने ईरान के विदेश मंत्री को ब्रसेल्स आमंत्रित किया

### भारत ने जताई चिंता

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को मद्देनजर रखते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ के साथ साथ बातचीत की। जयशंकर ने कहा कि भारत क्षेत्र में तनाव के स्तर को लेकर अत्यंत चिंतित है। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रमों ने बहुत गंभीर मोड़ ले लिया है। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, 'ईरान के विदेश मंत्री जे जरीफ से बात की। घटनाक्रम ने गंभीर मोड़ ले लिया है। भारत इस बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है। हमने संपर्क में रहने की सहमति जताई है।'

ईरान ने किसी अमेरिकी या अमेरिकी संपत्ति पर हमला किया तो हम 52 ईरानी स्थलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिका कोई खतरा नहीं चाहता

**डॉनल्ड ट्रंप**
राष्ट्रपति, अमेरिका

मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि अमेरिका ने 52 जगहों पर हमला करने की जो धमकी दी है वह सही है क्योंकि उनमें 'लड़ाई शुरू करने का साहस' ही नहीं है

**मेजर जनरल अब्दुल रहमान मौसावी**
सेना प्रमुख, ईरान

# तेल कीमतों में तेजी अस्थायी

**शाइन जैकब**

**अमेरिका** और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल के कारोबार में बाधा पड़ने से खतरा बढ़ता जा रहा है। देश की तेल-मार्केटिंग कंपनियों को लगता है कि यह अस्थायी दौर है और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लंबी अवधि तक बरकरार नहीं रह सकती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष एम के सुराणा कहते हैं, 'सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के संयंत्र पर पिछले साल हमला हो गया था लेकिन सऊदी अरब ने बेहद परिपक्व प्रतिक्रिया देते हुए तत्काल ही सारी चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश की थी।'

सऊदी अरामको के शेयर 1.7 फीसदी गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर चले गए। पिछले महीने ही सऊदी अरामको का आईपीओ रिकॉर्ड स्तर पर सूचीबद्ध हुआ था। अरामको के शेयर गिरकर 34.55 रियाल प्रति शेयर हो गए जो पिछले महीने के कारोबार की शुरुआत के बाद सबसे निचला स्तर है।

अमेरिका ने बगदाद में हवाई हमला किया जिसमें ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए जिसके बाद शुक्रवार को तेल की कीमतों में करीब 3 डॉलर प्रति बैरल की उछाल आई। इसके अलावा सोना और सुरक्षित बॉन्ड में भी बढ़त दिखी। इसके अलावा दोनों ही देशों में जंग छिड़ने की आशंका को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं क्योंकि ईरान ने बदला देने की बात कही है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) में ईराक दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और पिछले महीने तक यह हर रोज 46.5 लाख बैरल का उत्पादन करता था। इसके पड़ोसी देश, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान मिलकर प्रतिदिन करीब 1.5 करोड़ बैरल का उत्पादन करते हैं। सुराणा कहते हैं कि आपूर्ति के लिहाज से भारत के लिए चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं है। उनका कहना है, 'इस लिहाज से तेल आपूर्ति मांग की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन तनाव बढ़ने की चिंता जरूर बढ़ेगी। सारी बातें ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर होगा। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ही तात्कालिक चिंता का कारण हो सकता है।'

केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें आने वाले दिनों में 70 डॉलर प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमत में किसी भी तरह की बढ़ोतरी देश के लिए चिंता की बात हो सकती है क्योंकि भारत ने अपनी तेल जरूरतों के 80 फीसदी से अधिक का आयात किया है।

उद्योग के दूसरे विशेषज्ञ भी सुराणा की बातों से इत्तफाक रखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में पूर्व निदेशक एस के जोशी कहते हैं, 'कच्चे तेल की कीमतों पर असर अस्थायी ही होगा। हालांकि ईरान इन हमलों का जवाब देने की धमकी दे रहा है और लंबी अवधि का असर ईरान की प्रतिक्रिया पर ही निर्भर करेगा।'

मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत ने कच्चे तेल का रोजाना 45 लाख बैरल (अप्रैल-नवंबर) आयात किया है और आयात पर इसकी निर्भरता खपत पर निर्भर होगी जो एक साल पहले की समान अवधि में 83.3 फीसदी की तुलना में बढ़कर 84.5 फीसदी हो गई है। सुराणा कहते हैं, 'पहले यह स्थिति थी कि एक ही समूह कीमतों पर नियंत्रण कर सकता था लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। तार्किक रूप से पश्चिम एशिया, रूस और अमेरिका तीन जगहें हैं। ये न तो छोटे और न बड़े हैं बल्कि इनकी समान ही हैं। हालांकि किसी एक हालात में इन तीनों खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया समान होगी। हम कह सकते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया समान रूप से विरोधाभासी भी हो सकती है।' उनका कहना है कि किसी भी हालात में किसी एक जगह की आपूर्ति बाधित होने से पहले के मुकाबले असर कम ही दिखेगा। सामान्यतौर पर ऐसे भूराजनैतिक तनाव का भारत के व्यापार घाटे, देश के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और विनिमय दर पर असर होगा। सुराणा कहते हैं, 'आपको विनिमय दर पर गौर करने की जरूरत होगी। ऐसे स्थिति में कभी-कभी मुद्रा भी चिंता की वजह हो सकती है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि लोगों की आशंका के मुकाबले चीजें अच्छी ही होती हैं।'

**कच्चे तेल में झटका** ब्रेंट क्रूड (डॉलर प्रति बैरल)

**देश का तेल आयात** (डॉलर प्रति बैरल)

| साल | मूल्य (डॉलर अरब) |
|---|---|
| 2017-18 | 87.8 (220.4) |
| 2018-19 | 111.9 (226.5) |

कोष्ठक में आयात कारोबार के आंकड़े (एमटीए)

**84.7%** कच्चे तेल पर भारत की आयात निर्भरता

सऊदी अरामको के शेयर 1.7 फीसदी गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर चले गए। पिछले महीने ही अरामको का आईपीओ रिकॉर्ड स्तर पर सूचीबद्ध हुआ था।

# ईरान-अमेरिकी तनाव से चाय निर्यातकों की चिंता

**अभिषेक रक्षित**

**ईरान** पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद पश्चिम एशिया के घटनाक्रम में अचानक बदलाव दिखने लगा है जिसकी वजह से चाय निर्यातकों और चाय बगान कंपनियों की चिंता बढ़ी है। दरअसल ईरान भारतीय चाय के लिए मुख्य निर्यातक देश हैं जिसने रूस और दूसरे प्रमुख परंपरागत बाजारों को पीछे छोड़ दिया है। अब चिंताजनक बात यह है कि ईरान में तनाव बढ़ने की स्थिति में इस देश को ज्यादा व्यापार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा जिससे चाय के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। ईरान के एक निर्यातक का कहना है, 'व्यापार के लिए स्थिरता बेहद अहम है और अमेरिका बार-बार हवाई हमलों और ईरान बदला लेने की बात कर रहा है ऐसे में यहां चिंताजनक स्थिति है।'

देश के चाय का निर्यात ईरान में होता है और जनवरी-नवंबर 2019 के दौरान साल में पहली बार चाय निर्यात ने 5 करोड़ किलोग्राम का आंकड़ा पार कर किया और इसकी कीमत उच्च स्तर पर कीमत 280 रुपये प्रतिकिलो रही। इसकी वजह से ईरान सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया। कारोबार के लिहाज से भी देखें तो ईरान का निर्यात एक साल पहले की तुलना में दोगुनी होकर 1,415 करोड़ रुपये हो गई है।

ईरान को निर्यात करने वाले एक चाय कारोबारी कहते हैं, 'हालात जटिल है। ईरान देश का प्रमुख परंपरागत चाय आयातक है। अगर ईरान का निर्यात प्रभावित होता है तब चाय बगान कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल होगी।'

हालांकि भारतीय चाय बोर्ड आशावादी है। इसके उपाध्यक्ष ए के रे कहते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान का चाबहार बंदरगाह (दोनों सरकार इस पर काम कर रही हैं और समझौते के मुताबिक यह देश के निर्यात मार्गों से जुड़ा होगा) के बाहर रहने और भारत तथा ईरान के बीच रुपया-रियाल समझौते की वजह से अमेरिका-ईरान के बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति से भारत के कारोबारी हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मिसाल के तौर पर जब अमेरिका ने पिछले साल ईरान पर प्रतिबंध लगाया था तब देश के चाय निर्यात में तेजी आई थी जबकि श्रीलंका की अच्छी-खासी बाजार हिस्सेदारी खत्म हो गई थी। हालांकि एक अन्य निर्यातक कहते हैं कि अगर अमेरिका चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर नहीं रखता तब क्या होगा। भारतीय चाय संगठन के अध्यक्ष विवेक गोयनका कहते हैं, 'इस क्षेत्र की स्थिरता किस तरह प्रभावित होगी यह उस बात पर निर्भर करेगा और भारत का इसमें कैसा रूख रहेगा। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि ईरान के साथ कारोबार बरकरार रहेगा।'

**भारत से चाय का निर्यात**

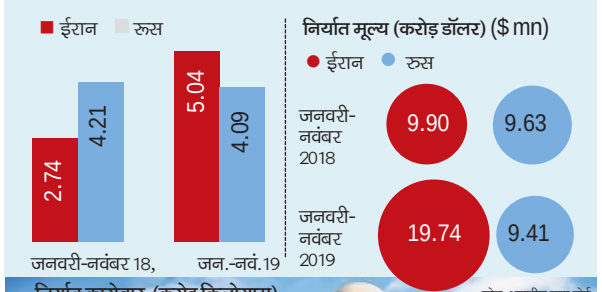


निर्यात कारोबार (करोड़ किलोग्राम)

स्रोतः भारतीय चाय बोर्ड

### प्रभावित होगा भारत का निर्यातः फियो

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ने की स्थिति में फारस की खाड़ी के देशों में भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि निर्यातकों ने अभी ईरान में निर्यात को लेकर कोई चिंता नहीं जताई है। उन्होंने कहा, 'यदि तनाव जारी रहता है तो इससे ईरान को भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है।' भारत के लिए ईरान प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में एक हैं। ईरान द्वारा भारत को कच्चे तेल, खाद और रसायन का निर्यात किया जाता है। वहीं वह भारत से मोटे अनाज, चाय, कॉफी, बासमती चावल, मसालों का आयात करता है। वित्त वर्ष 2018-19 में ईरान को भारत का निर्यात 24,920 करोड़ रुपये का रहा था। वहीं इस दौरान आयात 13.52 अरब डॉलर या 96,000 करोड़ रुपये रहा। व्यापार असंतुलन की प्रमुख वजह भारत द्वारा ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करना है। अभी दोनों देश आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय तरजीही व्यापार करार (पीटीए) को लेकर वार्ताएं कर रहे हैं।

# बासमती चावल निर्यात पर असर

**वीरेंद्र सिंह रावत और टी ई नरसिम्हन**

**अमेरिका** और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से भारत के बासमती चावल निर्यात पर असर पड़ सकता है जिससे निर्यातकों की चिंता बढ़ी है। ईरान को होने वाला बासमती निर्यात वर्ष 2018-19 में 33 फीसदी या करीब 1.56 अरब डॉलर रहा। लेकिन बासमती निर्यात को पिछले साल अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से ही अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा घटनाक्रम से हालात बिगड़े और अक्टूबर तक निर्यात 57 करोड़ डॉलर रहा जिसका निर्यात में 26 फीसदी योगदान है।

उद्योग के सूत्रों का कहना है कि ईरान की तरफ से कुल 1200 करोड़ रुपये की देनदारी में से 800 करोड़ रुपये का भुगतान अटका है। ऐसे में निर्यातकों को इस बात का डर है कि ताजा निर्यात से भुगतान में दिक्कत आएगी। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संगठन के कार्यकारी निदेशक विनोद कौल कहते हैं, 'अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से व्यापार पर असर पड़ेगा जिनमें भारत से होने वाला बासमती निर्यात भी शामिल है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो सुरक्षा चिंताओं की वजह से माल ढुलाई पर असर पड़ेगा।' पिछले कुछ महीने से ईरान में होने वाले बासमती निर्यात पर असर पड़ा है।

### हल्दी निर्यात बाधित

ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों से हल्दी निर्यात पर भी असर पड़ा है। ईरान साबुत हल्दी का सबसे बड़ा खरीदार है। निर्यातकों का कहना है कि मई से ही ईरान में हल्दी का माल नहीं जा रहा है। खाद्य एवं दवा उद्योग के अलावा चमड़ा उद्योग से भी मांग बढ़ने से हल्दी निर्यात में तेजी आई है। हल्दी के एक प्रमुख निर्यातक दीपकमल निर्यात के निदेशक दीपक मजूमदार कहते हैं कि अमेरिका ने डॉलर पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे ईरान में होने वाले हल्दी निर्यात पर असर पड़ा और आयातकों को केवल चुनिंदा बैंकों की मदद से ही भुगतान करना पड़ रहा है जिससे भुगतान प्रभावित हो रहा है।

# दुनिया भर के बाजार में छाए आशंका के बादल

पृष्ठ 1 का शेष

**पिछले साल** में विदेशी निवेशकों ने 1.01 लाख करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के शेयर खरीदे हैं और यह आंकड़ा घरेलू संस्थागत निवेशकों की लिवाली से 2.4 गुना अधिक है। शुक्रवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 0.61 प्रतिशत गिरावट के साथ 71.80 पर बंद हुआ।

शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि विदेशी निवेशक भारत और तेजी से उभरते बाजारों में अपने निवेश को लेकर सशंकित कर सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि आगामी बजट में भी अमेरिका-ईरान के बीच तनाव से वृहद आर्थिक हालता के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का ध्यान रखना होगा। हालांकि अभी तक एशियाई बाजारों में कोई विशेष घबराहट नहीं दिखी है, लेकिन विशेषज्ञों की नजर में आने वाले समय में अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को शांघाई कंपोजिट थोड़ा ही कमजोर रहा। कोस्टपी इंडेक्स और ताइवान टाइएक्स भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। भारत में निफ्टी और सेंसेक्स में 0.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट दिखी।

विशेषज्ञ कहते हैं कि मौजूदा तनाव से बॉन्ड बाजार अस्थिर होगा। एसबीआई डीएफएचआई में उपाध्यक्ष (ट्रेजरी) हेमंत दोषी कहते हैं, 'अमेरिका और ईरान के बीच हालात काबू में नहीं रहे और तेल लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहा तो बॉन्ड कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।' तेल आयात पर भारत की निर्भरता के मद्देनजर उसके लिए जोखिम अधिक है। गोयनका ने कहा, 'तेल में 10 डॉलर बढ़ोतरी से महीने का तेल आयात करीब 1.5 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है, जबकि खुदरा महंगाई 0.4 प्रतिशत तक उछल सकती है। तेल कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल पार पहुंचने से निवेशकों में बेचैनी बढ़ जाएगी।'